भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 27 आषाढ़, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 77, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी: शेख हसीना

एजेंसी, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि

वह दिसंबर में भारत से बांग्लादेश देश लौटेंगी व कोर्ट में सरेंडर करेंगी। उन्होंने कहा कि उनके साथ अवामी लीग के कई सीनियर नेता भी बांग्लादेश लौटकर आत्मसमर्पण करेंगे। हसीना ने कहा कि अवामी लीग के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उनके मुताबिक, लगभग सभी बड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कई लोग छिपकर रहने को मजबूर हैं। हालांकि, उन्होंने वापसी की सटीक तारीख नहीं बताई।

पहले वंदे मातरम फिर जन-गण-मन होगा

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान जन-गण-मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को नए निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नियमों में पहले से तय है कि किन कार्यक्रमों में दोनों को गाना या बजाना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि अगर दोनों की एक साथ प्रस्तुति होती है तो पहले वंदे और फिर जन-गण-मन होगा। जिन राज्यों में राज्य गीत भी होता है, वहां भी तय क्रम का पालन करना होगा। 9 जुलाई को सभी राज्यों और मंत्रालयों को पत्र भेजा गया, जिसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई है। सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मूल शब्द, सही उच्चारण और तय प्रस्तुति का पूरी तरह पालन हो। दोनों का आधिकारिक पाठ और सही उच्चारण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, ताकि कोई गलती न हो।

राम मंदिर दान घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 को करेगा सुनवाई

एजेंसी, नई दिल्ली। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान की कथित चोरी की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहन की पीठ सुनवाई करेगी। याचिका दो वकीलों अजय कुमार राय और विनेश कुमार राय ने दायर की है। याचिका में केंद्र सरकार, यूपी सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था स्थापित करें, क्योंकि इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं।

स्पेन में जंगल की आग से 12 की मौत, 19 लापता

एजेंसी, मैड्रिड। दक्षिणी स्पेन के अल्मेरिया प्रांत में लगी जंगल की आग में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग लापता हैं। कई पीड़ितों के शव जली हुई गाड़ियों के अंदर मिले हैं। देश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच आग तेजी से फैली, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। फ्रांस के समाचार टेलीविजन नेटवर्क फ्रांस 24 तथा तुर्किये की सरकारी संवाद समिति अनादोलू ने क्षेत्रीय सरकार के हवाले से बताया कि अल्मेरिया प्रांत के बेदार और लॉस गैलार्डोस इलाके में फैली आग के बाद राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है।

ईरान को नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार : इसराइल

खामेनेई की शोकसभा में जा सकते हैं नए सुप्रीम लीडर मुजतबा

एजेंसी, वॉशिंगटन डीसी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल किसी भी हाल में ईरान

को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है और जरूरत पड़ने पर फिर हमला कर सकते हैं।

इसराइली वायुसेना के एक समारोह में नेतन्याहू ने कहा, 'अगर हमने कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना चुका होता।' साथ ही, इसराइली मीडिया में दावा किया गया है कि इसराइल ईरान पर फिर हमले के लिए तैयार है, लेकिन अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आ सकते हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, वे कोम शहर की हजरत मासूमेह दरगाह में अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शोकसभा की अगुवाई करेंगे। इसराइली एयर फोर्स के एक कार्यक्रम में नेतन्याहू ने कहा कि अगर इसराइल ने कार्रवाई नहीं की होती, तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना चुका होता।

होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही बढ़ने से तेल की मांग में सुधार

होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य होने के साथ दुनिया में कच्चे तेल की मांग फिर बढ़ने लगी है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2027 में दुनिया में तेल की मांग रोजाना करीब 20 लाख बैरल बढ़ेगी। हालांकि, 2026 में तेल की मांग अब भी रोजाना करीब 10 लाख बैरल घटने का अनुमान है, लेकिन साल की दूसरी छमाही में गिरावट की रफ्तार कम होगी और आखिरी तिमाही में मांग फिर बढ़ने लगेगी। आईईए के मुताबिक, जून में दुनिया भर में तेल का भंडार 2.1 करोड़ बैरल बढ़ा। यह लगातार चार महीने की गिरावट के बाद पहली बढ़ोतरी है। इस तेल का बड़ा हिस्सा जमीन पर भंडारण की बजाय जहाजों में ही रखा गया।

हमला हुआ तो इसराइल नहीं बचेगा : ईरान

ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके अहम ढांचे पर हमला हुआ, तो उसका जवाब दिया जाएगा और इसराइल इससे नहीं बचेगा। सरकारी मीडिया के मुताबिक, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बाघेर जोलगदर ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी।

महादेव बेटिंग ऐप मामला: ईडी ने विकास गर्ग की 940.77 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप और स्काई एक्सचेंज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 940.77 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। ये संपत्तियां कारोबारी विकास गर्ग, उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की बताई जा रही हैं। ईडी के अनुसार, अटैच की गई संपत्तियों में महंगी आवासीय संपत्तियां, जमीन, कंपनियों के शेयर और अन्य वित्तीय निवेश शामिल हैं। एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से अर्जित धन से जुड़ी हैं। मामले की जांच छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। इसके अलावा कई राज्यों में दर्ज मामलों को भी जांच में शामिल किया गया है। इनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे आरोप लगाए गए हैं। ईडी का कहना है कि महादेव ऑनलाइन बुक और स्काई एक्सचेंज का नेटवर्क विदेश से संचालित हो रहा था और फ्रेंचाइजी आधारित पैनल सिस्टम के जरिए देशभर में फैलाया गया। एजेंसी के मुताबिक यह देश के बड़े अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क में से एक है।

बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच भारत के चेपॉक स्टेडियम में 12 दिसंबर को

◆ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से मोदी ने की घोषणा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जताई खुशी

एजेंसी, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया की टी-20 लीग बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच भारत में खेला जाएगा। मुकाबला चैन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 12 दिसंबर को होगा।

यह पहली बार होगा, जब किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मैच भारत में होगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। मोदी अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भी मौजूद रहे। बीबीएल के 15 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा, जब लीग का कोई मैच ऑस्ट्रेलिया के बाहर आयोजित होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बाजार भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने और लीग को वैश्विक पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम मान रहा है।

मोदी अपनी यात्रा के तीसरे चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे, एयरपोर्ट पर लक्सन ने किया स्वागत

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के तीसरे चरण में शुक्रवार को न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने उनके अगले गंतव्य पर पहुंचने की जानकारी एक्स पर साझा की। उन्होंने बताया, 'कुछ देर पहले ऑकलैंड पहुंच गया हूं। हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए प्रधानमंत्री लक्सन का आभारी हूं। यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि चार दशकों में यह पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड का दौरा कर रहा है।

अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 3 माह जेल

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने ये आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की थी, लेकिन प्रयास असफल रहा। 16 फरवरी को कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। 5 फरवरी को उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव को कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए तुरंत सरेंडर करने को कहा था, जिसके बाद राजपाल यादव ने जेल में सरेंडर कर दिया था। राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। हालांकि, जून 2024 में उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजपाल यादव आदतन अपराधी नहीं हैं, इसलिए उनकी सजा निलंबित की जाती है।

ई20 से पांच फीसदी घट सकती है माइलेज, लेकिन स्वच्छ दहन जैसे लाभ अधिक : पेट्रोलियम मंत्रालय

◆ कहा-न इंजन खराब होगा न पुरानी गाड़ियां होंगी बेकार

एजेंसी, नई दिल्ली। ई20 पेट्रोल को लेकर देशभर में हंगामा बरपा है। ई20 यानी 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सवालों के घेरे में है। इसे लेकर उठ रहे सवालों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही अफवाहों के बीच केंद्र सरकार का जवाब आया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) के इस्तेमाल से कुछ वाहनों में ईंधन दक्षता (माइलेज) तीन से 5 फीसदी तक कम हो सकती है, लेकिन इसके बदले मिलने वाली ऊर्जा सुरक्षा, कम कार्बन उत्सर्जन और बेहतर इंजन प्रदर्शन जैसे लाभ कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। मंत्रालय के अनुसार इसके अलावा ऑक्टेन रेटिंग, बेहतर एंटी-नॉक क्षमता, तेज दहन, बेहतर पिकअप आदि जैसे लाभ भी इसमें शामिल हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम की आलोचनाओं का जवाब देने के लिए जारी प्रश्नोत्तर दस्तावेज में बताया कि ई20, ई10 या शुद्ध पेट्रोल की तुलना में "अधिक स्वच्छ, बेहतर गुणवत्ता वाला और अधिक दक्ष ईंधन है।"

इसे वर्षों तक वैज्ञानिक परीक्षण, वाहन विनिर्माताओं के साथ परामर्श और घरेलू इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बाद ही लागू किया गया है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस आशंका को खारिज किया कि यह कार्यक्रम जल्दबाजी में लागू किया गया। मंत्रालय ने कहा कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है। इथेनॉल का आविष्कार हमने नहीं किया था, जिसे एक सदी से भी पहले, हेनरी फोर्ड ने 'मॉडल टी' को इथेनॉल से चलाने के लिए डिजाइन किया था और ब्राजील एवं अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों ने दशकों से इथेनॉल ब्लेंड का इस्तेमाल किया है।

सीएसआर के जरिए उत्तराखंड के विकास में भागीदार बनें उद्योग
निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार : सीएम धामी

एजेंसी, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उद्योग जगत से राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनने और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत उत्तराखंड में अधिक निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट क्षेत्र की भागीदारी से राज्य के समग्र एवं सतत विकास को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित 'उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में सीएसआर के तहत किया गया योगदान विशेष महत्व रखता है। उन्होंने राज्य में कार्यरत औद्योगिक समूहों से अपने सीएसआर फंड का अधिकतम उपयोग उत्तराखंड में ही करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल औपचारिक

बैठक नहीं, बल्कि राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का साझा संकल्प है। कार्यक्रम के दौरान कौशल विकास, सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए तथा कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। ऐसे में राज्य को ऐसा विकास मॉडल चाहिए जो रोजगार सृजन, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करे। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में कॉरपोरेट जगत का अनुभव और संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। धामी ने कहा कि वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य को 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम सहित 30 से अधिक उद्योग समर्थक नीतियां लागू कर निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है।

12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं अब केवल डॉक्टर की पर्ची पर मिलेंगी

◆ मेडिकल स्टोरों को इनकी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा

एजेंसी, नई दिल्ली। अब बाजार में अधिक अल्कोहल वाली दवाएं बिना लाइसेंस व डॉक्टरों की पर्ची के बिना नहीं मिलेंगी।

केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए अधिक मात्रा में अल्कोहल (इथाइल अल्कोहल) वाली दवाओं की बिक्री और वितरण पर सख्त नियम लागू किए हैं। इसके तहत अब 12 प्रतिशत से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली और 30 मिली से अधिक मात्रा की सभी दवा तैयारियों को पहले की तरह शेड्यूल के तहत छूट नहीं मिलेगी। यानी अब इन दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सरकार ने इन दवाओं को शेड्यूल एच 1 में शामिल किया है। इसका मतलब है कि अब ये दवाएं केवल पंजीकृत डॉक्टर की पर्ची पर ही बेची जा सकेंगी। मेडिकल स्टोरों को इनकी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा। इस कदम का उद्देश्य ऐसी दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी सूचना के अनुसार, इलायची, अदरक और अन्य सुगंधित टिंचर जैसी कुछ औषधीय तैयारियों में 80-90प्रतिशत तक इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। इन्हें दवा के बजाय नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने की शिकायतें कई राज्यों से मिली थीं। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, नए नियमों से ऐसी दवाओं की बिक्री केवल अधिकृत दवा आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से होगी। इससे इनके दुरुपयोग पर रोक लगेगी, जबकि वास्तविक मरीजों को जरूरत के अनुसार दवाएं पहले की तरह उपलब्ध होती रहेंगी।

डीबीटी से पारदर्शिता बढ़ी, योजनाओं का लाभ सीधे खातों में पहुंचा : मुख्यमंत्री सैनी

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए राज्य के लाखों लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी।

सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न 19 योजनाओं के तहत 50 लाख 20 हजार 460 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 1582 करोड़ 16 लाख रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि भेजना सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सीएम

लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी

सीएम ने कार्यक्रम के दौरान दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त भी जारी की। इसके तहत 9 लाख 98 हजार बहनों और बेटियों के बैंक खातों में 209 करोड़ 69 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। सीएम ने बताया कि योजना की शुरुआत से अब तक 9 किस्तों में कुल 1832 करोड़ 69 लाख रुपए लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं।

ने कहा कि 15 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34 लाख 83 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में 1121 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि सीधे भेजी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

वकील ने सीजेआई सूर्यकांत का नाम लेकर कहे अपशब्द

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक वकील ने हंगामा किया। सीजेआई सूर्यकांत को अपशब्द कहे और फाइल भी फेंकी। इस दौरान सीजेआई कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थे। दरअसल, यह केस जस्टिस केवी विश्वनाथन, जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने सुना जा रहा था। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती की याचिका का था। इस पर याचिकाकर्ता ही पैरवी कर रहा था, जब उस याचिकाकर्ता वकील ने अभद्रता शुरू की, तब कोर्ट रूम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। सिक्योरिटी ने उसे कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया।

हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप करने वाले क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करा पाएंगे : सीएम योगी

एजेंसी, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था का दिखावा करने वाले दलों पर रामनगरी में कड़ा प्रहार किया।

उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी, लेकिन क्या सपा, कांग्रेस या अन्य सरकारें जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएंगी। यदि नहीं करा पाएंगी, तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों कराया गया था? आस्था का दिखावा कर रहे लोगों ने यह पाप किया था, जबकि भाजपा ने अयोध्या को सनातन धर्म की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 217 विकास

परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर अयोध्या के विकास कार्यों पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना की प्रतिमा का अनावरण भी किया व लोकार्पण व शिलान्यास वाली तमाम योजनाओं का जिक्र कर इनका श्रेय जनता व जनप्रतिनिधियों को दिया। बीकापुर विधायक ने पिछली बार ग्राम पंचायत खिरौनी-सुचित्तागंज को नगर पंचायत बनवाया था। अब उनकी मांग पर यह नगर पंचायत में ज्वाला देवी के नाम पर होगी। समाजवादी पार्टी का असली चरित्र सभी ने देखा होगा, जब इनके नमूने चेयरमैन ने भदरसा में गुस्ताखी की थी। भदरसा नगर पंचायत अब भरतनगर भरतकुंड होगा। भाई-भाई का संबंध भरत जी से सीखिए।

14 वर्ष तक भरतकुंड के पास रहकर उन्होंने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया। भगवान राम की चरण पादुकाएं अयोध्या का संचालन कर रही थीं।

सीएम रेखा ने नितिन गडकरी से मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की अपील की

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर दक्षिण दिल्ली के मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और इसके विकास का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि लगभग 8.8 किलोमीटर लंबा मांडी रोड दिल्ली-एनसीआर का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सड़क गलियारा है।

यह छतरपुर मेट्रो स्टेशन के निकट महरौली-गुरुग्राम रोड (एनएच-148ए) को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से जोड़ता है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पड़ोसी आर्थिक केंद्रों गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच एक महत्वपूर्ण

◆ मांडी रोड के उन्नयन से यात्रियों को मिलेगी बेहतर यातायात सुविधा

संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है तथा अंतर-राज्यीय यातायात के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर (यूटीटीआईपीईसी) की गवर्निंग बॉडी ने 27 सितंबर 2023 को आयोजित 68वीं बैठक में मांडी रोड के महत्व को मान्यता देते हुए इसके चौड़ीकरण और व्यापक विकास के प्रस्ताव का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि मांडी रोड के रणनीतिक महत्व, मौजूदा और भावी यातायात मांग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-148ए के साथ इसके सीधे संपर्क को देखते हुए इस सड़क को एनएचएआई के दायरे में लाने पर विचार किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर इसके विकास की जिम्मेदारी एनएचएआई को सौंपी जाए, ताकि इसके विकास के काम का समयबद्ध उन्नयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रतिदिन इस मार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों को बेहतर और अधिक सुगम यातायात सुविधा मिलेगी।

बैठक प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में 75 करोड़ से बनेंगी आधुनिक जांच लैब, भर्ती प्रक्रिया भी तेज

आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे सभी मेडिकल कॉलेज: सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को इस वर्ष के अंत तक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस किया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य के भीतर ही उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने हजारों पदों पर भर्ती की है। उन्होंने कहा कि एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश के

स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। उन्होंने बताया कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी आयुर्विज्ञान (एआईएमएसएस) चमियाणा में अत्याधुनिक जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। इन प्रयोगशालाओं के लिए राज्य सरकार ने 75 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी) शिमला में पीईटी स्कैन मशीन स्थापित की जा चुकी है। टांडा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए भी पीईटी स्कैन मशीनों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न पैरामेडिकल श्रेणियों के 71 पद और 50 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा पैरामेडिकल श्रेणियों के 162 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं।

आईजीएमसी, टांडा व एआईएमएसएस चमियाणा में नए भवनों के निर्माण को मिली रफ्तार

चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराया जाएगा और प्रत्येक बैच में 60 विद्यार्थियों की संख्या सुनिश्चित की जाएगी। आईजीएमसी शिमला में तीन लेक्चर थिएटर और एक परीक्षा भवन के निर्माण के लिए 5.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में लेक्चर थिएटर के निर्माण के लिए अतिरिक्त 14.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एआईएमएसएस चमियाणा में 23.75 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल ब्लॉक और 42 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।

प्रदेश में खराब मौसम के दौरान उपायुक्त करेंगे स्कूल बंद करने का फैसला : रोहित

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान लगातार हो रही बारिश के बीच राज्य सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को कहा है कि सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने-अपने जिले में मौसम की स्थिति के अनुसार स्कूल खुले रखने या बंद करने का अधिकार दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों की सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दे रही है और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जहां भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से छात्रों और शिक्षकों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका होगी, वहां संबंधित जिला उपायुक्त स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर स्कूलों को बंद रखने या खोलने का निर्णय ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था मानसून के दौरान लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। इसी व्यवस्था के तहत शुक्रवार को भारी बारिश के कारण सोलन और सिरमौर जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला संबंधित जिला प्रशासन ने लिया। सरकार का कहना है कि मौसम की स्थिति सामान्य होने पर आगे के निर्णय भी जिला प्रशासन स्थानीय हालात के अनुसार लेगा।

रोहित ठाकुर ने कहा कि मानसून को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेब सीजन शुरू होने के साथ बड़ी संख्या में बागवानों की आवाजाही रहती है और प्रदेश में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में सड़कें बंद होने की स्थिति में उन्हें परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को बंद मार्गों को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार मौसम की स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

71 दिनों में पहुंचे 22 लाख वाहन

रिकॉर्ड पर्यटकों के बावजूद सामान्य रही ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस की रणनीति कामयाब

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस साल ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों की भारी आमद दर्ज की गई है। 1 मई से 10 जुलाई तक 71 दिनों में विभिन्न प्रवेश मार्गों से करीब 22 लाख वाहनों का आवागमन हुआ।

इनमें मई में करीब 8.5 लाख, जून में 10.5 लाख और जुलाई के पहले 10 दिनों में ही करीब तीन लाख वाहन शिमला पहुंचे। प्रदेश में मानसून ने 30 जून को दस्तक दे दी थी और उसके बाद लगातार कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। इसके बावजूद शिमला आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी नहीं आई। इतनी बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने के बाद भी शहर की यातायात व्यवस्था सामान्य बनाए रखना शिमला पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही। पुलिस का कहना है कि पहले से बनाई गई योजना और अतिरिक्त तैनाती के कारण पूरे पर्यटन सीजन में शहर में यातायात को लगातार सुचारु रखा गया। बढ़ते दबाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड के जवानों की संख्या 136 से बढ़ाकर 265 की गई। इसके साथ करीब 50 स्वयंसेवकों और 32 ट्रैफिक बाइक राइडर्स की भी तैनाती की गई। इससे जाम की स्थिति बनने पर तुरंत कार्रवाई कर यातायात को सामान्य किया गया।

शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर ढंग से संभालने के लिए पूरे शिमला को पांच सेक्टरों में बांटा गया। हर सेक्टर की जिम्मेदारी डीएसपी ट्रैफिक की निगरानी में एक एनजीओ ग्रेड-वन अधिकारी को सौंपी गई। ये अधिकारी निगरानी के साथ खुद सड़क पर मौजूद रहकर यातायात संचालन करते रहे। थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी व्यस्त समय में लगातार सड़कों पर मौजूद रहे और जरूरत पड़ने पर मौके पर ही निर्णय लेकर व्यवस्था संभाली। पुलिस के अनुसार किसी भी मार्ग पर यातायात को पूरी तरह रोकने की स्थिति नहीं आने दी गई। जहां भी दबाव बढ़ा, वहां सेक्टर अधिकारियों, ट्रैफिक बाइक राइडर्स और क्रेन की मदद से रास्तों को जल्द खाली कराया गया। शहर के भीतर वाहनों का दबाव कम करने के लिए कुफरी, मशोबरा, नालदेहरा, अपर शिमला और किन्नौर जाने वाले वाहनों को शोगी-मेहली बाईपास से भेजने की व्यवस्था की गई। ऐसे वाहनों की पहचान शोगी से पहले स्टिकर लगाकर की गई। इसके चलते हर दिन औसतन 600 से 800 वाहन इस वैकल्पिक मार्ग से गुजरते रहे, जिससे शहर के मुख्य मार्गों पर दबाव कम हुआ। पुलिस ने जरूरत के अनुसार भीड़ वाले स्थानों पर वाहनों का चरणबद्ध नियमन भी किया। साथ ही ट्रैवलर, अर्बेनिया और स्कैनिया जैसे बड़े यात्री वाहनों को प्रमुख पर्यटन स्थलों तक जाने की अनुमति दी गई, जिससे पर्यटकों को आवाजाही में सुविधा मिली।

शिमला पुलिस का दावा है कि यातायात प्रबंधन के दौरान पार्किंग स्थलों की निगरानी, सोशल मीडिया के जरिए रीयल टाइम ट्रैफिक अपडेट, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने और इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से यातायात नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया गया। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ट्रैफिक विंग, जिला पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्कूली छात्रों, स्थानीय स्वयंसेवकों और अन्य विभागों के समन्वित प्रयासों से भारी पर्यटक दबाव के बावजूद शहर की यातायात व्यवस्था सामान्य बनी रही। पुलिस ने नागरिकों और पर्यटकों के सहयोग के लिए आभार जताते हुए भविष्य में भी सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री को ऐसे बयान शोभा नहीं देते : सत्ती

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उनके बयान स्पष्ट रूप से क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे कैबिनेट मंत्री से इस प्रकार की संकीर्ण और विभाजनकारी भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

प्रदेश को जोड़ने का दायित्व निभाने के बजाय विक्रमादित्य सिंह समाज को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। सतपाल सत्ती ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं है, जब विक्रमादित्य सिंह ने गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया हो। इससे पहले भी वे अपने ही अधिकारियों, अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों के कारण कई बार कांग्रेस सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है और स्वयं मुख्यमंत्री तथा पार्टी नेतृत्व को भी उनसे दूरी बनानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 में बाहरी राज्यों से आए आईएएस व आईपीएस अधिकारियों को लेकर दिए गए उनके बयान ने पूरे प्रशासनिक तंत्र में विवाद खड़ा कर दिया था। प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के संगठनों ने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। अंततः उनकी अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री को इस बयान से किनारा करना पड़ा। इससे पहले स्ट्रीट वेंडर्स और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के बयान पर भी कांग्रेस नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ी थी। हाल ही में राम मंदिर के चंदे की जांच संबंधी बयान देकर उन्होंने फिर अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया। सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आजकल एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है और इसी प्रतिस्पर्धा में उसके नेता बिना सोचे-समझे बयान देकर सुर्खियां बटोरने का प्रयास करते हैं। विक्रमादित्य सिंह भी इसी प्रवृत्ति का शिकार हैं और राजनीतिक परिपक्वता के बजाय बचकाने बयान देकर अपनी ही पार्टी और परिवार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।

एबीवीपी नगरोटा इकाई के अध्यक्ष अमन लाल व कुनाल बने सचिव

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के 78वें स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर धर्मशाला कॉलेज के सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ रक्तदान शिविर के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और युवाओं ने रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया। इसके बाद पंजाबी नृत्य, गद्दी नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गईं, जिन्हें उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में उमेश दत्त उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में एबीवीपी के 78 वर्षों के गौरवशाली इतिहास, राष्ट्र निर्माण में संगठन की भूमिका व छात्र शक्ति के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्रहित व समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद चुनाव अधिकारी शक्ति की देखरेख में नगरोटा इकाई का गठन किया गया। इसमें अधिवक्ता अमन लाल को नगरोटा इकाई का अध्यक्ष और कुनाल को सचिव नियुक्त किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और छात्र हितों के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उद्घोष के साथ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

भाजपा बिलासपुर का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न

कार्यकर्ताओं को संगठन व राष्ट्र निर्माण का दिया संदेश

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के तहत आयोजित भाजपा बिलासपुर के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को समापन हो गया।

झंडूता विधानसभा क्षेत्र के शाहतलाई में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन छह सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर के नेताओं और विशेषज्ञ वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन, सरकार की योजनाओं, मीडिया प्रबंधन और पार्टी के इतिहास सहित विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया। शिविर के दूसरे दिन पहले सत्र में भाजपा के प्रदेश सहप्रभारी संजय टंडन ने संगठन की कार्यपद्धति पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भाजपा में व्यक्ति से अधिक विचारधारा को महत्व दिया जाता है। पार्टी में किसी पद से ज्यादा दायित्व महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि सामूहिक निर्णय, आपसी समन्वय और अनुशासित कार्यशैली भाजपा संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। दूसरे सत्र में भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने केंद्र की मोदी सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। तीसरे सत्र में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने मीडिया प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बदलते दौर में मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक जानकारी दी। अंतिम सत्र में नयनादेवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने भाजपा के इतिहास और संगठन की यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और संघर्षों से अवगत करवाया। इस प्रशिक्षण शिविर में जिला भर से लगभग 200 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। समापन अवसर पर झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने शिविर के सफल आयोजन के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णलाल चंदेल सहित झंडूता और शाहतलाई मंडलों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को बधाई दी।

लंबे अंतराल बाद शुरू होगा हिमाचल बाल विज्ञान सम्मेलन, छात्रों में वैज्ञानिक सोच को मिलेगा बढ़ावा

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में लंबे अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश बाल विज्ञान सम्मेलन के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सम्मेलन का संचालन हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के माध्यम से किया जा रहा है।

सम्मेलन का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार, अनुसंधान और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। बाल विज्ञान सम्मेलन में सरकारी और निजी विद्यालयों के कक्षा छठी से बारहवीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। जिला हमीरपुर के इच्छुक विद्यार्थियों को जल्द शुरू होने वाले एचपी सीएसएसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र होंगे। सम्मेलन के तहत मैथ ओलंपियाड, साइंस क्विज, साइंस मॉडल मेकिंग, साइंस एक्टिविटी कॉर्नर और साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन सितंबर 2026 से दिसंबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से खंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन अगले स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा।

जिला विज्ञान पर्यवेक्षक राजेश गौतम ने बताया कि बाल विज्ञान सम्मेलन विद्यार्थियों को वैज्ञानिक परियोजनाएं प्रस्तुत करने, स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान खोजने और अपने नवाचारी विचारों को साझा करने का मंच उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, तार्किक क्षमता और अनुसंधान की प्रवृत्ति को मजबूती मिलेगी। राजेश गौतम ने बाल विज्ञान सम्मेलन को दोबारा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला हमीरपुर के विज्ञान शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी ऑनलाइन पंजीकरण में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे और जिला को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखने में योगदान देंगे।

रूपिंदर कौर ने संभाला बिलासपुर एडीसी का कार्यभार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। आईएएस 2021 बैच की अधिकारी रूपिंदर कौर ने शुक्रवार को बिलासपुर में अतिरिक्त उपायुक्त व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सह-परियोजना निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया।

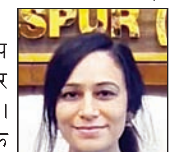

उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार की विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगी। उन्होंने ग्रामीण विकास, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। बिलासपुर नियुक्ति से पहले वह मंडी सदर में एसडीएम के पद पर सेवाएं दे चुकी हैं। आईएएस बनने से पूर्व उनका चयन आईपीएस में भी हुआ था। उन्होंने आईआईटी रोपड़ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है।

भाजपा के मेयर-डिप्टी मेयर्स को शपथ न दिलाना व्यवस्था परिवर्तन का नमूना: अनिल

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। सदर के विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के चलते भाजपा के जीते हुए नगर निगमों में मेयर व डिप्टी मेयर को शपथ दिलाने की नोटिफिकेशन में देरी की जा रही है, जिसके चलते जीतने के बावजूद भी मेयर-डिप्टी मेयर अपना कार्यभार संभाल नहीं पा रहे हैं। शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की माली हालत ठीक न होने की वजह से विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मंडी में नगर निगम भाजपा का बहुमत है और पूर्व में भी भाजपा की ही नगर निगम रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व नगर निगम ने बहुत से विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन बजट की कमी की वजह से कई देनदारियां अभी भी देनी है। हालांकि, नगर निगम अपने आपमें एक स्वायत संस्था है। लेकिन स्थानीय विधायक होने के नाते नगर निगम के लिए बजअ उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम से पहले ही अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा प्रबंधन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मंडी पेयजल संवर्धन योजना उहल को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जिसके लिए तीन वैकल्पिक स्रोत से जोड़ा गया है। इस बार बरसात के मौसम में मंडी शहर के लिए पानी की किल्लत नहीं होगी।

सरकार के व्यवस्था परिवर्तन से बिगड़ी प्रदेश की कानून व्यवस्था : राकेश शर्मा

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारियों की बेलगाम कार्यप्रणाली को लेकर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा द्वारा गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं।

प्रदेश कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर कटास करते हुए उन्होंने बिलासपुर समेत अन्य क्षेत्रों में दिनदहाड़े गोलीबारी च मारपीट की घटनाओं ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं तथा कहा कि शिमला सहित विभिन्न क्षेत्रों में दिनदहाड़े गोलीबारी, कुल्हाड़ी से हमले और हत्या जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आला अधिकारियों और शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के मामले भी सामने आए हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगा है। शुक्रवार को धर्मशाला से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेश में अपराधिक गतिविधियों का ग्राफ बढ़ा हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री सुक्खविंद्र सिंह सुक्खू इस बावत कड़ा संज्ञान लेने की बजाए तमाशगीन बने हुए हैं। उन्होंने कहा कहा कि प्रदेश में न्याय मांगने वालों पर खुद सरकार मामले दर्ज करवा रही है, जबकि अपराधी बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। राकेश शर्मा ने कहा कि सुक्खू सरकार ने जो व्यवस्थ्सा परिवर्तन किया है उससे जनता में त्राहिमान मचा हुआ है।

शिमला में सेब के बगीचे में पेड़ से लटका मिला महिला का शव

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिले में 34 वर्षीय महिला का शव सेब के बगीचे में एक पेड़ से लटका मिला है। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की अंतिम पुष्टि होगी। ये घटना जिला के नेरवा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मढ़ाना में सामने आया। पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत मढ़ाना के प्रधान ने नेरवा थाना को फोन पर सूचना दी कि गांव मढ़ाना की रहने वाली गीता देवी पत्नी सुरेश कुमार ने कथित रूप से बुरांश के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस ने सेब के बगीचे में महिला का शव बरामद किया। मौके पर बुरांश के पेड़ से रस्सी लटकी हुई मिली। पुलिस ने बताया कि महिला के शरीर पर गर्दन पर फंदे के निशान के अलावा कोई बाहरी चोट नहीं मिली। घटनास्थल और घर की तलाशी के दौरान कोई सुसाइड नोट या अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद नहीं हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेरवा पहुंचाकर सुरक्षित रखवा दिया है।

12 महीने के वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर रोहित से मिला प्रतिनिधिमंडल

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू का प्रतिनिधिमंडल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मिड डे मील वर्कर्स की समस्याओं और लंबित मांगों को शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा। शिक्षा मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल ने वेतन वृद्धि, हर माह समय पर पूरा वेतन जारी करने, वर्ष में 20 छुट्टियां देने, दो वर्दियां उपलब्ध करवाने, चुनाव ड्यूटी के दौरान आर्थिक भुगतान करने, 21 अगस्त के निदेशक के ड्यूटी संबंधी आदेश लागू करने, मेडिकल चेकअप के दौरान वेतन भुगतान करने और क्लस्टर स्कूलों से कर्मियों की छंटनी रोकने की मांग उठाई। इसके अलावा मिड डे मील वर्कर्स को ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी और कर्मचारी मुआवजा सुविधा देने, 25 बच्चों की शर्त समाप्त करने तथा 12 महीने का वेतन देने की मांग भी रखी गई। शिक्षा मंत्री ने इन मुद्दों पर उचित समाधान का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधिमंडल में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम, कोषाध्यक्ष जगत राम, यूनियन प्रदेशाध्यक्ष संदीप कुमार, महासचिव शांति देवी, कोषाध्यक्ष सपना ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। यूनियन अध्यक्ष संदीप कुमार और महासचिव शांति देवी ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में करीब 21 हजार बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने का कार्य वर्कर्स द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिड डे मील वर्कर्स को कई बार समय पर वेतन नहीं मिलता और उन्हें पूरे वर्ष में कोई अवकाश सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच द्वारा 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन देने के फैसले के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया है। यूनियन ने 25 बच्चों की शर्त हटाने, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी और पेंशन सुविधा देने, मेडिकल जांच का खर्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन करने, मिड डे मील योजना को प्लस टू स्तर तक लागू करने, वेतन का भुगतान हर माह की पहली तारीख को करने तथा चुनावी ड्यूटी में अतिरिक्त मानदेय देने की मांग की।

शिमला ग्रामीण में कांग्रेस का कुनबा बढ़ा, 50 लोगों ने थामा पार्टी का दामन

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष हरिकृष्ण हिमराल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के करीब 50 लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान नए कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की नीतियों और निर्णयों में आस्था जताते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया।

कांग्रेस में शामिल होने वालों में रोहड़ू से एचआरटीसी के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक केसी चौहान, शिमला ग्रामीण से पूर्व बीडीसी सदस्य लक्ष्मी दास, वार्ड सदस्य जय लाल नेगी और वार्ड सदस्य करिश्मा शर्मा सहित अन्य समर्थक शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन विनोद जिंटा, कांग्रेस उपाध्यक्ष अमित नंदा, सोनिया चौहान, प्रधान जितेंद्र ठाकुर, पवन कुमार, कुलदीप ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने कहा कि नए कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने से संगठन को मजबूती मिल रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे संगठन विस्तार अभियान के तहत लगातार नए लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष हरिकृष्ण हिमराल ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन से जुड़ने वाले सभी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन को मजबूत करने और अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

निरीक्षण मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना : 24 आवासों का निर्माण जारी, डीसी ने निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश

'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' को मिलेगी पक्की छत

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत जिला शिमला में बन रहे लाभार्थियों के आवासों की समीक्षा डीसी अनुपम कश्यप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की।

उन्होंने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को निर्देश दिए कि आवास निर्माण कार्य पूरा होने तक हर तीन महीने में लाभार्थियों के घरों का निरीक्षण सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्रत्येक सीडीपीओ को हर महीने कम से कम एक निर्माणाधीन आवास की फील्ड रिपोर्ट स्वयं लेने के निर्देश दिए गए। डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेसहारा बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा देकर उनके बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपी है। ऐसे में सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि योजना के

लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत बेघर अनाथ और निराश्रित बच्चों को घर बनाने के लिए तीन बीघा जमीन और तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। जिला शिमला में योजना के तहत 29 लाभार्थियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से पांच घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 24 आवासों का कार्य जारी है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने लाभार्थियों से फोन पर बातचीत कर निर्माण कार्य और सहायता राशि की जानकारी भी ली। कुमारसैन क्षेत्र के अक्षित और ननखड़ी के शानित ने बताया कि उन्हें विभाग से नियमित सहायता मिल रही है और आवास निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल सहित सभी सीडीपीओ मौजूद रहे।

जनगणना की तैयारियों की समीक्षा, समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश

शिमला। जनगणना-2027 के प्रथम चरण (हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस) की प्रगति को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में चार्ज अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का कार्य 11 जुलाई तक तथा आंकड़ों की जांच, परीक्षण और सत्यापन का कार्य 15 जुलाई तक पूरा किया जाना है। उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने और त्रुटियों को समय रहते सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़ों की गुणवत्ता, शुद्धता, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को विशेष संकेतकों के सत्यापन, पूर्ण कवरेज और समयबद्ध डेटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में दूसरे चरण की तैयारियों, विशेषकर हिमपात प्रभावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम योजना बनाने पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा और जिला राजस्व अधिकारी शिवानी भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आईटीआई के 30 मेधावी प्रशिक्षु कजाकिस्तान जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण का मिलेगा अनुभव

शिमला। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के 30 मेधावी प्रशिक्षुओं का दल अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के लिए 12 जुलाई को कजाकिस्तान रवाना होगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में जाने वाले इस प्रतिनिधिमंडल में 30 प्रशिक्षुओं के अलावा तकनीकी शिक्षा निदेशक और तीन संकाय सदस्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू वर्चुअल माध्यम से दल को रवाना करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में 21 पुरुष और 9 महिला प्रशिक्षु शामिल हैं, जो 16 राजकीय आईटीआई और 10 ट्रेड का प्रतिनिधित्व करेंगे। कजाकिस्तान के अल्माटी में प्रशिक्षु औद्योगिक प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों और आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा कर तकनीकी शिक्षा, विनिर्माण प्रक्रियाओं और कौशल विकास की नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

कार्यालय ग्राम पंचायत मूलबरी देवनगर
विकास खंड टूटू (हीरा नगर) तह. व जिला शिमला (हि. प्र.)

निविदा सूचना

ग्राम पंचायत मूलबरी देवनगर मे मनरेगा वअन्य सभी मदों के तहत विभिन विकास कार्यो के निष्पादन के लिए वर्ष 2026-27 हेतु निर्माण सामग्री जैसे रेत, ईंट, बजरी, इंटरलॉक , टाइल्स, पेवरब्लाक, सरिया, पत्थर, ड्रेनेज पाइपें, जे0 सी0 बी0 मशीनरी के कार्य, कंक्रीट मिक्षर व कुशल मजदूरों की व सीमेंट केरिज़ की आवश्यकता है जिसके लिए ग्राम पंचायत मूलबरी देवनगर निविदाए आमंत्रित करती है बंद लिफाफे मे अपनी निविदाए दिनांक 23-07-2026 तक पंचायत मे जमा करवा दे व 25-07-2026 को सुबह 11 बजे निविदाएं खोल दी जाएगी जिसकी निविदाएं सबसे कम दर की प्राप्त होती है उसे पंचायत द्वारा स्वीकृत कर दी जाएगी निविदाए स्वीकृत होने के उपरांत प्रार्थी द्वारा यदि मटेरियल की गुणवता सही नही पाई जाती है तो उसे उसी समय रद्द करवाकर दूसरे कम दर की निविदाओं को स्वीकृत किया जा सकता है । विस्तृत विवरण की जानकारी तथा आवेदन कर के लिए ग्राम पंचायत मूलवरी देवनगर से सीधे तौर पर 23-07-2026 तक संपर्क करें। संबन्धित फर्म के पास GST Noव W / X (M) Form होना अनिवार्य है अन्यथा फर्म को रद्द कर दिया जाएगा ।

नोट :- मटेरियल खरीद करते समय पारित निविदा करता को मौके पर अदायगी नही हो पाएगी ।

प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत मूलबरी देवनगर
विकास खंड टूटू (हीरा नगर) तह. व जिला शिमला (हि. प्र.)

केदारनाथ धाम में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट

भारतेंदु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की ओर से जारी भारी वर्षा की चेतावनी के बाद केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन की टीमें लगातार यात्रा मार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी कर रही हैं।

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देश पर केदारनाथ यात्रा मार्ग के सभी संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। सेक्टर अधिकारियों के साथ पुलिस, आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासनिक टीमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम तक लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों की ओर से यात्रियों और स्थानीय लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की जा रही है।

भारी बारिश और नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका को देखते हुए केदारनाथ धाम स्थित संगम घाट क्षेत्र में मौजूद यात्रियों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। प्रशासन ने यह कदम किसी भी संभावित दुर्घटना या अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखी गई हैं।

देहरादून में आज से शुरू होगा पांच दिवसीय लोक संवर्धन पर्व

कारीगरों और शिल्पकारों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच, देहरादून में लगेगा महोत्सव

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून के परेड मैदान में 11 से 15 जुलाई तक पांच दिवसीय लोक संवर्धन पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त सहयोग से आयोजित होने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन 11 जुलाई को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे। उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा उत्तराखंड सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यह महोत्सव 15 जुलाई तक प्रतिदिन आम जनता के लिए निशुल्क खुला रहेगा और इसमें देशभर की पारंपरिक कला, संस्कृति, हस्तशिल्प तथा स्थानीय व्यंजनों की विविधता देखने को मिलेगी।

◆ **लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू**

लोक संवर्धन पर्व का यह छठा संस्करण कई मायनों में विशेष माना जा रहा है। पहली बार इस आयोजन को किसी राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और उत्तराखंड इस पहल में भागीदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह आयोजन प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश की पारंपरिक कला, शिल्प, हथकरघा, लोक संस्कृति और पारंपरिक आजीविका को संरक्षण प्रदान करना है। केंद्र और राज्य सरकार की यह संयुक्त पहल कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए कारीगर अपनी उत्कृष्ट हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन स्थल पर लगभग 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें करीब 40 प्रतिशत स्टॉल उत्तराखंड के स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आरक्षित होंगे। इन स्टॉलों पर राज्य की पारंपरिक कला, लकड़ी की नक्काशी, ऊनी वस्त्र, हस्तनिर्मित उत्पाद और स्थानीय शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध हस्तशिल्प, अजरख ब्लॉक प्रिंटिंग, लाख की चूड़ियां, पीतल शिल्प, टेराकोटा कला, बांस और बेंत से बने उत्पाद, हथकरघा वस्त्र तथा देश के विभिन्न हिस्सों की पारंपरिक कलाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

हरेला सप्ताह में हुआ 10 हजार पौधों का रोपण

भारतेंदु संवाददाता, पिथौरागढ़। हरेला सप्ताह के उपलक्ष्य में 130 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) इकोलॉजिकल कुमाऊँ द्वारा आज बनानी क्षेत्र में ग्राम पंचायत, स्थानीय ग्रामीणों एवं स्कूली विद्यार्थियों के सहयोग से विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण में वृद्धि तथा जनसहभागिता के माध्यम से प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। अभियान के अंतर्गत आज 10,000 पौधों का रोपण किया गया।अभियान में बटालियन के अधिकारियों, सैनिकों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों तथा स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण एवं भावी पीढ़ियों के लिए हरित एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया।बटालियन द्वारा हरेला सप्ताह के दौरान 70,000 पौधों के रोपण एवं बीजारोपण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान 16 जुलाई 2026 को हरेला पर्व के अवसर पर अपने भव्य समापन तक पहुँचेगा।

समापन अवसर पर लेलू ग्राम, पिथौरागढ़ में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य वन विभाग, जिला प्रशासन, भारतीय सेना, अर्द्धसैनिक बल ग्राम पंचायतें, स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवी संगठन, स्कूली छात्र-छात्राएँ तथा अन्य सामाजिक संगठन संयुक्त रूप से सहभागिता करेंगे।

वन्यजीव सुरक्षा के लिए एनएचएआई ने किए विशेष इंतजाम

वन्यजीव संरक्षण पर खर्च होंगे 6.04 करोड़ रुपए

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। भानियावाला-जॉलीग्रांट-ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना को लेकर पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण संबंधी उठ रहे सवालों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अपना विस्तृत पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि परियोजना का निर्माण सभी वैधानिक और पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए किया जा रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि यह परियोजना केवल आधुनिक और सुरक्षित सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण संरक्षण, वन क्षेत्र की सुरक्षा और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन को भी समान महत्व दिया गया है।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह ने बताया कि परियोजना की इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करते समय सड़क की क्षमता बढ़ाने के साथ पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम रखने पर विशेष ध्यान दिया गया।

उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र वाले हिस्से में राइट ऑफ वे को यथासंभव कम रखा गया है। जहां सामान्य रूप से 60 मीटर चौड़ाई रखी जाती है, वहीं इस परियोजना में वन क्षेत्र में इसे घटाकर केवल 23 मीटर किया गया है, ताकि अतिरिक्त वन भूमि प्रभावित न हो।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड वन विभाग, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी सुझावों के आधार पर हाथियों सहित अन्य वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए विशेष संरचनाएं विकसित की जा रही हैं।

एनएचएआई ने दिया परियोजना पर स्पष्टीकरण

परियोजना में एक प्रमुख ब्रिज-कम-एलीफेंट अंडरपास और चार समर्पित एलीफेंट अंडरपास बनाए जा रहे हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग साढ़े तीन किलोमीटर होगी। इसके अलावा बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली सूअर, सियार और अन्य वन्यजीवों के लिए छह बॉक्स कल्वर्ट तथा छोटे वन्यजीवों और सरीसृपों के लिए 13 पाइप कल्वर्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। एनएचएआई के अनुसार परियोजना में वन्यजीवों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए ग्रीन गाइड हेज, साउंड बैरियर, एंटी ग्लेयर स्क्रीन, जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल की गई हैं।

उत्तराखंड कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं : केसी वेणुगोपाल

बोले- कांग्रेस जनता की राय से तैयार करेगी घोषणा पत्र, उत्तराखंड में गुटबाजी की खबरों को बताया निराधार

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान शुक्रवार को देहरादून में आयोजित प्रेसवार्ता में स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ और युवा नेता एकजुट होकर आगामी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और संगठन पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरा ध्यान जनता के मुद्दों को उठाने और राज्य में मजबूत विकल्प प्रस्तुत करने पर है।

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उनका दावा था कि महंगाई, बेरोजगारी, विकास कार्यों की धीमी गति और जनहित से जुड़े कई मुद्दों को लेकर जनता सरकार से नाराज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन सभी मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएगी

लगातार बारिश से अलकनंदा का जलस्तर तेजी से बढ़ा।

और आगामी चुनाव में जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास और सुशासन का रोडमैप प्रस्तुत करना है।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए पार्टी की घोषणा पत्र समिति समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषज्ञों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और अन्य संगठनों से सुझाव लेगी। उन्होंने कहा कि जनता की राय के आधार पर ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, जो प्रदेश की वास्तविक आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखे।

प्रेसवार्ता के दौरान केसी वेणुगोपाल ने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे की कथित चोरी के मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की निगरानी में कराई जानी चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके और लोगों का विश्वास बना रहे।

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। उन्होंने उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने सरकार से इस मामले में शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति करते हैं, वे ऐसे मामलों पर जवाब देने से बच रहे हैं।

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस राज्य में संगठन को और मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय बनाने और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगी और लोकतांत्रिक तरीके से जनता का समर्थन हासिल करने का प्रयास करेगी।

प्रेसवार्ता के अंत में उन्होंने दोहराया कि उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह संगठित है और पार्टी के सभी नेता मिलकर प्रदेश के विकास, जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उसी के आधार पर आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है।

न्यूज ब्रीफ

उत्तराखंड में वर्दीधारी सिपाही भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, युवाओं को तीन साल तक आयु सीमा में राहत

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वर्दीधारी सिपाही पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। कार्मिक विभाग ने चयन प्रक्रिया संशोधन नियमावली 2026 जारी कर दी है। इसके तहत 31 दिसंबर 2028 तक कई पदों पर भर्ती संबंधित सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी। नए नियमों के कारण आयु सीमा से बाहर हो रहे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक जनवरी 2029 से सभी पदों पर 35 वर्ष की आयु सीमा लागू होगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलती रहेगी। फैसले से हजारों बेरोजगार युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

एफआरआई में सेना के अधिकारियों को मिला वन संरक्षण का प्रशिक्षण

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) देहरादून में शुक्रवार को भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों के लिए **वन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं सतत प्रबंधन** विषय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एफआरआई की निदेशक ऋचा मिश्रा ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण के संतुलन पर जोर दिया। प्रशिक्षण में लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज गुरुंग, मेजर पी.सी. मिश्रा सहित लगभग 45 सैन्य कर्मियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों के पुनर्स्थापन तथा सैन्य गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य सेना के कर्मियों को संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाना था।

पंजाब एंड सिंध बैंक ने टनकपुर अस्पताल को दी हीमोडायलिसिस मशीन

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जनस्वास्थ्य के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (छ्टर) कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, टनकपुर को अत्याधुनिक हीमोडायलिसिस मशीन भेंट की है। इस हीमोडायलिसिस मशीन का लोकार्पण उत्तराखंड संवाद छ्टर -2026 कार्यक्रम के दौरान दिनांक 10 जुलाई 2026 को उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दूरस्थ माध्यम से किया गया। इस अवसर पर पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री स्वरूप कुमार साहा सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जिला चिकित्सालय, टनकपुर में स्थापित इस अत्याधुनिक हीमोडायलिसिस मशीन से अस्पताल की डायलिसिस सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा किडनी संबंधी रोगों से पीड़ित मरीजों को बेहतर एवं समयबद्ध उपचार उपलब्ध हो सकेगा। इस पहल से टनकपुर तथा आसपास के क्षेत्रों के हजारों मरीजों को अपने निकट ही गुणवत्तापूर्ण एवं जीवनरक्षक डायलिसिस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इस अवसर पर पंजाब एंड सिंध बैंक ने समाज के समग्र विकास एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि बैंक स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, पर्यावरण संरक्षण तथा सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में प्रभावी एवं सतत परियोजनाओं के माध्यम से समाज के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर कार्य करता रहेगा।

हॉलमार्किंग अनियमितताओं पर बीआईएस सख्त

फर्जी हॉलमार्किंग पर बीआईएस की बड़ी कार्रवाई, हरिद्वार में दो प्रतिष्ठानों पर छापेमारी

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के देहरादून शाखा कार्यालय ने फर्जी हॉलमार्किंग की शिकायत मिलने पर हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में दो आभूषण प्रतिष्ठानों पर प्रवर्तन अभियान चलाया। बीआईएस की टीम ने जहांगीर और बादशाह नामक प्रतिष्ठानों पर तलाशी एवं जांच कर हॉलमार्किंग से जुड़े उपकरणों, अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया।

जांच के दौरान एक कटिंग मशीन भी मिली, जिसे तकनीकी परीक्षण और विस्तृत जांच के लिए बीआईएस की निगरानी में रखा गया है। मामले की जांच भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों के तहत जारी है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बीआईएस के संयुक्त निदेशक सचिन चौधरी ने कहा कि संस्था हॉलमार्किंग प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी ज्वैलर्स से अपील की कि वे केवल बीआईएस से मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग केंद्रों से ही स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग कराएं और सभी कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि 1 जून 2026 से बीआईएस केयर ऐप में नई सुविधा जोड़ी गई है। अब उपभोक्ता किसी भी स्वर्ण आभूषण के छह अंकों वाले एचयूआईडी नंबर को ऐप पर सत्यापित करने पर उस आभूषण का फोटो और वजन भी देख सकते हैं।

पहाड़ों में खेती से समृद्धि का मॉडल बने नरेश भट्ट

भारतेंदु संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक स्थित देवार गांव के प्रगतिशील किसान नरेश चंद्र भट्ट ने आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती को अपनाकर सफलता की प्रेरक कहानी लिखी है। वर्ष 2014 से खेती और पशुपालन को आजीविका का आधार बनाने वाले नरेश भट्ट वर्तमान में करीब 20 नाली भूमि पर व्यावसायिक सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। उनके पॉलीहाउस में गोभी, लहसुन, खीरा, लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च और टमाटर जैसी उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। स्थानीय बाजारों में उनकी उपज की अच्छी मांग है जिससे उन्हें बेहतर आय प्राप्त हो रही है। नरेश भट्ट खेती से प्रतिवर्ष लगभग आठ लाख रुपये की बचत कर रहे हैं। उनकी सफलता से प्रभावित होकर गांव की सात महिलाओं को भी नियमित रोजगार मिला है।

उत्तराखंड का बंगाल से एक विशेष सांस्कृतिक जुड़ाव : महाराज

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। देवभूमि उत्तराखंड आज दुनिया के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनकर उभर रहा है। हमारी सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड पर्यटन को केवल चारधाम यात्रा तक सीमित न रखकर इसे साहसिक, ग्रामीण, सीमांत, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनाया जाए।

उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को कोलकाता के बिस्वा बांग्ला मेला प्रांगण में फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित भारत के सबसे बड़े ट्रैवल ट्रेड शो नेटवर्क स्न्न (ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर) में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होकर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए कही। उन्होंने ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि

◆ **कोलकाता में पर्यटन मंत्री ने किया उत्तराखंड का प्रचार**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की है।

नीति घाटी, चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन किया गया जो समुद्र तल से 14300 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर आयोजित हुआ इसमें देश भर से 1200 से अधिक साहसिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन का भी सफल आयोजन किया गया जिसमें देश के 26 से अधिक राज्यों के लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह दोनों आयोजन विश्व की सबसे ऊंची और चुनौती पूर्ण अल्ट्रा मैराथनों में से गिने जाते हैं।

बदलाव — चौधरी सेठपाल सिंह बने अध्यक्ष, ऋषिपाल सिंह चौहान ने संभाला सचिव पद

लक्सर अधिवक्ता संघ की तीसरी कार्यकारिणी का हुआ गठन

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। लक्सर अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को चंदन पैलेस में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सचिव सहित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे और नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं।

समारोह को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने कहा कि न्याय व्यवस्था को प्रभावी और मजबूत बनाने में बार और बेंच की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि न्यायालय और अधिवक्ता एक दूसरे के सहयोगी हैं और दोनों के बीच आपसी विश्वास सम्मान तथा बेहतर तालमेल से ही न्याय प्रक्रिया को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि कई बार कार्यप्रणाली को लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं लेकिन बातचीत संयम और सकारात्मक सोच के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

◆ **संघ को और सक्रिय बनाने की बढ़ी उम्मीद**

◆ **अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा को नई टीम ने जताई प्रतिबद्धता**

जिला जज ने कहा कि लक्सर न्यायालय में तीसरी बार अधिवक्ता संघ का गठन हुआ है। ऐसे में नई कार्यकारिणी की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई टीम सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधिवक्ता संघ की सक्रियता से न्यायालय की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

समारोह के दौरान चौधरी सेठपाल सिंह ने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद की शपथ ली जबकि ऋषिपाल सिंह चौहान ने सचिव पद की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा नई कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का संकल्प लिया।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौधरी सेठपाल सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं ने जिस विश्वास के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है उसे वह पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यों को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और उनके हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी।

ऋषिकेश में हरियाली बढ़ाने के लिए चला वृक्षारोपण अभियान

भारतेंदु संवाददाता, ऋषिकेश। ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल के सुपुत्र के जन्मदिवस के अवसर पर रेंज कार्यालय ऋषिकेश (निकट इंदिरा नगर) में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संदेश के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक श्री अनिल मित्तल जी ने उपस्थित जनसमूह से अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।इस अवसर पर डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार के शुभ अवसरों जैसे विवाह, जन्मदिन एवं वैवाहिक वर्षगांठ पर

◆ **जन्मदिन को हरियाली के उत्सव में बदला**

वृक्षारोपण को एक परंपरा के रूप में अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी अपने परिवार के प्रत्येक मंगल कार्य पर वृक्षारोपण करते हैं और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करते

उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।कार्यक्रम में ऋषिकेश मंडल अध्यक्ष मनोज ध्यानी, वीरभद्र मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, रायवाला मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र बिष्ट, ऋषिकेश महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष निवेदिता सरकार, वरिष्ठ कार्यकर्ता बृजेश शर्मा, चेतन शर्मा, इंद्र कुमार गोदवानी, माधव नौटियाल, राम सिंह पवार, ज्योति पांडे, वीरभद्र मंडल महामंत्री पुनीता भंडारी, राकेश पारचा, अनिरुद्ध शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हरियाणा पर बढ़ा भाजपा नेतृत्व का फोकस, विकास को रफ्तार

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लगातार दौरों से हरियाणा को विकास परियोजनाओं और राजनीतिक महत्व की मिली नई पहचान

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा में अक्टूबर 2024 में नायब सिंह सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में तेजी से उभरकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार हरियाणा दौरों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राज्य को विकास, संगठन और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहा है। दिल्ली से तीन दिशाओं से जुड़े हरियाणा का रणनीतिक महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है और केंद्र सरकार प्रदेश के विकास कार्यों तथा संगठनात्मक मजबूती पर विशेष ध्यान दे रही है।

मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को दूसरी बार हरियाणा के दौरे पर जींद पहुंचेंगे। इससे पहले वह 17 अक्टूबर 2024 को पंचकूला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अवधि में कई बार हरियाणा का दौरा कर चुके हैं। दोनों शीर्ष नेताओं की लगातार मौजूदगी को राजनीतिक विश्लेषक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जताए जा रहे विश्वास और हरियाणा की बढ़ती राजनीतिक अहमियत से जोड़कर देख रहे हैं।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संगठन और प्रशासन दोनों स्तरों पर अपनी कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीता है। यही कारण है कि उन्हें केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि अन्य राज्यों के चुनावी अभियानों में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी उन्हें अहम भूमिका दी गई है। इससे पहले दिल्ली, बिहार तथा अन्य राज्यों के चुनावों में भी वह भाजपा के प्रमुख प्रचारकों में शामिल रहे हैं।

17 जुलाई को जींद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर वह जींद-सोनीपत रेलखंड पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक सहित नारनौल, भिवानी और अंबाला से जुड़े अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। माना जा रहा है कि यह दौरा हरियाणा के बुनियादी ढांचे और परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व और कार्यशैली की सार्वजनिक रूप से सराहना की है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद उन्होंने हरियाणा सरकार को सुशासन और अनुभव का प्रभावी संगम बताया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, सैनिकों और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व की प्रशंसा की है। इन दौरों के दौरान उन्होंने औद्योगिक, सहकारिता, पुलिस प्रशिक्षण और आधारभूत संरचना से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। साथ ही राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था की भी सराहना की। अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शांत, सरल और कुशल प्रशासक बताते हुए कहा कि जनता के बीच से निकला नेतृत्व ही शासन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है।

कम्युनिटी सेंटर में गंदगी पर भड़के लोग, सख्त सफाई नियमों की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर

वार्ड-13 स्थित कम्युनिटी सेंटर में कार्यक्रमों के आयोजन के बाद समय पर सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नगर परिषद जीरकपुर इस कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग के लिए करीब 6000 रुपये का शुल्क वसूलती है, लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद परिसर में फैली गंदगी लंबे समय तक नहीं हटाई जाती। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि आयोजनों के बाद कूड़ा-कचरा, डिस्पोजल सामग्री और सब्जियों के छिलके परिसर में बिखरे रहते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल जाती है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय निवासी डॉ. लाभ सिंह, आरपी शर्मा, सुरेंद्र सोंधी, दलबीर सिंह, यशपाल गुप्ता, रमेश धीमान और डॉ. अजय यादव ने इस समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि कम्युनिटी सेंटर के आसपास रहने वाले लोग प्रतिदिन सुबह यहां सैर, योग और व्यायाम के लिए आते हैं, लेकिन कार्यक्रमों के बाद फैली गंदगी और बदबू के कारण उन्हें असुविधा झेलनी पड़ती है। कई बार तो परिसर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वहां रुकना भी मुश्किल हो जाता है।

निवासियों का कहना है कि नियमों के अनुसार कार्यक्रम समाप्त होने के बाद परिसर की सफाई करवाने की जिम्मेदारी आयोजकों की होती है, लेकिन अधिकांश मामलों में इसका पालन नहीं किया जाता। वहीं नगर परिषद की ओर से भी इसकी निगरानी प्रभावी ढंग से नहीं की जाती। लोगों का आरोप है कि लगभग हर आयोजन के बाद उन्हें नगर परिषद में शिकायत दर्ज करानी पड़ती है।

न्यूज ब्रीफ

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसानों का रोष मार्च

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और पंजाब की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के नेतृत्व में पंजाब के विभिन्न जिलों से पहुंचे किसानों ने सेक्टर-34 में धरना दिया। धरने के बाद किसानों ने सेक्टर-34 से मटका चौक तक रोष मार्च निकाला। प्रदर्शन के मद्देनजर पूरे मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि यदि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता लागू होता है तो इसका सबसे अधिक नुकसान किसानों और छोटे व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस समझौते को लागू न करने की मांग की। साथ ही पंजाब सरकार से नई लैंड पूलिंग पॉलिसी तत्काल वापस लेने की भी मांग की। उगराहां ने कहा कि किसान पहले ही इस नीति को अस्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भी चिंता जताते हुए कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा छोटे व्यापारियों और मजदूर वर्ग से भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की।

बारिश से चंडीगढ़ की रफ्तार थमी, सड़कों पर जाम

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। लगातार हो रही बारिश ने शहरवासियों को भीषण गर्मी और उमस से राहत तो दिलाई, लेकिन इसके साथ ही पूरे शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो गई। वीरवार को 34 मिमी बारिश दर्ज होने के बाद शहर के अधिकांश प्रमुख मार्गों और चौकों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सेक्टर-17 से 22 को जोड़ने वाला मार्ग सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां यातायात लगभग ठप हो गया। बापूधाम से सेंट कबीर स्कूल तक वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही। वहीं ट्रांसपोर्ट चौक की ओर जाने वाला मार्ग और पंचकूला-चंडीगढ़ सीमा पर भी दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। कई लोगों को सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना समय लगाकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है।

पंजाब में स्टार्टअप बढ़ावा देने को दो नई पहल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब को स्टार्टअप और नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने दो नई पहल की शुरुआत की। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंजाब इन्वेस्टर सर्कल और स्टार्टअप पंजाब हब- न्यूरॉन 2.0 का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य स्टार्टअप को निवेश, तकनीकी सहयोग, मेंटरशिप और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, एग्रीटेक, मैन्युफैक्चरिंग और डीप-टेक क्षेत्र के 14 स्टार्टअप ने अपने नवाचार और कारोबारी मॉडल निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत किए। साथ ही नेटवर्किंग सत्र आयोजित कर स्टार्टअप को फंडिंग और दीर्घकालिक साझेदारी के अवसर प्रदान किए गए। अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सेक्टर-88 और 89 के पार्कों में 2 .27 करोड़ से बनेंगे आधुनिक ओपन जिम

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली।

ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) शहर के विकसित रिहायशी सेक्टरों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार कर रही है। इसी क्रम में सेक्टर-88 और सेक्टर-89 के पार्कों में आधुनिक ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 2.27 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना पूरी होने के बाद क्षेत्र के लोगों को घर के नजदीक ही आधुनिक आउटडोर फिटनेस सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

अधिकारियों के अनुसार, दोनों सेक्टर तेजी से विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र हैं, जहां बड़ी संख्या में परिवार निवास करते हैं। इन पार्कों में पहले से ही मॉर्निंग वॉक, योग और मनोरंजन के लिए लोग पहुंचते हैं। अब यहां आधुनिक फिटनेस मशीनें लगाए जाने से युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को नियमित व्यायाम के लिए निजी जिम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डिविजनल इंजीनियर अवदीप सिंह ने बताया कि परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

पार्कों में बढ़ेंगी फिटनेस सुविधाएं

गमाडा अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल पार्कों का सौंदर्यीकरण करना नहीं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य और फिटनेस गतिविधियों का केंद्र बनाना भी है। ओपन जिम में ऐसे आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिनका उपयोग विभिन्न आयु वर्ग के लोग आसानी से कर सकेंगे। इन मशीनों के माध्यम से शरीर के अलग-अलग अंगों का व्यायाम किया जा सकेगा, जिससे लोगों को नियमित शारीरिक गतिविधियों के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा। वर्तमान में बड़ी संख्या में लोग सुबह और शाम पार्कों में टहलने, योग करने और व्यायाम के लिए पहुंचते हैं। ओपन जिम की सुविधा मिलने से पार्कों की उपयोगिता और बढ़ेगी तथा फिटनेस के प्रति लोगों की रुचि भी बढ़ने की उम्मीद है।

चंडीगढ़ वारदातों के बाद मोहाली में 24 घंटे विशेष नाकाबंदी

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

चंडीगढ़ और मोहाली में हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं के बाद जिला पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। अपराधियों पर शिकंजा कसने और कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से एसएएस नगर (मोहाली) पुलिस ने पूरे जिले में विशेष नाकाबंदी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिले के प्रमुख प्रवेश और निकास मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, संवेदनशील क्षेत्रों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चौबीसों घंटे पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। इन नाकों पर आने-जाने वाले प्रत्येक वाहन की गहन जांच की जा रही है, जबकि संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर उनकी पहचान भी सत्यापित की जा रही है।

देर रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मोहाली ने स्वयं विभिन्न पुलिस नाकों का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि किसी भी वाहन या व्यक्ति की जांच में लापरवाही न बरती जाए। प्रत्येक वाहन के दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए और संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के दौरान आम नागरिकों के साथ शालीन और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखा जाए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ जनता का पुलिस पर विश्वास भी मजबूत हो।

एसएसपी ने कहा कि एसएएस नगर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी असामाजिक तत्व को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या हेल्पलाइन पर दें। आम जनता का सहयोग अपराध पर प्रभावी नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पीएसपीसीएल मीटर टेंडर रद्द, कोर्ट ने दोबारा प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को बड़ा झटका देते हुए पावर क्वालिटी मीटरों की खरीद और स्थापना के लिए जारी किए गए टेंडर को रद्द कर दिया है। अदालत ने माना कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया गया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निगम को पूरी निविदा प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले को सार्वजनिक खरीद प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह मामला पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। तकनीकी आधार पर टेंडर प्रक्रिया से बाहर की गई एक कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जिस तकनीकी आधार पर उसकी कंपनी को अयोग्य घोषित किया गया, उसी

प्रकार की कमियां बाद में चयनित कंपनी के मीटरों में भी पाई गईं, लेकिन इसके बावजूद उसे टेंडर का लाभ दे दिया गया। इस पूरे मामले को सबसे पहले मीडिया में प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद यह विवाद और गहरा गया।

अदालत में सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी सामने आया कि आईईसी क्लास-ए पावर क्वालिटी मीटरों की सप्लाई और इंस्टॉलेशन से जुड़े टेंडर (एमपीक्यू-246) में कई स्तरों पर नियमों की अनदेखी की गई। आरोप है कि तत्कालीन अधिकारियों और संबंधित समिति ने एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर की अनिवार्य शर्तों में व्यावहारिक रूप से ढील दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि तकनीकी मानकों पर खरे न उतरने के बावजूद चयनित कंपनी को प्रक्रिया में बनाए रखा गया।

जानकारी के अनुसार, टेंडर खोलने की तिथि 28 अप्रैल 2025 निर्धारित थी, लेकिन उससे पहले 4 अप्रैल 2025 को तत्कालीन मुख्य अभियंता (मीटरिंग) इंजीनियर जे.एस. जम्मू ने एक विशेष प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को तत्कालीन निदेशक (जनरेशन) इंजीनियर हरजीत सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने मंजूरी दे दी। इसके तहत टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी कंपनियों को टाइप टेस्ट रिपोर्ट जमा कराने की अनुमति दी गई। आरोप है कि इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ एल-1 कंपनी को मिला, जिससे वह टेंडर प्रक्रिया में बनी रही। मामले में नया मोड़ तब आया जब 8 मई 2025 को गठित डेटा असेसमेंट कमेटी ने मीटरों की तकनीकी जांच शुरू की। समिति में डिप्टी मुख्य अभियंता, सहायक अधीक्षण अभियंता तथा तकनीकी ऑडिट से जुड़े अधिकारी शामिल थे। समिति ने 9 सितंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट में संबंधित मीटरों के संबंध में गंभीर तकनीकी आपत्तियां दर्ज कीं और संकेत दिया कि वे निर्धारित तकनीकी मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरते।

मोहाली सहित चार शहरों के बीच सिटी बस सेवा की मांग तेज

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। शहर और आसपास के क्षेत्रों के बीच बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। कन्फेडरेशन ऑफ ग्रेटर मोहाली रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान के. के. सैनी ने पंजाब सरकार को पत्र भेजकर मोहाली, खरड़, जीरकपुर और डेराबस्सी के बीच जल्द सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि क्षेत्र की लगातार बढ़ती आबादी और बढ़ते शहरी विस्तार को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना समय की आवश्यकता बन गया है।

◆ निजी वाहनों की निर्भरता घटाने को सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग

पत्र में बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में मोहाली के साथ-साथ खरड़, जीरकपुर और डेराबस्सी में बड़ी संख्या में नई आवासीय कॉलोनियां विकसित हुई हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोग प्रतिदिन नौकरी, शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं। पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण अधिकांश लोगों को निजी वाहनों, टैक्सी या अन्य महंगे साधनों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उनकी यात्रा लागत भी बढ़ जाती है। के. के. सैनी ने कहा कि यदि इन शहरों के बीच नियमित सिटी बस सेवा शुरू की जाती है तो लोगों को सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा।

92.98 करोड़ के तीन शैक्षणिक भूखंडों की ई-नीलामी करेगा गमाडा

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने और आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के उद्देश्य से शहर के तीन प्रमुख शैक्षणिक भूखंडों की ई-नीलामी करने का निर्णय लिया है। इन तीनों भूखंडों की कुल आरक्षित कीमत 92.98 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। गमाडा का मानना है कि इस पहल से मोहाली में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधाओं का विस्तार होगा और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

गमाडा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह ई-नीलामी के-12 और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना के लिए आरक्षित भूखंडों के आवंटन हेतु आयोजित की जा रही है। ऑनलाइन बोली प्रक्रिया 10 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे शुरू होगी और 10 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी। इच्छुक शैक्षणिक संस्थान और पात्र आवेदक निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन और वित्तीय बोली जमा कर सकेंगे।

नीलामी के लिए तीन अलग-अलग स्थानों पर स्थित भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें सेक्टर-77 में 2.50 एकड़ का शैक्षणिक भूखंड शामिल है, जिसकी आरक्षित कीमत 23.74 करोड़ रुपये रखी गई है। वहीं सेक्टर-79 में 2.00 एकड़ का भूखंड 20.71 करोड़ रुपये की आरक्षित कीमत पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा आईटी सिटी के सेक्टर-66 बीटा में स्थित 4.10 एकड़ का सबसे बड़ा भूखंड 48.53 करोड़ रुपये की आरक्षित कीमत के साथ नीलामी के लिए रखा गया है। यह भूखंड क्षेत्रफल और मूल्य, दोनों दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गामाडा अधिकारियों के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया 'के-12 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए शैक्षणिक प्लॉट आवंटन नीति-2025' के तहत संचालित की जाएगी। नीलामी में दो-लिफाफा प्रणाली अपनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत पहले चरण में आवेदकों की तकनीकी पात्रता की जांच की जाएगी। केवल पात्र घोषित किए गए संस्थानों की वित्तीय बोलियां ही दूसरे चरण में खोली जाएंगी।

सात महीनों में 54 गैंगस्टर गिरफ्तार, नेटवर्क ध्वस्त

एसएसओसी और एजीटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कई कुख्यात गिरोहों के सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, हथियार भी बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए मोहाली पुलिस, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने वर्ष 2026 के पहले सात महीनों में बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त अभियानों के दौरान 54 से अधिक खतरनाक अपराधियों और गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में कई कुख्यात गिरोहों के सक्रिय सदस्य और सहयोगी शामिल हैं, जिनका संबंध डोनी बल, लक्की पटियाल, लॉरेंस बिश्नोई, बंबीहा, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और गोल्डी ढिल्लों गिरोह से बताया गया है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधी पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ तथा अन्य राज्यों में हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती, फायरिंग, आर्म्स एक्ट के मामलों, वाहन लूट और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी जैसी गंभीर वारदातों में शामिल रहे हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अत्याधुनिक हथियार, कारतूस, विदेशी मुद्रा, लग्जरी वाहन, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है।

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष की शुरुआत से ही संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। पूछताछ और विभिन्न राज्यों की जांच एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं में सामने आया कि ये गिरोह हब एंड स्पोक मॉडल के तहत संचालित हो रहे थे। विदेशों में बैठे हैंडलर कनाडा, अमेरिका, थाईलैंड, मलेशिया और आर्मेनिया जैसे देशों से सोशल मीडिया, इंटरनेट कॉलिंग और एन्क्रिप्टेड एप के माध्यम से अपने गुर्गों को निर्देश भेजते थे। उनके इशारे पर रंगदारी वसूली, सुपारी लेकर हत्या, जमीनों पर अवैध कब्जे छुड़वाने और हाईवे पर वाहन लूट जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता था।

वर्ष 2026 के दौरान मोहाली में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच कई मुठभेड़ भी हुईं। इन अभियानों में कुछ वांछित अपराधी घायल हुए, जबकि कई ने पुलिस की घेराबंदी के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लगातार चलाए जा रहे अभियानों से कई गैंगों का नेटवर्क कमजोर पड़ा है। साथ ही उनके आर्थिक स्रोतों और आपराधिक गतिविधियों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, ताकि प्रदेश में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

विदेशी हैंडलरों पर पुलिस का शिकंजा

जांच एजेंसियों के अनुसार पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय कई गैंगस्टर गिरोहों का संचालन विदेश में बैठे हैंडलरों द्वारा किया जा रहा था। कनाडा, अमेरिका, थाईलैंड, मलेशिया और आर्मेनिया जैसे देशों में बैठे संचालक सोशल मीडिया, इंटरनेट कॉलिंग और एन्क्रिप्टेड संचार माध्यमों के जरिए स्थानीय अपराधियों को निर्देश दे रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रंगदारी वसूली, अवैध हथियारों की आपूर्ति, सुपारी लेकर हत्या की साजिश और आर्थिक लेन-देन का संचालन भी विदेश से किया जा रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क, बंबीहा ग्रुप, शहजाद भट्टी गिरोह तथा लक्की पटियाल और डोनी बल से जुड़े स्थानीय मॉड्यूल पर विशेष फोकस रखते हुए कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की हैं। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और बिल्डरों से रंगदारी मांगने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया, अवैध हथियारों की खेप बरामद हुई, हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में वांछित आरोपियों को पकड़ा गया।

कांग्रेस पार्षद पर गरीब मजदूर से प्लॉट धोखाधड़ी का केस दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

महानगर में प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर कथित धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। मुंडियां कलां के कांग्रेस पार्षद गुरमीत सिंह के खिलाफ एक प्रवासी मजदूर से लाखों रुपये की कथित ठगी और फर्जी प्लॉट डीलिंग के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि पार्षद ने जिस प्लॉट का सौदा किया, उसका कानूनी मालिकाना हक उनके पास नहीं था। पुलिस ने शिकायत और जांच के आधार पर कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला मुंडियां कलां निवासी मोती लाल की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने परिवार के लिए घर बनाने के उद्देश्य से एक प्लॉट खरीदना चाहता था। इसी दौरान उसके चाचा किशन पाल के माध्यम से उसकी मुलाकात कांग्रेस पार्षद गुरमीत सिंह से हुई। किशन पाल ने पहले भी पार्षद के ताजपुर रोड स्थित कार्यालय के माध्यम से एक प्लॉट खरीदा था।

शिकायत के मुताबिक, पार्षद गुरमीत सिंह ने मोती लाल को ताजपुर रोड स्थित अपनी कथित कॉलोनी दिखाई, जहां उसे 70 वर्ग गज का प्लॉट नंबर 224 पसंद आया। दोनों पक्षों के बीच 5 फरवरी 2023 को 6400 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से कुल 4 लाख 48 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। आरोप है कि सौदे के समय मोती लाल ने गवाहों की मौजूदगी में एक लाख रुपये बतौर बयाना दिए। इसके बाद बाकी रकम 30 मासिक किश्तों में देने की बात तय हुई।

मोती लाल के अनुसार, उसने अपनी मेहनत की कमाई से अलग-अलग समय पर पार्षद को कुल 2 लाख 27 हजार 600 रुपये का भुगतान कर दिया। जब उसने वर्ष 2024 में बाकी रकम की व्यवस्था कर रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा तो आरोप है कि पार्षद ने रजिस्ट्री करने में टालमटोल शुरू कर दी और उसे लगातार बहाने बनाकर टरकाता रहा।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने जमीन के रिकॉर्ड की जांच करवाई। जांच में सामने आया कि जिस जमीन को पार्षद अपनी कॉलोनी का हिस्सा बताकर बेच रहे थे, उसके वास्तविक मालिक कोई अन्य लोग हैं। शिकायत के अनुसार, जमीन के असली मालिक इंदरजीत सिंह और उनकी पत्नी सुखजिंदर कौर हैं। आरोप है कि पार्षद का पहले जमीन मालिकों के साथ सौदा हुआ था, लेकिन शर्तें पूरी न होने और भुगतान संबंधी विवाद के कारण वह सौदा 17 अप्रैल 2020 को रद्द हो चुका था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद पार्षद ने खुद को जमीन का मालिक बताकर उसके साथ प्लॉट का सौदा किया और पैसे ले लिए।

फर्जी प्लॉट सौदे का आरोप

पुलिस ने बताया कि मामले से जुड़े दस्तावेजों, जमीन रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों की गहन जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शिकायतकर्ता के आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच जारी है।

पंजाब स्विमिंग चैंपियनशिप में 200 खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा

भारतेन्दु संवाददाता, फिरोजपुर। जिला स्विमिंग एसोसिएशन फिरोजपुर की ओर से पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन के मार्गदर्शन में 37वीं पंजाब सब-जूनियर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप-2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह दो दिवसीय प्रतियोगिता 17 और 18 जुलाई को दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिरोजपुर के स्विमिंग पूल में आयोजित होगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ 17 जुलाई को दोपहर के समय किया जाएगा।

पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन के मानद महासचिव अनुज शर्मा ने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पंजाब के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में युवा तैराक हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में करीब 140 लड़के और 60 लड़कियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। खिलाड़ियों को उनकी जन्म तिथि के आधार पर दो आयु वर्गों में शामिल किया जाएगा। इसमें वर्ष 2012-13 और 2014-15 में जन्मे खिलाड़ी भाग लेंगे।

◆फिरोजपुर में तैराकी प्रतियोगिता

उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों के लिए कुल 42 व्यक्तिगत स्पर्धाओं और 8 रिले स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। इन मुकाबलों में तैराक अपनी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान कुल 74 पदकों के लिए खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए आयोजकों की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं। प्रतियोगिता के संचालन और तकनीकी व्यवस्था की जिम्मेदारी 30 योग्य तकनीकी अधिकारियों को सौंपी जाएगी। ये अधिकारी नियमों के अनुसार मुकाबलों का संचालन करेंगे और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे।

ऑपरेशन प्रहार 3.0 से 200 बदमाश गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

अपराध और नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

महानगर में बढ़ते अपराध और नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट ने विशेष अभियान 'ऑपरेशन प्रहार 3.0' के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में एक साथ छापेमारी करते हुए करीब 200 आरोपियों और संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद अपराधियों और नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभियान के दौरान कई विशेष टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने महानगर के अलग-अलग क्षेत्रों, संवेदनशील इलाकों, नशा तस्करी से जुड़े स्थानों और संदिग्ध ठिकानों पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार, पिस्तौल, नशीली गोलियां और हेरोइन समेत अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद किया है।

डीसीपी हरपाल सिंह ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से पूरे शहर को अलग-अलग सेक्टरों में बांटकर एक साथ अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य समाज विरोधी तत्वों, अपराधियों और नशा कारोबार से जुड़े लोगों पर प्रभावी शिकंजा कसना था। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया और कई मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान में केवल छोटे अपराधियों पर ही कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि गंभीर मामलों में वांछित कई बदमाशों और फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर कई आरोपियों को उनके ठिकानों से पकड़ा।

डीसीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब और पुलिस कमिश्नर के निर्देशों के अनुसार शहर को अपराध और नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह के अभियान जारी रहेंगे।

अमरनाथ यात्रा में ऑक्सीजन कमी से कारोबारी की हुई मौत

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

श्री अमरनाथ यात्रा पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गए लुधियाना के एक होजरी कारोबारी की यात्रा के दौरान दुखद मौत हो गई। मृतक की पहचान सेक्टर-38, चंडीगढ़ रोड निवासी अंकित मल्होत्रा (38) के रूप में हुई है। अंकित वेट गंज क्षेत्र में होजरी कारोबार से जुड़े हुए थे। उनके असामयिक निधन से परिवार, रिश्तेदारों और लुधियाना के व्यापारिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

परिजनों के अनुसार, अंकित मल्होत्रा श्रद्धालुओं के एक जत्थे के साथ श्री अमरनाथ यात्रा पर गए थे। बुधवार को उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और दर्शन के बाद बालटाल बेस कैंप की ओर लौट रहे थे। वापसी के दौरान ऊंचाई वाले दुर्गम इलाके में अचानक उनका ऑक्सीजन स्तर तेजी से गिरने लगा। इसके कारण उन्हें सांस लेने में गंभीर परेशानी हुई। साथ मौजूद श्रद्धालुओं ने बिना देर किए उन्हें बालटाल बेस कैंप पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया। हालांकि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एंबुलेंस से श्रीनगर के एक निजी अस्पताल भेजा गया।

अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार शुरू किया और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए। लेकिन वीरवार सुबह इलाज के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई।

पंजाबभर में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान हुआ तेज

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने का कार्य तेज़ी से जारी है। घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया 24 जुलाई तक चलेगी। इस अभियान को अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाने के लिए 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक दो दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में मतदाता अपने गणना फॉर्म भरने के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकेंगे।

मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब अनिंदिता मित्रा ने प्रदेश के सभी पात्र मतदाताओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपना गणना फॉर्म नहीं भरा है, वे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करें या विशेष शिविर के दौरान निकटतम मतदान केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल होना प्रत्येक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि 3 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी पात्र नागरिक समय रहते अपने विवरण का सत्यापन और आवश्यक संशोधन करवा लें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ पूरे समय उपस्थित रहेंगे और मतदाताओं को फॉर्म भरने, दस्तावेजों की जांच तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करेंगे।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और निर्धारित समय के भीतर अपना गणना फॉर्म जमा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में योगदान दें। चुनाव विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे और सभी नागरिक आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

इसके अलावा चुनाव विभाग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने अथवा विवरण में आवश्यक संशोधन से संबंधित प्रक्रिया भी नियमानुसार पूरी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जिन मतदाताओं के पते, नाम, आयु या अन्य व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन हुआ है, वे संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने बूथ स्तर अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

पीएसपीसीएल कर्मचारियों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

भारतेन्दु संवाददाता, पटियाला

जत्थेबंदी इम्प्लाइज फेडरेशन चाहल ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) में कथित भ्रष्टाचार और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संगठन ने बिजली निगम में मोबाइल खरीद, टेंडर प्रक्रिया और अन्य स्तरों पर हुए कथित घोटालों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग उठाई है।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुरवेल सिंह बल्लपुरिया और प्रवक्ता मनजीत सिंह चाहल ने बताया कि 16 कर्मचारी संगठनों के संयुक्त आह्वान को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार कर्मचारियों की मांगों के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है और लगातार टालमटोल की नीति अपना रही है।

उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते (डीए) के मामले में भी सरकार उचित निर्णय नहीं ले रही है। बिजली निगम में कर्मचारियों को पहले पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता मिलता रहा है, लेकिन अब उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। संगठन नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी के खिलाफ संघर्ष को और तेज किया जाएगा। बैठक में फैसला लिया गया कि 14 जुलाई को पंजाब के सभी सब-डिवीजनों, हाइडल कार्यालयों और थर्मल प्लांटों में प्रदर्शन कर सरकार और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी।

न्यूज ब्रीफ

टांडा में बंदरों का आतंक, स्कूल में मची भगदड़

भारतेन्दु संवाददाता, टांडा। होशियारपुर जिले के टांडा उड़मुड़ और अहियापुर इलाकों में पिछले कई महीनों से बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। सोमवार सुबह एक बंदर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (गर्ल्स) में घुस गया और इमारत में इधर-उधर कूदने लगा। बंदर को देखकर छात्राओं में भगदड़ मच गई। स्कूल स्टाफ ने तुरंत छात्राओं को सतर्क करते हुए उन्हें कमरों में रहने की सलाह दी। स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले एक महीने में बंदर शिमला पहाड़ी क्षेत्र, बिजली घर कॉलोनी और कई रिहायशी इलाकों में घुसकर लोगों को घायल कर चुके हैं। बंदर घरों की छतों पर रखे सामान, पानी की टंकियों और बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके हमलों में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल टांडा में उपचार दिया गया। लोगों ने प्रशासन से बंदरों को पकड़ने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि बंदरों के डर से बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।

सीमा पार नशा नेटवर्क के दो तस्कर गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से संचालित नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8.378 किलोग्राम हेरोइन और 2 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। बरामद हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी सीमा पार बैठे तस्करों के निर्देश पर काम कर रहे थे। उनका काम पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से हेरोइन की खेप एकत्र कर आगे सप्लाई करना था। इस मामले में अमृतसर के थाना छेहरटा और थाना इस्लामाबाद में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। जांच के दौरान तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और सहयोगियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

फ्रिज खराब होने से ब्लड बैंक की 25 यूनिट हुईं नष्ट

भारतेन्दु संवाददाता, गुरदासपुर

सिविल अस्पताल गुरदासपुर के ब्लड बैंक में रक्त की कुछ यूनिट खराब होने का मामला सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं, जिनमें 200 से 250 यूनिट रक्त खराब होने की बात कही जा रही थी। हालांकि जांच के बाद सामने आया कि ब्लड बैंक में केवल 25 यूनिट रक्त ही खराब हुआ था, जिसे मरीजों के लिए इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं था।

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में रखी रक्त की बोतलें अस्पताल परिसर में कूड़े के पास दिखाई दी थीं। इसके बाद मामला चर्चा में आ गया और लोगों में चिंता बढ़ गई। बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए जाने लगे। मामले की पड़ताल के बाद स्पष्ट हुआ कि खराब हुई रक्त यूनिटों की संख्या केवल 25 थी।

ब्लड बैंक अधिकारी डॉ. पूजा खोसला ने बताया कि ब्लड बैंक का एक फ्रिज खराब हो गया था। बाहर से फ्रिज का तापमान सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर का तापमान निर्धारित स्तर पर नहीं था। इसके कारण उसमें रखे कुछ रक्त यूनिट प्रभावित हो गए। जैसे ही रक्त के खराब होने की जानकारी मिली, तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के निर्देश के बाद खराब हुई 25 यूनिट रक्त को नियमानुसार नष्ट कर दिया गया। डॉ. खोसला ने सोशल मीडिया पर चल रही 200 या 250 यूनिट रक्त खराब होने की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जिस रात फ्रिज में तकनीकी खराबी आई थी, उस समय ब्लड बैंक में कुल करीब 50 यूनिट रक्त ही उपलब्ध था।

कनाडा पीआर दिलाने का झांसा देकर शादी के बाद लाखों की ठगी का आरोप

विदेश भेजने के नाम पर परिवार से धोखा

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

मैरिज फ्रॉड में लुधियाना के परिवार ने दर्ज कराया केस

विदेश भेजने और कनाडा की स्थायी नागरिकता दिलाने का झांसा देकर कथित तौर पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का मामला सामने आया है। आरोप है कि गिरोह ने शादी के माध्यम से एक युवक और उसके परिवार को अपने जाल में फंसाया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि बेटे के भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद में उन्होंने लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन शादी के बाद हालात पूरी तरह बदल गए।

जानकारी के अनुसार, लुधियाना निवासी गुरजीत सिंह ने थाना मेहरबान पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उनके बेटे का विवाह गुरप्रीत कौर नामक युवती से इस आश्वासन के साथ करवाया गया था कि शादी के बाद वह उनके बेटे को कनाडा बुलाकर वहां की स्थायी नागरिकता दिलाने में मदद करेगी। परिवार ने युवती की विदेश में पढ़ाई, रहने की व्यवस्था, हवाई यात्रा और अन्य खर्चों पर बड़ी रकम खर्च की।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कनाडा पहुंचने के बाद युवती के व्यवहार में बदलाव आ गया। उसने कथित तौर पर अपने पति को कनाडा बुलाने में टाल-मटोल शुरू कर दी और उसके साथ रहने से भी इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि बाद में उन्हें पता चला कि युवती ने कनाडा में किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बना लिए हैं।

गुरजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि जब उनके बेटे ने इस मामले का विरोध किया तो युवती और उसके परिवार की ओर से उसके खिलाफ कथित रूप से झूठी शिकायतें दर्ज करवाई गईं। इसके अलावा तलाक की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे को कनाडा में धमकियां दी गईं, जिससे पूरा परिवार मानसिक तनाव में है।

पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाना मेहरबान पुलिस ने आरोपी युवती और उसके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

फर्जी जीएसटी बिलिंग घोटाले में कारोबारी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़।

पंजाब राज्य कर विभाग ने 55.35 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी बिलिंग घोटाले का पर्दाफाश करते हुए जालंधर स्थित एक फर्म के मालिक को गिरफ्तार किया है। विभाग की कार्रवाई से करीब 8.35 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के जरिए किए जा रहे गलत आईजीएसटी रिफंड दावों पर रोक लगाई गई है। विभाग के अनुसार, खुफिया सूचना के आधार पर जांच के दौरान जालंधर स्थित मैसर्स रैमसंस कॉर्पोरेशन के मालिक भूपिंदर शर्मा को पंजाब जीएसटी अधिनियम-2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि फर्म बिना वास्तविक माल आपूर्ति के फर्जी जीएसटी चालान जारी कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि फर्म ने करीब 55.35 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग कर 8.35 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी हासिल किया और इसे अन्य फर्मों को स्थानांतरित किया। विभाग ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर 9 जुलाई को

मकोरा नदी में ओवरलोड नाव पलटी, यात्री सुरक्षित

भारतेन्दु संवाददाता, दीनानगर

रावी नदी के मकोरा नदी क्षेत्र के दूसरी तरफ रहने वाले सात गांवों के लोगों के लिए आवागमन की समस्या एक बार फिर सामने आ गई है। कुछ दिन पहले नदी पर बनाया गया प्लटून पुल का एक हिस्सा बह जाने के बाद पुल पर यातायात पूरी तरह बंद हो गया था। इसके बाद प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर बचा हुआ प्लटून पुल भी हटा दिया था।

पुल हटाए जाने के बाद ग्रामीणों को नदी पार करने के लिए बड़ी नाव और छोटी नाव (मशुआ) का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी दौरान शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जानकारी के अनुसार, छोटी नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए, जिसके कारण नदी किनारे पहुंचते समय अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। नाव में सवार सभी लोग नदी में गिर गए।

घटना के बाद मौके पर मौजूद नाविकों और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राहत की बात यह रही कि नदी में पानी का स्तर कम था, जिससे किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई। नाविक नछत्तर सिंह ने बताया कि नाव अचानक किनारे के पास पलट गई थी, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि छोटी नाव में केवल पांच से सात लोगों के बैठने की क्षमता है, लेकिन नदी पार करने की जल्दी में लोग अधिक संख्या में सवार हो जाते हैं।

आपदा मिट्टी की बोरियां और क्रेन से टूटा बांध अस्थायी रूप से जोड़ा गया

नहर का बांध टूटने से कॉलोनियों में भरा पानी

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर

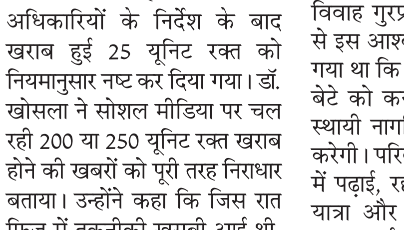

शहर के गदईपुर इलाके में नहर का बांध टूटने से आसपास की कॉलोनियों में पानी भर गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। समय रहते कार्रवाई होने से पानी रिहायशी मकानों के अंदर नहीं पहुंचा और बड़ा नुकसान टल गया।

जानकारी के अनुसार, पंजाब के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण नहरों का जलस्तर काफी बढ़ गया था। इसी दबाव के चलते देर रात गदईपुर क्षेत्र में दो स्थानों पर नहर का बांध टूट गया। पानी तेजी से आसपास की कॉलोनियों की ओर बढ़ने लगा, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय निवासियों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी और राहत कार्य में सहयोग करना शुरू कर दिया। प्रशासन ने पानी के बहाव को रोकने के लिए मिट्टी से भरी बोरियां लगाकर अस्थायी बांध बनाया। साथ ही क्रेन मशीनों की सहायता से टूटे हुए हिस्सों में मिट्टी डालकर मरम्मत का कार्य किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया।

स्थानीय निवासी देसराज ने बताया कि रात करीब 11 बजे बांध टूटने की जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके के लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्य शुरू किया। वहीं, सलेमपुर निवासी और क्रेन मशीन संचालक मोनू ने बताया कि सूचना मिलते ही वह मशीन लेकर मौके पर पहुंचे और दोनों स्थानों पर मिट्टी डालकर नया अस्थायी बांध तैयार किया गया, जिससे पानी का बहाव रोकने में सफलता मिली।

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक पंजाब के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन ने नहरों और निचले इलाकों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने की अपील की गई है।

प्रशासन ने एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और सिंचाई विभाग की टीमों को चौबीसों घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से की स्थायी मरम्मत का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।

वैष्णो देवी जाने हेतु वॉल्वो बस सेवा शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजाब रोडवेज ने बड़ी सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। विभाग पहली बार लुधियाना और जालंधर से जम्मू-कटरा के लिए सुपरफास्ट एसी वॉल्वो बस सेवा शुरू करेगा। यह सेवा सोमवार से नियमित रूप से प्रतिदिन संचालित होगी। इससे श्रद्धालुओं को आरामदायक, सुरक्षित और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा।

रोडवेज अधिकारियों के अनुसार, नई बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची और निजी बस संचालकों के अधिक किराए से राहत मिलेगी। विशेष रूप से गर्मी की छुट्टियों, नवरात्र और अन्य पर्वों के दौरान मां वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे समय में सीटों की कमी और महंगे किराए के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। नई सेवा इन समस्याओं को काफी हद तक कम करेगी।

जानकारी के अनुसार, सुपरफास्ट एसी वॉल्वो बस लुधियाना से रवाना होकर जालंधर बस स्टैंड से होते हुए जम्मू और कटरा पहुंचेगी। विभाग का कहना है कि सरकारी किराए पर उपलब्ध यह लग्जरी बस सेवा यात्रियों को बेहतर सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर का अनुभव देगी। इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक बनेगी।

पंजाब रोडवेज ने इस सेवा का किराया भी तय कर दिया है। जालंधर से जम्मू तक यात्रा के लिए 765 रुपये, जालंधर से कटरा के लिए 945 रुपये और लुधियाना से कटरा तक सफर के लिए 1145 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में यात्रियों की संख्या और मांग के आधार पर इस मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। विभाग ने श्रद्धालुओं से इस नई सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है पंजाब रोडवेज की इस पहल से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य के सार्वजनिक परिवहन को भी मजबूती मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों के संचालन की नियमित निगरानी भी की जाएगी। रोडवेज विभाग ने बताया कि जम्मू-कटरा धार्मिक यात्रा का प्रमुख मार्ग है और हर साल पंजाब सहित आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।

डिजिटल सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता

आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। शासन-प्रशासन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, रक्षा और व्यापार, लगभग हर क्षेत्र डिजिटल तकनीक पर निर्भर हो चुका है।

ऐसे में डिजिटल सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे-सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुका है। जिस प्रकार सीमाओं की रक्षा के लिए सेना और आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस बल आवश्यक है, उसी प्रकार साइबर हमलों से देश की रक्षा के लिए सशक्त डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य हो गई है।

डिजिटल प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता के साथ-साथ साइबर अपराधों और साइबर हमलों का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। सरकारी वेबसाइटों की हैकिंग, डाटा चोरी, बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी ऐप्स, रैनसमवेयर अटैक और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाना-ये सभी गतिविधियां न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि देश की सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी चुनौती देती हैं। कई बार तो साइबर हमलों के जरिए संवेदनशील सैन्य और रणनीतिक जानकारियां चुराने का प्रयास किया जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत घातक हो सकता है।

डिजिटल सुरक्षा का एक बड़ा पहलू नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा से भी जुड़ा है। आधार, बैंक खाते, मोबाइल नंबर, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और अन्य निजी डाटा यदि असुरक्षित हो जाएं, तो आम नागरिक साइबर ठगी और पहचान की चोरी का शिकार बन सकता है। जब नागरिकों का डिजिटल तंत्र पर भरोसा कमजोर पड़ता है, तो डिजिटल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी अभियानों की सफलता भी प्रभावित होती है। इसलिए मजबूत साइबर कानून, डाटा संरक्षण नीतियां और प्रभावी निगरानी तंत्र समय की मांग बन गए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, साइबर सुरक्षा से जुड़े कानूनों को और अधिक प्रभावी एवं कठोर बनाया जाना चाहिए, ताकि साइबर अपराधियों को त्वरित और सख्त दंड मिल सके।

दूसरा, सरकारी और निजी संस्थानों में साइबर सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य किया जाना चाहिए। तीसरा, अत्याधुनिक तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन का उपयोग कर, साइबर खतरों की पहचान और रोकथाम की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए।

डिजिटल साक्षरता आज केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम आधार बन चुकी है। जब तक आम नागरिक साइबर खतरों, फर्जी लिंक, ओटीपी धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक डिजिटल सुरक्षा अधूरी ही रहेगी। साइबर अपराधों का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर नागरिकों की निजी सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सौहार्द पर पड़ता है।

इस चुनौती से निपटने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता को शामिल करना आवश्यक है। इसके साथ ही सरकारी स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग समान रूप से डिजिटल खतरों को समझ सकें और उनसे बचाव कर सकें। डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग समय की मांग है।

केशव शर्मा 'रसिक'
कोटला, घुमारवीं, बिलासपुर

यह भी स्पष्ट हो चुका है कि भविष्य की लड़ाइयां केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ी जाएंगी। साइबर हमले, डेटा चोरी और डिजिटल दुष्प्रचार किसी भी देश की संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है।

आज भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में सुरक्षित डिजिटल वातावरण केवल सरकार की ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। सरकार को आधुनिक साइबर सुरक्षा ढांचे को और मजबूत बनाने के साथ-साथ अनुसंधान तथा स्वदेशी साइबर तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। वहीं नागरिकों को भी सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करने नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करने और किसी भी संदिग्ध संदेश या लिंक से सतर्क रहने की आदत विकसित करनी चाहिए। जब सरकार निजी क्षेत्र शैक्षणिक संस्थान और आम नागरिक मिलकर डिजिटल सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे तभी आत्मनिर्भर डिजिटल भारत का सपना सुरक्षित और सफल रूप से साकार हो सकेगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में छात्रों का बढ़ता मानसिक तनाव और शिक्षा की नई चुनौती

'कितना बदल गया जमाना' यह वाक्य अब केवल एक साधारण टिप्पणी नहीं रहा, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, छात्र जीवन और सामाजिक सोच पर खड़ा एक गहरा प्रश्न बन चुका है।

आज के विद्यार्थियों की आंखों में सपनों के साथ-साथ थकान है, उनके कंधों पर बस्तों से ज्यादा अपेक्षाओं का बोझ है और मन में सीखने से अधिक खुद को साबित करने की बेचैनी। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि हम शिक्षा को किस दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे छात्र जीवन की शुरुआत सादगी से होती थी। स्लेट, खड़िया और लकड़ी की पटरी ही हमारी दुनिया थी। स्लेट की बत्ती को जीभ से चाटना, मोरपंख किताब में रखना या पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर परीक्षा का तनाव कम करना-आज ये बातें हास्यास्पद लग सकती हैं, लेकिन उस मासूम विश्वास में सीखने का आनंद छिपा था। संसाधन कम थे, पर भरोसा बहुत था।

आज का छात्र स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट बोर्ड और अनंत ऑनलाइन सामग्री के बीच घिरा है। जानकारी की कमी नहीं, बल्कि इतनी अधिकता है कि सही दिशा ही खोती जा रही है। तकनीक ने शिक्षा को तेज और सुलभ बनाया है, लेकिन क्या उसने उसे संवेदनशील और मानवीय भी बनाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सीखने की रफ़्तार बढ़ा दी, लेकिन समझने की क्षमता घटा दी?

भटूरे में ईनो डालकर उसे फुलाना और फिर उसी ईनो से पेट की समस्या ठीक करना केवल खानपान का व्यंग्य नहीं, बल्कि हमारी पूरी आधुनिक जीवनशैली का प्रतीक है। पहले समस्या रची जाती है, फिर समाधान परोसा जाता है, और जब वही समाधान नई समस्या पैदा करता है तो उस पर नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी जाती है। यही स्थिति शिक्षा व्यवस्था में भी दिखती है। बच्चों पर भारी पाठ्यक्रम, अंकों की होड़ और रैंकिंग का दबाव डाल दिया जाता है, फिर उसी से पैदा हुए तनाव के लिए काउंसलिंग और वेलनेस प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। यह अंतहीन चक्र हमारी सामूहिक विफलता की ओर इशारा करता है। पहले पढ़ाई जीवन का स्वाभाविक हिस्सा थी, कोई थोप दी गई शर्त नहीं। माता-पिता को न ट्यूशन की चिंता थी, न कोचिंग की दौड़। शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाते थे, संस्कार भी देते थे। आज के विद्यार्थी पिटते नहीं, पर टूटते जरूर हैं-तुलना, रैंक, सोशल मीडिया और 'टॉपर बनो' की सोच से। किताबों से रिश्ता था, उन्हें छूने और पलटने का आनंद था। आज ज्ञान स्क्रीन पर है, लेकिन धैर्य और जिज्ञासा संकट में हैं।

रजनीश रांगड़ा
प्रधानाचार्य, स्वर्ण जयंती
राजकीय (उत्कृष्ट) वरिष्ठ माध्यमिक
पाठशाला, टौणी देवी

स्कूल का रास्ता भी सीखने का हिस्सा था। साइकिल पर दोस्तों के साथ जाना, नियम तोड़ना, लेकिन दोस्ती निभाना—ये सब जीवन का पाठ थे। आज बच्चे गाड़ियों में अकेले, हेडफोन लगाए चलते हैं। सुविधाएं बढ़ी हैं, पर संवाद घटा है। शिक्षक-छात्र संबंध भी बदल गया है। शिक्षक अब मार्गदर्शक से अधिक 'रिजल्ट' से आंके जाते हैं और छात्र 'विद्यार्थी' से अधिक 'स्कोर' बनते जा रहे हैं। माता-पिता भी इस दबाव से अछूते नहीं हैं। पहले वे अच्छे इंसान बनने की उम्मीद रखते थे, आज करियर पैकेज और भविष्य की असुरक्षा में उलझे हैं। नतीजा यह है कि छात्र कम उम्र में ही थक जाता है। एक असफलता आज कई बच्चों को भीतर तक तोड़ देती है।

शिक्षा को फिर से मानवीय बनाना होगा। छात्र को केवल प्रतियोगी नहीं, जिज्ञासु बनाना होगा। तकनीक को साधन बनाना होगा, लक्ष्य नहीं। स्कूल को ऐसा स्थान बनाना होगा जहां बच्चा डर से नहीं, विश्वास से सीखे।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

> डूबते को बचाना ही अच्छे इंसान का कर्तव्य होता है।
> – डॉ. मनोज चतुर्वेदी

संपादकीय

अनियोजित विकास की बाढ़ में बहते शहर

इस वर्ष का मानसून केवल बारिश लेकर नहीं आया, बल्कि उसने देश के विकास मॉडल, शहरी नियोजन और पर्यावरणीय दृष्टिकोण की कमजोरियों को भी उजागर कर दिया है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, केरल, कर्नाटक और देश के अनेक हिस्सों में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़, जलभराव, भूस्खलन और आधारभूत ढांचे को हुए नुकसान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समस्या केवल अत्यधिक वर्षा की नहीं है। वास्तविक संकट उस विकास मॉडल का है जिसमें प्रकृति के लिए पर्याप्त स्थान नहीं छोड़ा गया। हर वर्ष मानसून के दौरान सामने आने वाली तस्वीरें अब सामान्य नहीं रहीं बल्कि वे हमारी योजनाओं और नीतियों की असफलता का आईना बन चुकी हैं। बारिश प्रकृति का सामान्य चक्र है। भारत जैसे मानसूनी देश में हर वर्ष अच्छी वर्षा होना कृषि, जल संसाधनों और पर्यावरण के लिए आवश्यक भी है। लेकिन जब यही वर्षा शहरों को डुबो देती है, सड़कों को नदी में बदल देती है, पुल बह जाते हैं, पहाड़ टूटने लगते हैं और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या केवल मौसम नहीं बल्कि हमारी तैयारी और विकास की दिशा है। यदि किसी शहर में कुछ घंटों की बारिश के बाद यातायात पूरी तरह ठप हो जाए, अस्पतालों में पानी भर जाए, बिजली व्यवस्था बाधित हो जाए और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाए, तो इसे केवल प्राकृतिक आपदा नहीं कहा जा सकता।

देश के अधिकांश शहरों का विस्तार बिना वैज्ञानिक योजना के हुआ है। जनसंख्या बढ़ी, नए आवास बने, ऊंची इमारतें खड़ी हुईं और कंक्रीट का विस्तार लगातार होता गया, लेकिन जल निकासी व्यवस्था उसी अनुपात में विकसित नहीं हुई। कई स्थानों पर पुराने नालों को पाटकर सड़कें बना दी गईं, तालाबों और झीलों पर कॉलोनियां बस गईं तथा प्राकृतिक जल प्रवाह के मार्गों पर निर्माण कार्य कर दिए गए। परिणाम यह हुआ कि वर्षा का पानी अपने पारंपरिक रास्तों से बहने के बजाय आबादी वाले क्षेत्रों में भरने लगा। प्रकृति अपने मार्ग स्वयं बनाती है और जब उसके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तब वह बाढ़ और जलभराव के रूप में अपना अस्तित्व दर्ज कराती है। हिमालयी राज्यों की स्थिति और भी चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण, पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई, नदी किनारे होटल और भवन निर्माण तथा सड़कों के चौड़ीकरण में पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी ने जोखिम को कई गुना बढ़ा दिया है। भारी वर्षा होने पर पहाड़ों का खिसकना, भूस्खलन, पुलों का बहना और गांवों का संपर्क टूट जाना अब लगभग हर वर्ष की घटना बन चुकी है। यह केवल प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम भी है।

मैदानी क्षेत्रों में भी स्थिति अलग नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में थोड़ी देर की तेज बारिश भी सामान्य जीवन को प्रभावित कर देती है। करोड़ों रुपये खर्च कर विकसित किए गए आधुनिक शहर कुछ घंटों की वर्षा का सामना नहीं कर पाते। इससे स्पष्ट है कि विकास केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और चमकदार परियोजनाओं का नाम नहीं है। वास्तविक विकास वह है जो प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ संतुलन स्थापित करते हुए नागरिकों को सुरक्षित और टिकाऊ जीवन प्रदान करे। इस पूरे संकट में शहरी नियोजन की कमजोरियां सबसे अधिक जिम्मेदार दिखाई देती हैं। अधिकांश नगरों के मास्टर प्लान वर्षों पुराने हैं या फिर केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं। जहां नियम बने भी हैं वहां उनका पालन प्रभावी ढंग से नहीं होता। अवैध निर्माण, अतिक्रमण और राजनीतिक संरक्षण के कारण योजनाएं अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पातीं। कई बार विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय का अभाव भी समस्या को बढ़ा देता है। एक विभाग सड़क बनाता है, दूसरा नाला बंद कर देता है और तीसरा जलभराव रोकने के लिए नई योजना तैयार करता है। परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद समस्या जस की तस बनी रहती है।

जलवायु परिवर्तन ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब वर्षा कम दिनों में अधिक तीव्रता के साथ होती है। कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है। ऐसे में दशकों पुराने जल निकासी मानकों पर आधारित व्यवस्था प्रभावी नहीं रह सकती। बदलती परिस्थितियों के अनुसार शहरों की योजना, सीवर नेटवर्क, वर्षा जल निकासी प्रणाली और आपदा प्रबंधन तंत्र का आधुनिकीकरण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। साथ ही जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी पुनर्जीवित करना होगा। पहले गांवों और शहरों में तालाब, पोखर, बावड़ियां और खुली भूमि वर्षा के पानी को रोकने और जमीन में पहुंचाने का काम करती थीं। आधुनिक विकास की दौड़ में इन प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी की गई। यदि इन जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए और वर्षा जल संचयन को व्यापक स्तर पर लागू किया जाए तो जलभराव की समस्या कम होने के साथ-साथ भूजल स्तर में भी सुधार होगा। इससे भविष्य में जल संकट से निपटने में भी सहायता मिलेगी।

भविष्य की योजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव का गंभीर मूल्यांकन अनिवार्य होना चाहिए। किसी भी नई कॉलोनी, औद्योगिक क्षेत्र, सड़क या भवन निर्माण की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां प्राकृतिक जल निकासी बाधित न हो। नदियों के बाढ़ क्षेत्र, आर्द्रभूमियों, झीलों और तालाबों को कानूनी संरक्षण दिया जाए तथा उनके आसपास अनियंत्रित निर्माण पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।

-शिवांश धाकड़

बढ़ती महंगाई और सीमित रोजगार के बीच गरीब परिवारों को योजनाओं से वंचित करना चिंता का विषय

पंक्ति में बैठे अंतिम गरीब तक पहुंचने का दावा करने वाली सुक्खू सरकार ने लाखों बीपीएल परिवारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मुख्यमंत्री बेशक बीपीएल परिवारों की भारी छंटनी को दूसरे फेज की प्रक्रिया बताकर जनता को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि पंचायत प्रतिनिधियों को दरकिनार कर आला अधिकारियों ने बीपीएल सूचियों पर अंतिम मुहर लगा दी है।

सरकार ने बीपीएल परिवारों की जो चयन प्रक्रिया जटिल बनाई है उसे देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में लाखों बीपीएल परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बीपीएल परिवारों का चयन प्रक्रिया अनुसार 18 से 59 वर्ष का व्यक्ति जिस घर का मुखिया, प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी, एक हेक्टर सिंचित भूमि का मालिक अब बीपीएल सूची में शामिल नहीं होगा।

सुखदेव सिंह
स्वतंत्र लेखक, नूरपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और अधिकतर जनता खेती-बाड़ी पर निर्भर करती है। मौसम की बेरुखी, महंगे उर्वरक, जुताई, बंदरों, सूअर, आवारा पशुओं के आतंक से किसान, बागवान खेती-बाड़ी छोड़ने को मजबूर हैं। रोजगार की कोई गारंटी नहीं, एक दिहाड़ीदार को मजदूरी नहीं मिलती। बेरोजगार युवा बद्दी, अंब, काला अंब, बरोटीबाला आदि उद्योगों में चंद सिक्कों में रोजी रोटी कमा रहे हैं। सरकारी विभागों में रोजगार पद जितने खत्म हो रहे राज्य सरकारें नए पद भरने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। सरकारें आउटसोर्स, पीटीए, अनुबंध पर कर्मचारी रखकर युवाओं का जमकर वर्षों शोषण करती रही हैं। सुक्खू सरकार ने वन, रोगी, जंगल और आपदा मित्रों की भर्तियां करके अपनी रोजगार गारंटी पूरी करने की कोशिश की है। यही नहीं, खाड़ी देशों में मोटरसाइकिल राइडर, वेयर हाउस पदों के लिए बेरोजगार युवाओं को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। हिमाचल प्रदेश में गत तीन वर्ष से आपदाओं के चलते जनता का काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। आपदा के जख्म भरने का नाम नहीं लेते और अगली बरसात उन्हें कुरेदकर हरी कर देती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 83 हजार मकान स्वीकृत किए थे।

इस योजना के तहत बनने वाले अधिकतर मकानों का काम एक वर्ष उपरांत भी किस्तों की लेटलतीफी के कारण लटका है। किस्त लेने की प्रक्रिया इस कदर जटिल है कि लाभार्थियों को भारी मशक्कत झेलते हुए पंचायत कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 1 लाख 57 हजार रुपए मिलने तय हुए हैं, जिसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकार को चुकाना है। क्षेत्रीय बैंक के सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के चलते लाभार्थी बैंक खाता धारकों के खाते में कई महीनों बाद पहली किस्त आई।

प्रदेश सरकार कर्जे क बोझ तले दबी जिसके चलते कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन भुगतान करना बहुत बड़ी चुनौती है। विकास कार्यों का काम लटकना बजट के अभाव में स्वाभाविक है। जब राज्य सरकार स्वयं भारी कर्ज के बोझ तले दबी हो, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आम जनमानस आर्थिक रूप से साधन-संपन्न कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को लगातार फोटोग्राफी, मस्टररोल भरने और जटिल औपचारिकताओं से गुजरना पड़ रहा है, जिससे गरीब परिवार खासे परेशान हैं। दूसरी ओर भवन निर्माण सामग्री के दाम सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं। सीमेंट, सरिया, ईंट, रेत, बजरी और पत्थर की कीमतों में लगातार वृद्धि ने गरीबों के लिए पक्का मकान बनाना लगभग असंभव कर दिया है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि वर्तमान परिस्थितियों में नाकाफी साबित हो रही है। इस राशि से एक सामान्य गरीब परिवार मकान की मजबूत नींव तक नहीं डाल सकता। मजबूरी में कई लाभार्थियों ने बैंकों और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर किसी तरह अपने मकानों पर लेंटल डाला है। विडंबना यह है कि अब सुक्खू सरकार इन्हीं परिवारों को साधन-संपन्न मानते हुए बीपीएल सूचियों से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।

यह सच है कि अतीत में कुछ अपात्र लोगों को नियमों की अनदेखी कर बीपीएल सूची में शामिल किया गया, लेकिन इसका समाधान यह नहीं कि वास्तविक गरीबों को ही बाहर कर दिया जाए। वर्तमान समय में बीपीएल श्रेणी का लाभ केवल सरकारी डिपुओं से मिलने वाले सस्ते राशन तक सीमित रह गया है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

मानवता के सशक्त कथाकार हैं अमिताव घोष

अमिताव घोष

अमिताव घोष का जन्म 11 जुलाई 1956 को कोलकाता में हुआ। वे समकालीन भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लेखकों में गिने जाते हैं। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे जिसके कारण बचपन में उन्हें भारत के विभिन्न शहरों तथा विदेशों में रहने और विभिन्न संस्कृतियों को निकट से समझने का अवसर मिला। यही विविध अनुभव आगे चलकर उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता बने। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की तथा बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से सामाजिक मानवशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की।

अमिताव घोष के उपन्यास इतिहास संस्कृति प्रवासन उपनिवेशवाद पर्यावरण और मानवीय संबंधों जैसे विषयों पर आधारित होते हैं। वे अपने गहन शोध ऐतिहासिक तथ्यों और सशक्त कथानक के लिए विश्वभर में सम्मानित हैं। उनकी रचनाओं में केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज और इतिहास की गहरी समझ भी दिखाई देती है।

कविता

सवाल

उदयवीर भारद्वाज, भारद्वाज भवन
मंदिर मार्ग कांगड़ा

चुप्पी साधे हर सवाल पर, खामोश क्यों रहूं
हर सवाल पर बोलूंगा, अय्याशों का हर राज खोलूंगा
ऐसा दौर आया क्यों, शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया किसने
भले मानुष को आदमखोर बनाया किसने, क्यों पड़े घाव इंसानियत पर
प्यारी महकती धरा को, जहरीले नागों का घर बनाया किसने
प्रेम भरी दुनिया थी ये, 35 टुकड़ों में कटी बेटी
वीरान हुई घर समाज की बहारें, भेड़िए ने नोच डाला चिड़िया को
यूं लगा क्रूर कसाई काट रहा बकरी को,क्यों न खौलेगा खून तेरा मेरा
लहूलुहान किया संविधान की छाती को, नजर कमजोर नहीं
नजरिया मजबूत है मेरा, लड़ना होगा कांटों से
फर्ज है यह तेरा मेरा, फर्ज है यह तेरा मेरा

11 जुलाई के बम धमाके: भारत के इतिहास का काला दिन

11 जुलाई 2006 का दिन भारत के इतिहास में एक अत्यंत दुखद और भयावह दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शाम के व्यस्त समय के दौरान पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार सात शक्तिशाली बम विस्फोट हुए। इन विस्फोटों ने कुछ ही मिनटों के भीतर पूरे महानगर को दहला दिया। इस आतंकी हमले में 180 से अधिक लोगों की जान चली गई जबकि सात सौ से अधिक लोग घायल हुए। बड़ी संख्या में यात्रियों को गंभीर चोटें आईं और अनेक परिवारों ने अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया। यह हमला केवल मुंबई पर नहीं बल्कि पूरे भारत की सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक एकता पर सीधा आघात था।

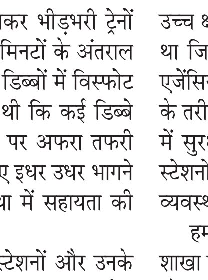

डॉ. दुनी चंद
स्वतंत्र लेखक

मुंबई की लोकल ट्रेनें शहर की जीवनरेखा मानी जाती हैं। प्रतिदिन लाखों लोग इन्हीं ट्रेनों के माध्यम से अपने कार्यस्थल तक पहुंचते हैं और शाम को घर लौटते हैं। 11 जुलाई की शाम भी हजारों लोग अपने कार्यालयों से निकलकर भीड़भरी ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान कुछ ही मिनटों के अंतराल में सात अलग अलग ट्रेनों के प्रथम श्रेणी डिब्बों में विस्फोट हुए। धमाकों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे जबकि अनेक यात्री घायल अवस्था में सहायता की गुहार लगा रहे थे।

विस्फोट मुंबई के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और उनके बीच के मार्गों पर हुए। माहिम जंक्शन बांद्रा खार रोड जोगेश्वरी बोरीवली मीरा रोड तथा माटुंगा रोड के आसपास धमाकों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि लोकल ट्रेनों को निशाना बनाकर बड़ा आतंकी हमला किया गया है। रेलवे सेवाएं बाधित हो गईं और पूरे महानगर में भय तथा अनिश्चितता का वातावरण बन गया। हजारों परिवार अपने परिजनों का पता लगाने के लिए रेलवे स्टेशनों अस्पतालों और पुलिस नियंत्रण कक्षों के चक्कर लगाने लगे।

हमले के तुरंत बाद पुलिस रेलवे सुरक्षा बल अग्निशमन विभाग और चिकित्सा सेवाओं ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मुंबई के नागरिकों ने भी अद्भुत साहस और मानवता का परिचय दिया। आसपास के लोग बिना किसी भेदभाव के घायलों को डिब्बों से बाहर निकालने लगे। निजी वाहनों टैक्सियों और एम्बुलेंसों की सहायता से घायलों को नजदीकी अस्पतालों तक पहुंचाया गया। कई अस्पतालों ने आपातकाल घोषित कर अतिरिक्त चिकित्सकों और कर्मचारियों को बुलाया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया ताकि घायलों का उपचार शीघ्र किया जा सके।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि विस्फोटकों को प्रेशर कुकर में रखकर बैगों के भीतर छिपाया गया था। इन बैगों को प्रथम श्रेणी डिब्बों में छोड़ दिया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार विस्फोटों में उच्च क्षमता वाले विस्फोटक पदार्थों का उपयोग किया गया था जिनकी वजह से नुकसान बहुत अधिक हुआ। जांच एजेंसियों ने घटनास्थलों से साक्ष्य एकत्र किए और विस्फोटों के तरीके का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। इसके बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया तथा रेलवे स्टेशनों हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई।

हमले की जांच महाराष्ट्र पुलिस की आतंकवाद निरोधक शाखा तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर की। जांच के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और विभिन्न राज्यों में छापेमारी की गई। समय के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए। मामला अदालत तक पहुंचा और वर्षों तक इसकी सुनवाई चलती रही। यह जांच भारतीय न्याय व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई क्योंकि घटना अत्यंत जटिल थी और इसमें कई स्तरों पर साक्ष्य जुटाने की आवश्यकता थी।

इस आतंकी हमले की देश और विदेश में व्यापक निंदा हुई। भारत सरकार ने इसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया और दोषियों को कठोर दंड दिलाने का संकल्प व्यक्त किया। अनेक देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया तथा आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ एकजुटता दिखाई। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद किसी एक देश या क्षेत्र की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती है।

मुंबई ने इस त्रासदी के बाद भी अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। अगले ही दिन बड़ी संख्या में लोग फिर से अपने काम पर लौटे और लोकल ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। इस दृढ़ता को अक्सर 'मुंबई स्पिरिट' के नाम से याद किया जाता है। हालांकि सामान्य जीवन लौट आया लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके लिए यह पीड़ा जीवनभर की बन गई। अनेक बच्चे अनाथ हुए कई परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई और कई घायल लोग लंबे समय तक शारीरिक तथा मानसिक आघात से जूझते रहे।

इस घटना के बाद भारत में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामान की जांच बढ़ाई गई। धातु जांच द्वार लगाए गए। निगरानी के लिए बंद परिपथ कैमरों का व्यापक उपयोग शुरू हुआ। संदिग्ध वस्तुओं की पहचान और निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्तों तथा खोजी कुत्तों की संख्या बढ़ाई गई। यात्रियों को भी जागरूक किया गया कि किसी लावारिस वस्तु या संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना सुरक्षा कर्मियों को दें। इसके अतिरिक्त विभिन्न शहरों में आपदा प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को भी अधिक प्रभावी बनाया गया।

मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों ने यह भी सिखाया कि आतंकवाद का मुकाबला केवल सुरक्षा बलों के माध्यम से नहीं किया जा सकता बल्कि समाज की सतर्कता और एकजुटता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। घटना के दौरान सामान्य नागरिकों ने जिस साहस और संवेदनशीलता का परिचय दिया वह प्रेरणादायक था।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

फिरोजाबाद मासूम आरव हत्याकांड में दोषी चाचा को फांसी की सजा

एजेंसी, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में एक युवक ने रिश्ते की भाभी से शादी करने की जिद में उसके मासूम बालक आरव की जमीन पर पटक – पटक कर हत्या की दी। इस प्रकरण के महज 40 दिन बाद न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हत्या के दोषी मृतक मासूम बालक के रिश्ते के चाचा विराज उर्फ जितेंद्र को फांसी की सजा सुनाई है।

थाना अरांव क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाली रति का विवाह वर्ष 2024 में बदायूं निवासी सुमित कुमार से हुआ था। पति से विवाद के बाद वह अपने मायके आ गई थी। 30 मई को रति अपने डेढ़ वर्षीय बेटे आरव के साथ थाना शिकोहाबाद क्षेत्र अन्तर्गत यादव कालोनी निवासी अपने एक रिश्तेदार के यहां थी, तभी महिला के रिश्ते का देवर विराज उर्फ जितेंद्र पाठक वहां पहुंच गया। विराज टॉफी दिलाने के बहाने बच्चे आरव को अपने साथ ले गया और रास्ते में मासूम आरव की जमीन पर पटक – पटक कर जघन्य हत्या कर दी थी। हत्या के बाद मासूम के शव को फेंककर वह भाग गया था। दोषी अपनी भाभी रति से शादी करने का दवाब बना रहा था। इसी के चलते उसने उसके मासूम बेटे की हत्या की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपित विराज उर्फ जितेन्द्र पुत्र विजेन्द्र पाल निवासी शेखूपुर थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं को उसी रात मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांचोपरांत महज 6 दिन में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि न्यायालय में 13 गवाहों ने गवाही दी।

न्यूज ब्रीफ

हाथरस में चांदी के हिसाब को लेकर घर पर पहुंचे युवकों ने की फायरिंग

एजेंसी, हाथरस। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के सादाबाद कस्बे के चांदी के हिसाब को लेकर घर पर पहुंचे युवकों द्वारा की गई फायरिंग से दहशत पैदा हो गयी। कोतवाली क्षेत्र के गांव बिसावर के पीड़ित ने गांव के ही एक युवक और उसके साथ आए निकटवर्ती गांव के युवक के खिलाफ कोतवाली में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। फायरिंग की पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी है। गांव बिसावर निवासी मुबारक पुत्र इकराम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुवार रात करीब 9:30 बजे गांव का एक युवक अपने साथी के साथ उसके घर पहुंचा। आरोप है कि गांव के युवक ने आते ही कहा कि उसके पास चांदी का हिसाब निकलता है। इस पर मुबारक ने किसी भी तरह का हिसाब होने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई।

घाघरा नदी की बाढ़ से निपटने को प्रशासन तैयार, एसडीएम रामनगर ने की समीक्षा बैठक

एजेंसी, बाराबंकी। जिले की रामनगर तहसील में घाघरा नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए शुक्रवार दोपहर तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी आनंद तिवारी की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। एसडीएम ने घाघरा किनारे बसे संवेदनशील गांवों के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व पंचायत सचिवों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कहा कि कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। जलस्तर की सूचना प्रतिदिन तहसील कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराई जाए। बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर व सूरतगंज को निर्देश दिए गए कि बाढ़ चौकियों पर मेडिकल टीम तैनात करें।

नोएडा में पैदल जा रहे युवक की नाले में डूबने से मौत,सड़क पर भरा था पानी

एजेंसी, नोएडा। नोएडा में एक 27 वर्षीय युवक पैदल जाते समय सड़क पर भरे पानी की वजह से वह गहरे नाले को नहीं देख पाया और नाले में जा गिरा। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। थाना सेक्टर 58 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सेक्टर 58 के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि युवक की पहचान आर्यन उम्र 27 वर्ष अट्टा गांव निवासी के रूप में हुई है। वह बृहस्पतिवार की शाम को पैदल जा रहे थे। तेज बारिश के चलते सड़क पर पानी भरा था। पानी भरे होने की वजह से वहां से बह रहे बड़े नाले को वह नहीं समझ पाए तथा चलते-चलते नाले में जा गिरे।

देवरिया : टेलर की चपेट में आने से महिला की मौत

एजेंसी, देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद के भलुअनी थाना क्षेत्र स्थित टेकुआ में शुक्रवार को तेज रफ्तार टेलर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी प्रदीप ने बताया कि ग्राम कुईया निवासी बनारसी राजभर की पत्नी सीता देवी (50) किसी कार्य से जा रही थीं। टेकुआ के पास एक तेज रफ्तार टेलर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

स्कूली वाहनों की सुरक्षा पर सख्ती , नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही

एजेंसी, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में शुक्रवार को जिलाधिकारी कपिल सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पाण्डेय की संयुक्त अध्यक्षता में जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतिभा शुक्ला वर्चुअल माध्यम से शामिल हुईं। बैठक में जनपद के सभी स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। तय किया गया कि सभी स्कूल वाहनों में चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन, वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर तथा आपातकालीन निकास जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।

फर्जी लोन ऐप से ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

एजेंसी, औरैया। उत्तर प्रदेश में औरैया जनपद की साइबर थाना पुलिस ने फर्जी लोन ऐप के जरिए लोगों से ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से बरामद सिम कार्डों से जुड़े मोबाइल नंबरों पर विभिन्न राज्यों से साइबर ठगी की 32 शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज मिली हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में बताया कि साइबर थाना पुलिस संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच एवं साइबर अपराध की रोकथाम के लिए दिबियापुर क्षेत्र में अभियान चला रही थी।

परिषदीय स्कूलों के छात्रों को सरकारी सहायता का इंतजार होगा खत्म

नोएडा के 30 हजार छात्रों को मिलेगी डीबीटी राशि

एजेंसी, नोएडा

बैंक और आधार सत्यापन के बाद जनपद गौतमबुद्ध नगर के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को जल्द ही डीबीटी योजना का लाभ मिलने वाला है। जिले के करीब 30 हजार विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में अगले महीने तक 1200 रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी। यह राशि विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी जैसी आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए दी जाती है। वर्तमान में इन विद्यार्थियों के बैंक खाते और आधार संबंधी विवरण का सत्यापन पूरा नहीं होने के कारण भुगतान रुका हुआ है।

बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार सरकार की डीबीटी योजना के तहत परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हर वर्ष 1200 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम करना है।

- **अगले महीने खातों में आएंगे 1200 रुपए**
- **बैंक और आधार सत्यापन के बाद छात्रों को मिलेगी डीबीटी राशि**

इस वर्ष जिले में पहले चरण के तहत 58 हजार से अधिक विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी की राशि सफलतापूर्वक भेजी जा चुकी है। वहीं करीब 30 हजार विद्यार्थियों को अभी इस सहायता राशि का इंतजार है। विभाग की ओर से इन विद्यार्थियों के विवरण की जांच और सत्यापन प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है, ताकि सभी पात्र बच्चों को योजना का लाभ मिल सके।

बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने बताया कि लंबित भुगतान का मुख्य कारण बैंक खातों और आधार विवरण में मौजूद त्रुटियां हैं। कई मामलों में बैंक खाते की जानकारी, आधार संख्या, नाम की वर्तनी, आईएफएससी कोड और अन्य जरूरी जानकारियों में अंतर पाया गया है। इसके अलावा कुछ अभिभावकों ने अभी तक अपने दस्तावेजों को अपडेट नहीं कराया है। इन कमियों के कारण सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और भुगतान में देरी हुई है।

उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों से संपर्क कर जरूरी दस्तावेजों को जल्द अपडेट कराएं।

यूपी में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को मिलेगा नया बाजार

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) एवं टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट (टीपीसीडीटी) के मध्य राज्य मिशन कार्यालय, लखनऊ में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका एवं उद्यमिता के अवसर विकसित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

उप मुख्यमंत्री शव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'विकसित भारत–2047' के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाना होगा और इसके लिए हम दिन–रात मेहनत करेंगे। गाँवों का विकास ही प्रदेश और राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत नींव है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों का सृजन, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना तथा स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करना है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आय बढ़ाना तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें 'लखपति दीदी' के रूप में स्थापित करना है।

लुक्सर जेल में कैदी उगा रहे सब्जियां आत्मनिर्भरता की नई मिसाल

एजेंसी, नोएडा

गौतम बुद्ध नगर के लुक्सर में स्थित जिला कारागार में कैदियों द्वारा उगाई जा रही सब्जियां आत्मनिर्भरता और पुनर्वास की नई मिसाल पेश कर रही है। जेल परिसर में बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती की जा रही है। जिससे जेल में बंद कैदियों को ताजी और हरी सब्जी उपलब्ध हो रही है। वहीं इन सब्जियों को प्रदेश के अन्य जिलों में भी नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। पिछले एक वर्ष में लुक्सर जेल से 681 कुंतल 90 किलोग्राम सब्जियां अन्य जिलों में भेजी गई है।

लुक्सर जेल के सुपरिंटेंडेंट बृजेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि जेल परिसर में 21.50 एकड़ क्षेत्र में सब्जियों की खेती की जा रही है। वर्तमान में 82 बंदी खेती और सब्जी के उत्पादन से जुड़े हैं। खेती के माध्यम से बंदियों को श्रम, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण मिल रहा है। उनका मानना है कि इस प्रकार की गतिविधियां बंदियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें भविष्य के लिए रोजगार पर कौशल भी प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि जेल में आलू, गोभी, पत्ता गोभी, पालक, गाजर, मूली, गांठ गोभी, लौकी, तोरही, भिंडी, कद्दू, अरबी ,टमाटर ,शलजम, बैगन जैसी विभिन्न मौसमी सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन करीब 4 कुंतल सब्जियों का उत्पादन यहां पर हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधों का होगा रोपण

एजेंसी, लखनऊ

गोरखपुर से सीएम योगी शुरू करेंगे वृक्षारोपण महायज्ञ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 12 जुलाई को गोरखपुर जनपद की सहजनवा तहसील में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट पौधा रोपित कर वृक्षारोपण महायज्ञ का शुभारम्भ करेंगे। महायज्ञ के अंतर्गत प्रदेश में वन विभाग व 26 राजकीय विभागों सहित समस्त विभाग स्वयं व व्यापक जनसहभागिता से एक दिन में 35 करोड़ पौधों का रोपण किया जायेगा। यह जानकारी प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डा.अरूण कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को लखनऊ के अरण्य भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में दी।

वन मंत्री ने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्कूली छात्र एवं छात्राओं की प्रतिभागिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। 12 जुलाई को प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदानों, एक्सप्रेस—वे,हाईवे व अन्य मार्गों के साथ—साथ रेल की पटरी के किनारे तथा सभी विश्वविद्यालय,कालेज,मेडिकल कालेजों,सीएचसी,पीएचसी व औद्योगिक इकाइयों के परिसरों में वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रदेश व केन्द्र के सभी मंत्री पौधरोपण कार्यक्रम में होंगे शामिल

प्रदेश में 12 जुलाई को पौधरोपण कार्यक्रम में प्रदेश व केन्द्र सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। मंत्री ने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी लखनऊ में पौधरोपण करेंगे।

रालोद अध्यक्ष व केन्द्रीय मंत्री जयंत चौधरी बागपत, जितिन प्रसाद पीलीभीत, अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मीरजापुर, एसपी सिंह बघेल आगरा, कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा, बीएल वर्मा बदायूं व कमलेश पासवान देवरिया में पौधरोपित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्यप्रताप शाही देवरिया, स्वतंत्रदेव सिंह जालौन, भूपेन्द्र चौधरी मुराराबाद, जयवीर सिंह फिरोजाबाद, ए.के.शर्मा आजमगढ़ तथा ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर में पौधरोपण करेंगे।

समाजसेवी इंजीनियर सुरेंद्र त्रिपाठी को महामना मालवीय मिशन ने दी श्रद्धांजलि

एजेंसी, वाराणसी। हामना मालवीय मिशन की काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा शुक्रवार को मिशन कार्यालय में प्रसिद्ध समाजसेवी इंजीनियर सुरेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सभा में महामना मालवीय मिशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।

श्रद्धांजलि सभा में कार्यकारी अध्यक्ष विजय नाथ पाण्डेय ने कहा कि इंजीनियर सुरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी का निधन महामना मालवीय मिशन और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे महामना के आदर्शों के सच्चे संवाहक थे। उनका सादगीपूर्ण जीवन, समाज के प्रति समर्पण और मिशन के कार्यों में उनका सक्रिय योगदान हमेशा हम सभी को प्रेरित करता रहेगा।

राष्ट्रीय सचिव गोविंद अग्रवाल ने कहा कि सुरेन्द्र त्रिपाठी ने एक कुशल इंजीनियर और समाजसेवी के रूप में समाज में जो प्रतिमान स्थापित किए, वे अनुकरणीय हैं। उन्होंने हमेशा मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। उनका जाना हमारे लिए एक अत्यंत दुखद क्षण है, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं।

रामपुर में होगी प्रदेश स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता

एजेंसी, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में शुक्रवार को मंडलीय क्रीड़ा समिति की बैठक में सत्र 2026–27 में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के लिए बनाई गई कार्य योजना, जनपद मुरादाबाद को प्रदेश स्तरीय क्रिकेट अंडर 17 व 19 वर्ष बालिका वर्ग प्रतियोगिता तथा जनपद रामपुर को प्रदेश स्तरीय हॉकी अंडर 14, 17 व 19 वर्ष बालक/ बालिका वर्ग प्रतियोगिता का दायित्व सौंपा गया। संचालन मंडलीय क्रीड़ा सचिव बंश बहादुर ने किया।

बैठक में सर्वप्रथम मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को मंडल के विभिन्न जनपदों को आवंटित किया गया जिसमें जनपद मुरादाबाद में तैराकी, बॉक्सिंग, क्रिकेट 17 एवं 19 वर्ष बालिका, सुब्रतो फुटबॉल, थागता मार्शल आर्ट, कराटे व कुश्ती , जनपद अमरोहा में कबड्डी, क्रिकेट 14 वर्ष बालक, टेबल टेनिस ,बैडमिंटन, हैंडबॉल, योगासन, भारोत्तोलन तथा एथलेटिक्स, जनपद बिजनौर में खो–खो, बास्केटबॉल, शतरंज, ताइक्वांडो, शूटिंग , नेहरू हॉकी, कलारीपयट्ट तथा वुशु जनपद रामपुर में वॉलीबॉल, गतका, मलखंभ को आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया। खेलों के निष्पक्ष आयोजन तथा श्रेष्ठ खिलाड़ियों के चयन हेतु चयनकर्ता तथा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षान्त समारोह 30 जुलाई को

एजेंसी, वाराणसी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने अपने 44वें दीक्षान्त महोत्सव की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा के निर्देशन में जारी अधिसूचना के अनुसार दीक्षान्त समारोह 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) को प्रातः 10 बजे विश्वविद्यालय के दीक्षान्त मण्डप में आयोजित होगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि समारोह में वर्ष 2026 की विद्यावारिधि, आचार्य, शास्त्री, शिक्षाशास्त्री, आयुर्वेदाचार्य, ग्रन्थालय विज्ञान तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार विज्ञान की परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होने के साथ भारतीय ज्ञान परम्परा और संस्कृत संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। दीक्षान्त समारोह में शामिल होने के इच्छुक सभी पात्र विद्यार्थियों को 20 जुलाई 2026 तक निर्धारित स्वीकृति–पत्र पूर्ण रूप से भरकर कुलसचिव कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद 21 और 22 जुलाई को प्रातः 10 बजे अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होकर अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा।

साथ ही 250 रुपये का निर्धारित शुल्क जमा कर दीक्षान्त परिधान (गाउन) तथा उपाधि प्राप्ति से संबंधित आवश्यक सामग्री प्राप्त करनी होगी ।कुलसचिव ने बताया कि अधिसूचना के साथ तीन आवश्यक प्रपत्र जारी किए गए हैं। पहला प्रपत्र दीक्षान्त समारोह में प्रवेश के लिए है, जिसे संस्थागत विद्यार्थियों के लिए संबंधित प्रधानाचार्य तथा स्वतंत्र परीक्षार्थियों के लिए सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।

विकास योगी ने कहा, अब प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत और सुरक्षित माहौल

सपा सरकार में जय श्रीराम का नारा लगाने वालों को जेल भेजा जाता था : योगी

एजेंसी, लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बस्ती के हर्रैया और कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्रों में 504.34 करोड़ रुपये की 77 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस को सनातन विरोधी करार देते हुए कहा कि रामभक्तों पर गोली चलाने के लिए समाजवादी पार्टी माफी मांगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या के बाद हर्रैया पहुंचे। यहां विकास की कुल 504.34 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें हर्रैया विधानसभा में 85.54 करोड़ रुपये की 22 नई परियोजनाओं का शिलान्यास और 275.76 करोड़ रुपये की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। जबकि कप्तानगंज विधानसभा में 62.08 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास और 80.96 करोड़ रुपये की पूर्ण हो चुकी 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। विकास कार्यों की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन विकास कार्यों से हर्रैया और कप्तानगंज के विकास की गति तेज होगी, क्योंकि वर्ष 2017 से पहले इन दोनों क्षेत्रों को विकास से उपेक्षित रखा गया और किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया गया लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने अपनी सरकार की हर क्षेत्र की उपलब्धियां गिनायीं।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को विकास विरोधी बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दोनों राम विरोधी और संविधान विरोधी हैं। इन दलों की जब सरकारें थीं तो गरीबों को लूटा जाता था और विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। उन्होंने कहा कि ये आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये दोनों पार्टियों ने हमेशा राम मंदिर और सनातन धर्म के विरोध में काम किया है। रामभक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी को अब माफी मांगनी चाहिए। सपा को कांवड़ यात्रा और पंचकोशी परिक्रमा रोकने के लिए माफी मांगनी चाहिए,लेकिन अब राम राज्य में न तो कांवड़ यात्रा रुकती है और न ही मंदिर का पैसा कब्रिस्तान के निर्माण पर खर्च हो रहा है।

77 परियोजनाओं का सीएम ने किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय (पीएमश्री) का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण संपर्क मार्ग, पर्यटन विकास, छात्रावास निर्माण, नगर पंचायत हर्रैया में गौशाला व अमृत सरोवर निर्माण और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। लोकार्पण वाली प्रमुख परियोजनाओं में राजकीय पालिटेक्निक हर्रैया, राजकीय महाविद्यालय भवन, अनेक प्रमुख मार्गों का निर्माण व चौड़ीकरण, सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास, पर्यटन विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

देवरिया डीएम ने कस्तूरबा विद्यालय का किया निरीक्षण

एजेंसी, देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शुक्रवार को विकास खंड गौरीबाजार के पथरहट स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में साफ–सफाई, पठन–पाठन, छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, भोजन व्यवस्था तथा आवासीय व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण करते हुए अधिकारियों एवं विद्यालय स्टॉफ को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शासन से मिलने वाली सभी सुविधाएं समयबद्ध और सुगमता के साथ छात्राओं के लिए निर्धारित समय पर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने विद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया कि छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ–साथ उन्हें कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल किया करें, ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

- **डीएम ने दिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वच्छता के निर्देश**

जिलाधिकारी ने वार्डन को विद्यालय परिसर में नियमित साफ–सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावास, कक्षाओं और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए स्वच्छ वातावरण बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। रसोईघर का निरीक्षण करते हुए डीएम ने छात्राओं के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि छात्राओं को पौष्टिक, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए।

बंद पड़े स्टोन क्रेशर में मजदूर का शव मिलने से मचा हड़कंप, हत्या की आशंका

भारतेंन्दु संवाददाता, नारनौल

जिले के गांव खातौली अहीर स्थित एक बंद पड़े स्टोन क्रेशर में गुरुवार देर रात मजदूर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी 47 वर्षीय बाबू राम के रूप में हुई है। वह लंबे समय से इसी स्टोन क्रेशर पर मजदूरी करता था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन, ग्रामीण और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार, जिस स्टोन क्रेशर में बाबू राम का शव मिला है, वह पिछले करीब 10 से 12 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। बताया गया कि बिजली बिल बकाया होने के कारण यहां बिजली आपूर्ति बंद थी। ऐसे में लोगों ने करंट लगने से मौत की संभावना पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों और मजदूरों का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। प्रवासी मजदूरों ने आरोप लगाया कि बाबू राम को क्रेशर संचालकों की ओर से काम के लिए बुलाया गया था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जाए और यदि किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

घटना की सूचना मिलने के बाद निजामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन परिजन न्याय की मांग को लेकर अड़ गए। परिजनों और ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। स्थिति को देखते हुए डीएसपी भारत भूषण और सीआईए इंचार्ज संदीप सिंह भी मौके पर पहुंचे।

कांग्रेस पर बरसे मुख्यमंत्री नायब सैनी

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर झूठे वादों का आरोप लगाते हुए सरकारी योजनाओं की गिनाईं उपलब्धियां

भारतेंन्दु संवाददाता, चंडीगढ

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य की डबल इंजन सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीब, किसान, युवा, महिला, बुजुर्ग और वंचित वर्गों का जीवन आसान, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को हरियाणा निवास में आयोजित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की योजनाओं का लाभ अब पात्र लोगों को घर बैठे मिल रहा है, जबकि पहले लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में गरीबों, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के नाम पर केवल वादे किए, लेकिन उन्हें योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावों के दौरान घोषणाएं कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करती रही हैं, जबकि भाजपा सरकार अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बुजुर्गों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हासिल करने के लिए लंबे समय तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लोगों को सिफारिशों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब तकनीक के माध्यम से योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गरीबों से 100 गज के प्लॉट देने सहित कई वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित रही।

पंजाब सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां भी जनता को कई बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन उन्हें धरातल पर लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल खरीद और युवाओं को रोजगार देने जैसे मुद्दों पर केवल वादे किए गए।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष में 50 हजार से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में योग्यता और प्रतिभा के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे युवाओं का सरकार और व्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है।

एसआईआर अभियान में फरीदाबाद पिछड़ा, केवल 45 प्रतिशत फॉर्म जमा

भारतेंन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत फॉर्म जमा कराने की रफ्तार धीमी बनी हुई है। प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जाने के बावजूद अब तक केवल 45 प्रतिशत फॉर्म ही भरकर वापस जमा हो पाए हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने अगले कुछ दिनों में शेष फॉर्म एकत्र करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जानकारी के अनुसार, एसआईआर अभियान के तहत जिले में करीब 80 प्रतिशत फॉर्म मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) लगातार घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं और उन्हें भरने की प्रक्रिया में सहायता भी दे रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अभी तक अपने फॉर्म जमा नहीं कराए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 14 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद 21 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे में समय पर फॉर्म जमा नहीं कराने वाले पात्र मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि प्रशासन एसआईआर अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार संपर्क बनाए रखें और मतदाताओं को फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 80 प्रतिशत फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 45 प्रतिशत फॉर्म ही वापस प्राप्त हुए हैं। एडीसी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम दिन का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंप दें। उन्होंने कहा कि यदि अंतिम समय में बड़ी संख्या में फॉर्म जमा होते हैं तो उनके सत्यापन और ऑनलाइन अपलोड की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी नागरिक समय रहते अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के फॉर्म निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा नहीं होंगे, उनका नाम 21 जुलाई को जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल होने में परेशानी आ सकती है।

न्यूज ब्रीफ

हैबतपुर में जलनिकासी संकट बरकरार

भारतेंन्दु संवाददाता, जींद। हैबतपुर गांव में पिछले 10 वर्षों से चली आ रही जलनिकासी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जींद मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए पंचायत ने 24 एकड़ जमीन दान दी थी और उस समय गांव की जलनिकासी व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज भी हालात जस के तस हैं। ग्रामीणों के अनुसार, पहले तालाब का पानी पाइपलाइन और मोटरों के माध्यम से उक्त जमीन तक पहुंचाया जाता था, जिससे जलभराव नियंत्रित रहता था। मेडिकल कॉलेज निर्माण के बाद यह व्यवस्था प्रभावित हो गई और अब तालाब ओवरफ्लो होने से गलियों में पानी जमा रहता है। महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से खड़े पानी के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और मकानों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है।

पुलिस से भागते आरोपी का पुल से गिरकर टूटा पैर

भारतेंन्दु संवाददाता, कैथल। सीआईए-1 पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास करने वाले आरोपी का पैर टूट गया। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया। डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि सीआईए-1 प्रभारी एसआई जसवंत सिंह के नेतृत्व में टीम गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गांव हजवाना निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ गोलू गांव सिसमौर से पाई नहर पुल के पास अवैध हथियार लेकर खड़ा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध पिस्तौल व एक कारतूस बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे यह हथियार एक सप्लायर ने दिया था। पुलिस आरोपी को निशानदेही के लिए ले गई थी, जहां उसने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की और पुल से कूद गया। गिरने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

खेत में करंट लगने से किसान की मौत

भारतेंन्दु संवाददाता, पानीपत। पानीपत जिले के गांव कवि में खेत पर काम करने गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव निवासी अनिल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, अनिल धान की फसल के लिए खेत में पानी लगाने गया था, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो वह खेत में ट्यूबवेल के पास बने कोठड़े में मृत मिला। उसके हाथ में बिजली का तार लगा हुआ था, जिससे करंट लगने से मौत की आशंका जताई गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनिल की मौत से परिवार में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की है।

बीरेंद्र सिंह की सतीश पूनिया से मुलाकात पर सियासी हलचल तेज

भारतेंन्दु संवाददाता, हरियाणा। राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली में हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया से मुलाकात की। इस बैठक के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह का हरियाणा की राजनीति में लंबा अनुभव और प्रभाव माना जाता है। वह पहले भाजपा में रह चुके हैं और बाद में कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऐसे में भाजपा प्रभारी से उनकी मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, दोनों नेताओं की ओर से इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी या बयान जारी नहीं किया गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस बैठक को प्रदेश में बदलते सियासी समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं।

साइबर ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार, पूरी रकम बरामद

भारतेंन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम फतेहाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पांच लाख 80 हजार रुपये की साइबर ठगी के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी गई पूरी राशि बरामद कर शिकायतकर्ता को वापस दिला दी।

थाना साइबर क्राइम फतेहाबाद प्रभारी निरीक्षक राहुल देव ने बताया कि रतिया निवासी गुरप्रीत सिंह ने शिकायत दी थी कि उनके एचडीएफसी बैंक खाते से जुड़ा पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया था। इसी बंद नंबर को एक अज्ञात व्यक्ति ने दोबारा अपने नाम पर सक्रिय करवा लिया और बैंक से नया एटीएम कार्ड जारी करवा लिया।

रोडवेज कर्मचारियों की दो दिवसीय हड़ताल शुरू, बसों का संचालन ठप

भारतेंन्दु संवाददाता, हिसार

अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पिछले 56 दिनों से धरने पर बैठे हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो के कर्मचारियों ने शुक्रवार से दो दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के चलते हिसार डिपो की बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहा। कर्मचारियों ने सुबह से ही डिपो परिसर में धरना देकर सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि प्रशासन की ओर से कर्मचारियों से बातचीत कर समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार तड़के करीब सवा तीन बजे कर्मचारियों ने हिसार डिपो से निकलने वाली बसों का संचालन रोक दिया। इसके बाद दिनभर रोडवेज की सभी सेवाएं प्रभावित रहीं। हड़ताल को सफल बनाने के लिए राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी हिसार पहुंचे और कर्मचारियों के साथ आंदोलन में शामिल हुए।

कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी लंबित मांगों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों के साथ बातचीत होने के बावजूद उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। इसी कारण उन्हें मजबूर होकर हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है।

इससे पहले गुरुवार शाम को भी रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का रात्रि संचालन बंद कर दिया था। कर्मचारियों ने रोडवेज महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर धरना शुरू करते हुए घोषणा की थी कि मांगें पूरी होने तक रात की बस सेवाएं भी बंद रखी जाएंगी।

तालाब में मिला प्लंबर का शव परिजनों ने थाने का किया घेराव

भारतेंन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

जिले के भूना क्षेत्र के गांव सनियाना में शुक्रवार सुबह तालाब से प्लंबर का शव मिलने के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय विपिन कुमार के रूप में हुई है। घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने भूना थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी और मामला दर्ज करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया।

परिजनों ने आरोप लगाया कि विपिन के साथ पहले विवाद हुआ था, लेकिन पुलिस ने समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि यदि पुलिस गंभीरता दिखाती तो शायद विपिन की जान बच सकती थी। मृतक की मां, पत्नी और अन्य ग्रामीण एफआईआर की प्रति मिलने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने की बात पर अड़े रहे।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को गांव में विपिन कुमार का कुछ लोगों के साथ मामूली विवाद हुआ था। आरोप है कि बुधवार को जब पुलिस मामले की जांच के लिए गांव पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस की मौजूदगी में ही दोबारा झगड़ा शुरू कर दिया। परिजनों के मुताबिक, करीब 20 से 25 लोग लाठी-डंडों से लैस होकर विपिन के पीछे दौड़ पड़े।

जान बचाने के लिए भाग रहे विपिन के सामने गांव का तालाब आ गया। हमलावरों के डर से उसने तालाब में छलांग लगा दी। उस समय लोगों को लगा कि वह तैरकर दूसरी ओर निकल गया होगा, लेकिन जब वह दो दिन तक घर वापस नहीं लौटा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। शुक्रवार सुबह तालाब के किनारे विपिन का शव मिला। शव मिलने की सूचना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया।

रेवाड़ी से 30 आधुनिक एंबुलेंस रवाना, हरियाणा में आपातकालीन सेवाओं को मिलेगी मजबूती

भारतेंन्दु संवाददाता, रेवाड़ी

हरियाणा में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने शुक्रवार को रेवाड़ी से 30 आधुनिक एंबुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई एंबुलेंसों के संचालन से प्रदेशभर में मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी होता है, इसलिए आधुनिक सुविधाओं से लैस एंबुलेंस सेवा को मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि नई एंबुलेंसों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से दुर्घटना, गंभीर बीमारी और अन्य आपात परिस्थितियों में मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया जा सकेगा। इससे मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के दौरान बेहतर देखभाल मिलेगी और इलाज शुरू करने में देरी नहीं होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गंभीर मरीजों के लिए शुरुआती समय यानी गोल्डन ऑवर काफी महत्वपूर्ण होता है। नई एंबुलेंसों के संचालन से मरीजों को कम समय में अस्पताल पहुंचाने में सहायता मिलेगी, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधार और विस्तार के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही एंबुलेंस नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को समान रूप से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इन 30 नई एंबुलेंसों के जुड़ने से प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपातकालीन सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी। इससे मरीजों को जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक आसानी से पहुंचाना है। नई एंबुलेंस सेवा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे खासकर दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने उम्मीद जताई कि आधुनिक एंबुलेंसों के संचालन से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई गति मिलेगी।

पानी से भरे गड्ढे में डूबकर नौ वर्षीय बच्चे की मौत

भारतेंन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। जिले के सेक्टर-65 स्थित आशियाना फ्लैट के पास शुक्रवार को दर्दनाक हादसा सामने आया। बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से नौ वर्षीय बच्चे रेहान की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस के अनुसार, रेहान सुबह रोजाना की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। वह स्कूल पहुंचा भी, लेकिन कुछ समय बाद किसी कारणवश स्कूल से बाहर आ गया। इसी दौरान वह रास्ते में बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई।

मृतक के दादा जलालुद्दीन ने बताया कि रेहान प्रतिदिन खुद ही स्कूल जाता था, क्योंकि स्कूल घर के पास ही था। शुक्रवार को भी वह सामान्य दिनों की तरह स्कूल के लिए निकला था। बाद में किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि बच्चा पानी से भरे गड्ढे में बेहोशी की हालत में पड़ा है। परिजन तुरंत उसे नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि रेहान के पिता नहीं हैं और उसकी देखभाल चाचा व अन्य परिजन करते थे।

मामूली विवाद में नौवीं के छात्र ने सहपाठी की कैंची घोंपकर कर दी हत्या

भारतेंन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

फतेहाबाद जिले के रतिया उपमंडल के गांव बादलगढ़ में मामूली विवाद ने एक नाबालिग छात्र की जान ले ली। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नौवीं कक्षा के दो छात्रों के बीच हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक छात्र ने अपने ही सहपाठी की कैंची मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, गांव बादलगढ़ निवासी 14 वर्षीय अरमान और नवनीत दोनों सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा के छात्र थे। गुरुवार को स्कूल में किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। विवाद के दौरान दोनों ने एक-दूसरे को शाम को गांव के मुख्य चौक पर देख लेने की धमकी दी थी।

बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम दोनों छात्र गांव के चौक पर पहुंचे। वहां बातचीत के दौरान विवाद फिर बढ़ गया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान आरोपी छात्र नवनीत अपने पिता की दुकान के अंदर चला गया। उसके पिता चौक में आरएमपी डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करते हैं।

आरोप है कि गुस्से में नवनीत ने दुकान में रखी कैंची उठा ली और अरमान की छाती पर वार कर दिया। कैंची लगने से अरमान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बचाने का प्रयास किया और अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रतिया के सरकारी अस्पताल भेजा गया।

पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों छात्र आपस में पड़ोसी भी थे। इस घटना ने गांव के लोगों को स्तब्ध कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के बीच मामूली विवाद का इतना गंभीर रूप लेना बेहद दुखद है। सदर थाना प्रभारी शीशपाल ने बताया कि मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर नाबालिग आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

रेवाड़ी-रींगस स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे बढ़े, यात्रियों और श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत

भारतेंन्दु संवाददाता, रेवाड़ी

यात्रियों की बढ़ती संख्या और धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी मार्ग पर संचालित स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। रेलवे के इस फैसले से खाटूश्यामजी और रींगस जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ दक्षिण हरियाणा के आम यात्रियों को भी राहत मिलेगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि गाड़ी संख्या 09633/09634 रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल रेल सेवा के संचालन को आगे बढ़ाया गया है। यह ट्रेन रेवाड़ी से 10 और 13 जुलाई को दो अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वहीं, रींगस से यह ट्रेन 11 और 14 जुलाई को अतिरिक्त यात्राएं करेगी।

इसी तरह गाड़ी संख्या 09637/09638 रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि में भी विस्तार किया गया है। यह ट्रेन रेवाड़ी से 10 और 13 जुलाई को अतिरिक्त फेरे संचालित करेगी, जबकि रींगस से भी 10 और 13 जुलाई को दो अतिरिक्त यात्राएं की जाएंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त फेरों का फैसला यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है। गर्मी के मौसम और धार्मिक यात्राओं के कारण रींगस और खाटूश्यामजी जाने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे में स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और नियमित ट्रेनों पर भी दबाव कम होगा।

इन ट्रेनों से गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल और दक्षिण हरियाणा के अन्य क्षेत्रों के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। यात्रियों को कम समय में बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे लगातार विशेष व्यवस्थाएं कर रहा है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन के समय, मार्ग और आरक्षण की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

नारनौल अदालतों में वकीलों का वर्क सस्पेंड, न्यायिक कार्य प्रभावित

महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर नारनौल समेत जिलेभर के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य रोका, मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई

भारतेंन्दु संवाददाता, नारनौल

महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्ताव के समर्थन में शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन नारनौल के आह्वान पर जिलेभर के अधिवक्ताओं ने एक दिन का वर्क सस्पेंड रखा। वकीलों के काम से दूर रहने के कारण नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली की रेवेन्यू कोर्ट तथा न्यायिक अदालतों में न्यायिक कार्य पूरी तरह प्रभावित रहा। बड़ी संख्या में अपने मामलों की सुनवाई के लिए पहुंचे लोगों को बिना कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा।

जिला बार एसोसिएशन नारनौल के प्रधान संतोख सिंह ने बताया कि महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन के साथ चल रहे विवाद और एडीएम कोर्ट से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। इसी प्रस्ताव के समर्थन में नारनौल सहित जिले की अन्य बार एसोसिएशनों ने अधिवक्ताओं की एकजुटता दिखाते हुए शुक्रवार को वर्क सस्पेंड रखने का निर्णय लिया।

वर्क सस्पेंड के दौरान अधिवक्ताओं ने अदालतों में किसी भी मामले की पैरवी नहीं की। इसके चलते न्यायालयों में पहले से निर्धारित मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई। जिन मामलों में पक्षकारों और गवाहों की उपस्थिति तय थी, उनमें भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। अदालत पहुंचे लोगों को अगली तारीख मिलने का इंतजार करना पड़ा।

अधिवक्ताओं के इस निर्णय से सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ी, जो दूर-दराज के क्षेत्रों से अपने मामलों की सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे थे। कई लोगों ने बताया कि वे सुबह से अदालत परिसर में अपने वकीलों से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कार्यवाही शुरू नहीं होने के कारण उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इससे उनका समय और धन दोनों प्रभावित हुआ।

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्क सस्पेंड का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करना नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके अधिकारों तथा सम्मान से जुड़े विषयों का समाधान जरूरी है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित विवादों को जल्द सुलझाने के लिए प्रशासन और संबंधित पक्षों की ओर से सकारात्मक पहल की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो और न्यायिक कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।

शुक्रवार को अदालत परिसरों में सामान्य दिनों की तुलना में कम चहल-पहल दिखाई दी। जहां आमतौर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता, पक्षकार और अन्य लोग मौजूद रहते हैं, वहीं वर्क सस्पेंड के कारण अदालतों का माहौल शांत रहा। कुछ लोग अपने मामलों की जानकारी लेने के लिए अदालत पहुंचे, लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा।

अधिवक्ताओं ने कहा कि यह निर्णय सभी बार एसोसिएशनों की सहमति से लिया गया था। उनका उद्देश्य अपने लंबित मुद्दों के समाधान के लिए एकजुटता प्रदर्शित करना है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

वहीं, न्यायालयों में कामकाज प्रभावित होने से आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कई मामलों में अगली तारीख तय होने के कारण पक्षकारों को दोबारा अदालत आना पड़ेगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे चाहते हैं कि विवाद का शीघ्र समाधान हो और न्यायिक व्यवस्था पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित हो सके। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से अपील की है कि लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि अदालतों में नियमित कामकाज बहाल हो और आम लोगों को राहत मिल सके।

दिल्ली में बादल छाए, रुक-रुक कर बारिश का दौर रहेगा जारी

बारिश से मिली गर्मी से राहत, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी बढ़ा सकती है मौसम की मार

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को राजधानी और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में 33.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है।

राजधानी में बारिश के बाद कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर जलभराव और यातायात की परेशानी भी देखने को मिली। सड़कों पर पानी जमा होने के कारण वाहन चालकों को धीमी गति से सफर करना पड़ा।

दिल्ली नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों ने जलभराव वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, दिल्ली में बारिश का यह दौर अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर जारी रह सकता है। मानसून की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण क्षेत्र में बादल बने हुए हैं। हालांकि, लगातार भारी बारिश की संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे बारिश और आंधी के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें तथा बिजली गिरने की स्थिति में सावधानी बरतें। तापमान में गिरावट के कारण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन उमस का असर कुछ समय तक बना रह सकता है। दिल्ली के लोगों के लिए आने वाले दिन राहत भरे रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत के अनुसार बारिश को लेकर नए अपडेट जारी किए जाएंगे। फिलहाल राजधानी में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली चमकने की संभावना के चलते सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया।

गाजियाबाद में बारिश का कहर जारी, प्रशासन अलर्ट पर

एजेंसी, नई दिल्ली

गाजियाबाद में एक दिन पहले हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में तीन बच्चों समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति देखने को मिली, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया और लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। जलभराव के कारण लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी।

प्रशासन के अनुसार, बारिश से हुए हादसों में अलग-अलग स्थानों पर लोगों की जान गई। कुछ घटनाएं पानी भरने, करंट लगने और अन्य दुर्घटनाओं से जुड़ी बताई जा रही हैं। मृतकों में बच्चों के शामिल होने से लोगों में चिंता और दुख का माहौल है। बारिश के बाद प्रशासन और नगर निकाय की टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किए। जलभराव वाले स्थानों से पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण बारिश के दौरान हर साल ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। लोगों ने प्रशासन से नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की है।

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें।

भारी बारिश का कहर, गाजियाबाद में 6 की मौत

न्यूज ब्रीफ

गुरुग्राम में गोलियों की गूंज, दीपक नांदल गैंग पर बड़ा प्रहार

एजेंसी, नई दिल्ली गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के चार शूटरों को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार, ये बदमाश एक कारोबारी के घर पर फायरिंग करने पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों और पुलिस के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई।मुठभेड़ के दौरान चार बदमाश मारे गए, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस कार्रवाई में पुलिस के तीन जवान भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मारे गए बदमाश गैंगस्टर दीपक नांदल के गिरोह से जुड़े हुए थे। दीपक नांदल का नाम पहले भी कई गंभीर आपराधिक घटनाओं में सामने आ चुका है। उसके गैंग पर हत्या, रंगदारी और फायरिंग जैसी वारदातों में शामिल होने के आरोप लगते हैं। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि गैंग के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों पर बड़ा असर पड़ेगा। गुरुग्राम पुलिस ने साफ किया है कि संगठित अपराध के खिलाफ उसका अभियान जारी रहेगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

फरीदाबाद में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रशासन अलर्ट, तैयारियां तेज

एजेंसी, नई दिल्ली फरीदाबाद में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नगर निगम और प्रशासन ने कार्यक्रम को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार सेक्टर-12/15 डिवाइडिंग रोड को विशेष रूप से सजाने की योजना बनाई गई है। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। समारोह स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक इंतजामों को लेकर संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नगर निगम की ओर से सड़क और आसपास के क्षेत्रों को सजाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। कार्यक्रम स्थल को तिरंगे के रंगों और देशभक्ति से जुड़े सजावटी सामानों से आकर्षक रूप दिया जाएगा। समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किए जाएंगे। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं, ताकि समारोह में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अलावा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर शहरवासियों में उत्साह का माहौल है। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस बार का आयोजन यादगार और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। समारोह में देशभक्ति कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी।

एनसीआर को मिलेगी नई रफ्तार, 74 किमी लिंक एक्सप्रेसवे की तैयारी शुरू

एजेंसी, नई दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 74 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के 56 गांवों की भूमि का उपयोग किया जाएगा। इनमें गौतमबुद्ध नगर जिले के आठ और बुलंदशहर जिले के 48 गांव शामिल हैं। प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे का उद्देश्य एनसीआर के प्रमुख क्षेत्रों के बीच आवागमन को आसान बनाना और वाहनों का दबाव कम करना है। परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में यात्रा का समय कम होने की उम्मीद है। इससे लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर संबंधित विभागों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रभावित गांवों की जमीन का सर्वे और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। परियोजना में करीब चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के कई क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से व्यापार, रोजगार और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रशासन का कहना है कि परियोजना को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय बनाया जा रहा है। लिंक एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद एनसीआर में सड़क नेटवर्क और अधिक मजबूत होगा।

पलवल में एनएचआरसी की बैठक बंधुआ मजदूरी खत्म करने पर जोर

एजेंसी, नई दिल्ली

पलवल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बंधुआ मजदूरी से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम ने की। उन्होंने अधिकारियों को बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए।

बैठक में जिले में बंधुआ मजदूरी की स्थिति, दर्ज मामलों और पीड़ितों के पुनर्वास की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि बंधुआ मजदूरी मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की पहचान के लिए नियमित निरीक्षण अभियान चलाए जाएं और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही, मुक्त कराए गए मजदूरों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में उपायुक्त डॉ. सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आयोग को जिले में बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों और प्रशासनिक कदमों की जानकारी दी। एनएचआरसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएं, ताकि लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी मिल सके। आयोग ने कहा कि बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई जरूरी है। बैठक के बाद प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जिले में बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

समन भेजने के नियमों पर कोर्ट सख्त, ईडी को सुधार के आदेश

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने विदेश में रह रहे एक आरोपी को समन भेजने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जांच एजेंसी को अपनी गलती सुधारने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते समय उसे उचित तरीके से सूचना देना जरूरी है। मामला धोखाधड़ी जैसे आरोपों से जुड़े एक प्रकरण का है, जिसमें आरोपी व्यक्ति विदेश में रह रहा था। ईडी ने आरोपी को समन भेजने के लिए उसके पिता के पते का इस्तेमाल किया था।

इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी गई, जिसके बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रक्रिया की समीक्षा की। अदालत ने कहा कि यदि आरोपी विदेश में रह रहा है, तो उसे समन भेजने के लिए कानूनी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। केवल उसके पिता या

परिवार के किसी सदस्य के पते पर समन भेजना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह सही प्रक्रिया अपनाते हुए आरोपी को दोबारा समन जारी करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। किसी भी आरोपी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलना आवश्यक है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह आदेश विदेश में रह रहे आरोपियों से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश साबित हो सकता है। अब ईडी को अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि समन प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। ईडी अब कानूनी नियमों के अनुसार आरोपी को नोटिस भेजेगी।

चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने चोरी के मामलों में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की स्कूटी और एक अवैध हथियार बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिल्ली के सीमापुरी निवासी जाकिर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता था। शालीमार गार्डन थाना पुलिस क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी, इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर जाकिर को रोककर पूछताछ की गई। जांच के दौरान उसके पास से चोरी की स्कूटी और हथियार बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी सामने आई। आरोपी के खिलाफ साहिबाबाद और शालीमार गार्डन थानों में चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब उससे जुड़े अन्य मामलों और उसके साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

कब्जे के विवाद में फायरिंग मधु विहार से आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली के मधु विहार इलाके में बैंक्वेट हॉल पर कब्जे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान बदमाशों ने कथित तौर पर फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, मामला बैंक्वेट हॉल के मालिकाना हक और कब्जे से जुड़े विवाद का बताया जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। गुरुवार को विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

घटना की जानकारी मिलते ही मधु विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की और

एक आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश जारी है। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और फायरिंग में इस्तेमाल हथियार के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद संपत्ति और बैंक्वेट हॉल के कब्जे को लेकर था। पुलिस का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि दोबारा किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मधु विहार फायरिंग मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

आईपी यूनिवर्सिटी ने जारी किया ऑफलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल

एजेंसी, नई दिल्ली

आईपी यूनिवर्सिटी के बी.फार्मा और एमएएमसी कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पहली ऑफलाइन काउंसलिंग 15 जुलाई को द्वारका स्थित मुख्य परिसर में आयोजित की जाएगी। इस दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और मेरिट के आधार पर सीटों का आवंटन उसी दिन किया जाएगा।

विश्वविद्यालय ने सभी पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित समय पर काउंसलिंग स्थल पर पहुंचने की अपील की है। अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेज, उनकी स्वप्रमाणित प्रतियां, पासपोर्ट आकार के फोटो तथा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। दस्तावेज अधूरे होने या निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवार का दावा प्रभावित हो सकता है। सीटों का आवंटन अभ्यर्थियों की मेरिट, उपलब्ध सीटों और निर्धारित प्रवेश नियमों के अनुसार किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित होगी, उन्हें तय समय सीमा के भीतर प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी सीट की पुष्टि करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय में औपचारिकताएं पूरी नहीं करता, तो उसकी सीट अगले पात्र उम्मीदवार को आवंटित की जा सकती है।

मेरिट से होगा बी.फार्मा सीट आवंटन

गुरुग्राम में पुलिस का बड़ा एनकाउंटर 4 बदमाश ढेर, 3 जवान घायल

एजेंसी, नई दिल्ली

गुरुग्राम में गुरुवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में चार बदमाश मारे गए, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान पुलिस के तीन जवान भी गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जानकारी के अनुसार, बदमाश एक कारोबारी के घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने बदमाशों को घेरकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही गोलियां चला दीं। इसके बाद दोनों ओर से कई मिनट तक जबरदस्त फायरिंग हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चार बदमाशों को ढेर कर दिया, जबकि पांचवां गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस ने घटनास्थल से कई आधुनिक हथियार, बड़ी संख्या में कारतूस और एक वाहन भी बरामद किया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाश संगठित अपराध से जुड़े हो सकते हैं और उनके खिलाफ पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस अब उनकी पहचान, आपराधिक रिकॉर्ड और घटना के पीछे की साजिश की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अब ई-वैन बनेगी सहारा! दिल्ली में नई परिवहन योजना पर मंथन

राजधानी में लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी आसान, आएंगी सेवन सीटर ई-वैन

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुलभ, आधुनिक तथा पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सेवन सीटर इलेक्ट्रिक वैन शुरू करने की योजना पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य उन इलाकों तक बेहतर परिवहन सुविधा पहुंचाना है, जहां बड़ी डीटीसी या क्लस्टर बसों का संचालन संभव नहीं हो पाता। सरकार का मानना है कि छोटे आकार के इलेक्ट्रिक वाहन संकरी गलियों और कम चौड़ाई वाली सड़कों पर आसानी से चल सकेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को आने-जाने में काफी सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित योजना के तहत इन इलेक्ट्रिक वैन को प्रमुख मेट्रो स्टेशनों, बस टर्मिनलों और रिहायशी कॉलोनियों के बीच फीडर सेवा के रूप में संचालित किया जा सकता है। इससे यात्रियों को अंतिम पड़ाव यानी 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' की बेहतर सुविधा मिलेगी। फिलहाल कई इलाकों में लोगों को सार्वजनिक परिवहन तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है या निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। नई व्यवस्था इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है।

सेवन सीटर इलेक्ट्रिक वैन पूरी तरह बैटरी से संचालित होंगी, जिससे प्रदूषण और ध्वनि दोनों में कमी आएगी। दिल्ली सरकार पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठा रही है और यह योजना उसी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य राजधानी में स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। सूत्रों के अनुसार, परिवहन विभाग इस योजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। इसमें संभावित रूट, किराया, चार्जिंग स्टेशन, संचालन मॉडल और यात्रियों की मांग का आकलन किया जा रहा है। योजना को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसे पहले चुनिंदा क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा सकता है।

दिल्ली सरकार लाएगी नई इलेक्ट्रिक वैन सेवा

नोएडा की सोसायटी में 14 घंटे गुल रही बिजली, लोग बेहाल

एजेंसी, नई दिल्ली

नोएडा के सेक्टर-150 स्थित एटीएस प्रिस्टीन सोसाइटी में गुरुवार को करीब 14 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से हजारों निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक बिजली नहीं रहने के कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई। भीषण गर्मी और उमस के बीच घरों में रहना मुश्किल हो गया, जबकि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे अधिक दिक्कतें झेलनी पड़ीं।

बिजली आपूर्ति ठप होने से लिफ्ट, पानी की मोटर और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित रहीं। कई टावरों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई, जिससे लोगों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ा। बिजली नहीं होने से इनवर्टर और बैटरियां भी जवाब दे गईं, जिसके कारण शाम तक स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग और सोसाइटी प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन लंबे समय तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें समय पर सही जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। कई परिवारों को छोटे बच्चों और बुजुर्गों को राहत देने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने पड़े।

बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी खराबी के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई थी। खराबी का पता लगाकर मरम्मत कार्य शुरू किया गया और कई घंटों की मेहनत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए संबंधित उपकरणों की जांच और रखरखाव को और मजबूत किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में आज और कल भारी बारिश की संभावना

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून के कम दबाव वाले सिस्टम के आपस में मिलने से 11-13 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर में बारिश बढ़ने की उम्मीद है जिसमें 11-12 जुलाई को बारिश सबसे ज़्यादा हो सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक आम तौर पर गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान भी लगाया है। साथ ही बीच-बीच में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने संवेदनशील इलाकों में भारी बारिश और संभावित भूस्खलन के लिए चेतावनी भी जारी की है।

मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर के अनुसार 10 जुलाई को मौसम आम तौर पर गर्म और उमस भरा रहेगा और कुछ जगहों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। जम्मू डिवीजन में कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश होने की संभावना है। 11-12 जुलाई को कई जगहों पर एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। जम्मू डिवीजन की चिनाब घाटी और पीर पंजाल रेंज में कुछ जगहों पर भारी बारिश और थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है।

13-16 जुलाई के बीच मौसम आम तौर पर गर्म और उमस भरा रहेगा और कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। जम्मू डिवीजन में कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश होने की संभावना है।

बाईपास नहीं, बीरवाह से गुजरे एनएच-701ए : महबूबा मुफ्ती

व्यापार और रोजगार बचाने को महबूबा ने उठाया एनएच-701ए का मुद्दा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-701ए के प्रस्तावित मार्ग को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। उन्होंने आग्रह किया है कि राजमार्ग का निर्माण बीरवाह कस्बे से होकर गुजरने वाले मौजूदा मार्ग को उन्नत करके किया जाए, न कि नए बाईपास के माध्यम से। उनका कहना है कि यदि राजमार्ग को कस्बे से बाहर ले जाया गया तो स्थानीय व्यापार, रोजगार और हजारों परिवारों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

महबूबा मुफ्ती ने अपने पत्र में बताया कि हाल ही में बीरवाह सिविल सोसायटी, ट्रेड फेडरेशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बाजार संघों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के

एनएच-701ए का मार्ग बदलने की मांग, गडकरी को लिखा पत्र।

प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित बाईपास को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कस्बे की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। स्थानीय लोगों की मांग को गंभीरता से लेते हुए महबूबा मुफ्ती ने यह मुद्दा सीधे केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया।

उन्होंने कहा कि बीरवाह मध्य कश्मीर का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्र है। आसपास के अनेक गांवों के लोग प्रतिदिन शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, सरकारी कार्यों और व्यापारिक जरूरतों के लिए इसी कस्बे पर निर्भर रहते हैं। मौजूदा सड़क उप-जिला अस्पताल, शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, बैंकों और प्रमुख बाजारों को जोड़ती है। यदि राष्ट्रीय राजमार्ग को बाईपास के माध्यम से बनाया गया तो यातायात का मुख्य प्रवाह कस्बे से बाहर चला जाएगा, जिससे स्थानीय दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

महबूबा मुफ्ती ने पत्र में उल्लेख किया कि सड़क किनारे व्यापार करने वाले दो हजार से अधिक परिवारों की आजीविका सीधे इस मार्ग पर निर्भर है। यदि बाईपास बनता है तो इन परिवारों की आय में भारी गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास परियोजना का उद्देश्य लोगों की सुविधा और क्षेत्र का विकास होना चाहिए, न कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करना।

जेकेएसएसबी टाइप टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र जारी

15 जुलाई से शुरू होगी जेकेएसएसबी की कौशल परीक्षा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) ने जूनियर असिस्टेंट पद के लिए आयोजित होने वाले टाइप टेस्ट की अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार विभिन्न आइटम नंबरों के तहत चयन प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षण 15 जुलाई 2026 से शुरू होगा। परीक्षा जम्मू और श्रीनगर स्थित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जम्मू केंद्र के अभ्यर्थियों का परीक्षण एनआईईएलआईटी जम्मू तथा श्रीनगर केंद्र के अभ्यर्थियों का परीक्षण एनआईईएलआईटी श्रीनगर में होगा।

बोर्ड ने बताया कि जिन उम्मीदवारों का टाइप टेस्ट 15 जुलाई से निर्धारित है, उनके प्रवेश पत्र 10 जुलाई 2026 से जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने यूजरनेम और पासवर्ड की सहायता से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का नाम, पता, परीक्षा की तिथि तथा रिपोर्टिंग समय सहित सभी आवश्यक जानकारी दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उम्मीदवार को डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।

यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई आती है या फोटो अथवा अन्य विवरण में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो वह कार्यालय समय के दौरान जम्मू या श्रीनगर हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकता है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा वाले दिन फोटो संबंधी किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को पहले ही अपने प्रवेश पत्र की जांच कर आवश्यक सुधार कराने की सलाह दी गई है।

जेकेएसएसबी ने परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड में से किसी एक वैध फोटो पहचान पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा।

न्यूज ब्रीफ

हाई टेंशन लाइन हादसे में हाथ गंवाने वाली 13 वर्षीय कीर्ति को डेढ़ महीने बाद भी नहीं मिला इंसाफ

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू के बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में हाई टेंशन बिजली लाइन से हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई 13 वर्षीय कीर्ति को डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिल सका है। हादसे में अपना एक हाथ गंवा चुकी बच्ची के मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने से पीड़ित परिवार गहरे आक्रोश और निराशा में है। परिवार का आरोप है कि संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है, जबकि पुलिस की ओर से भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कीर्ति के पिता सुरेश का कहना है कि हादसे के बाद से वह लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें हर स्तर पर केवल आश्वासन और टालमटोल का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि बिजली विभाग मामले की वास्तविक परिस्थितियों को छिपाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि कभी शिकायत पत्र की भाषा पर आपत्ति जताई जाती है तो कभी उन्हें शिकायत में हाई टेंशन तार टूटने का उल्लेख नहीं करने के लिए कहा जाता है। उनका मानना है कि ऐसा करके हादसे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

राजौरी में संदिग्ध फ़ूड पॉइज़निंग के बाद एक ही परिवार के छह सदस्य अस्पताल में भर्ती

भारतेंदु संवाददाता, राजौरी। राजौरी ज़िले के एक दूर-दराज़ गांव के एक परिवार के लगभग आधा दर्जन सदस्यों को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें गैस्ट्रोएंटेराइटिस और दस्त के लक्षण दिखे थे जिसके पीछे फ़ूड पॉइज़निंग की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि परिवार के सदस्य एक जंगली सब्ज़ी खाने के बाद बीमार पड़ गए। सभी बीमार लोगों को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनकी हालत पर नज़र रखी जा रही है। शुरुआती जाँच से पता चलता है कि बीमारी का संभावित कारण उस जंगली सब्ज़ी का सेवन हो सकता है। गांव में मेडिकल टीमें भेजी गई हैं और आगे की जांच चल रही है और अधिक जानकारी का इंतज़ार है।

जम्मू पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में सामान बरामद

भारतेंदु संवाददाता, जौरियां। गैर-कानूनी शराब के धंधे के खिलाफ एक सफल ऑपरेशन में पुलिस पोस्ट जौरियां की एक पुलिस टीम ने भरोसेमंद जानकारी के आधार पर छापेमारी की। उक्त कार्रवाई का नेतृत्व इंचार्ज पुलिस पोस्ट जौरियां वरिंदर सिंह कर रहे थे। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गैर-कानूनी शराब और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान मिली एक खास जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने तहसील जौरियां के जाध राजहोरमा गांव में एक जगह पर छापा मारा। इस दौरान एक महिला को गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला की पहचान रविंदर कौर पत्नी स्वर्गीय सुखविंदर सिंह निवासी जाध राजहोरमा, तहसील जौरियां, जिला जम्मू के रूप में हुई है।

एक ही परिवार के 8 सदस्य अचानक पड़े बीमार, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

भारतेंदु संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले की ख्वास तहसील के दूर-दराज इलाके गडयोग गांव के एक ही परिवार के 6-8 सदस्यों को गुरुवार आधी रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध फूड पॉइजनिंग के कारण उनमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस और दस्त जैसी बीमारी के लक्षण दिखे थे। सूत्रों के मुताबिक परिवार के प्रभावित सदस्यों ने जंगली सब्जी खाने के बाद उल्टी, दस्त और उससे जुड़े अन्य लक्षणों की शिकायत की थी। शुरुआती जांच से पता चलता है कि बीमारी जंगली खाने योग्य सब्जी या पौधे के सेवन से हुई हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारी सही कारण का पता लगाने के लिए और जांच कर रहे हैं। सभी प्रभावित लोगों को जीएमसी राजौरी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सभी मरीजों की हालत अभी स्थिर है, वे इलाज पर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और खतरे से बाहर हैं। इस बीच स्वास्थ्य टीमें स्थिति पर नजर रख रही हैं और घटना के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रही हैं।

श्रीनगर में भीषण आग से तीन मंजिला इमारत राख, लाखों की संपत्ति स्वाहा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के जकुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक टेक्सटाइल उद्योग की तीन मंजिला इमारत में गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिससे भवन, कढ़ाई की मशीनें, कच्चा पश्मीना तथा अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। सूचना मिलते ही कई दमकल केंद्रों की टीमें मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के दौरान इमारत के भीतर बेहोश पड़े मोहम्मद हसीब खान को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने भी राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया।

सुंदरबनी में कार-स्कूटी की टक्कर, युवक घायल

भारतेंदु संवाददाता, सुंदरबनी। जम्मू-राजौरी-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिओट क्षेत्र में शुक्रवार को एक मारुति कार और स्कूटी की टक्कर में 25 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल की पहचान सुंदरबनी निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मुकेश स्कूटी से नौशहरा से सुंदरबनी की ओर जा रहा था, तभी जम्मू से नौशहरा जा रही एक मारुति कार से उसकी भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे तुरंत उप जिला अस्पताल सुंदरबनी पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

अमरनाथ यात्रा के दौरान उधमपुर में बड़ा हादसा, छह श्रद्धालु घायल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। अमरनाथ यात्रा के दौरान शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में छह श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सुरक्षा बलों और प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया।

- पहलगाम जा रही श्रद्धालुओं की गाड़ी पलटी
- सेना और सीआरपीएफ ने बचाई जानें

जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना उधमपुर-चेनानी मार्ग पर टोल्डी नाला के पास हुई। श्रद्धालुओं को पहलगाम आधार शिविर ले जा रही गाड़ी अचानक सड़क पर संतुलन खो बैठी और पलट गई। हादसे के समय वाहन में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद राहत दल घटनास्थल पर पहुंच गए।

घायलों की पहचान मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर निवासी श्रद्धालुओं के रूप में हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ, भारतीय सेना, सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया।

घायल अमरनाथ यात्रियों से मिले डीआईजी शिव कुमार

भारतेंदु संवाददाता, उधमपुर। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान टोल्डी नाला के पास हुए सड़क हादसे में घायल यात्रियों का हालचाल जानने के लिए उधमपुर-कटरा-रियासी रेंज के डीआईजी शिव कुमार, एसएसपी उधमपुर अमृतपाल सिंह, उपायुक्त उधमपुर मिंगा शेरपा तथा सीआरपीएफ की 187वीं बटालियन के कमांडेंट मनोज सिकोन जिला अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार टोल्डी नाला के पास एक अर्टिगा कार सड़क से फिसल गई, जिससे पांच श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों की पहचान सुभाष गुप्ता, सीमा गुप्ता, राजीव गुप्ता, गीता गुप्ता और दलीप कुमार गुप्ता के रूप में हुई है।

राज्य का दर्जा मुद्दे पर भाजपा ने उमर सरकार पर साधा निशाना

जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही एनसी : भाजपा

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पर तीखा हमला करते हुए जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले साल इस अभियान का वादा किया था।

मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए शर्मा ने पूछा कि वादा किया गया जन हस्ताक्षर अभियान आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया और आरोप लगाया कि एनसी सरकार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता निभाने में विफल रही है। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नई दिल्ली में पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए भाजपा नेता ने प्रदर्शन को 'दिखावा' करार दिया और आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में व्यापक भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाना है। शर्मा ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के बजाय राजनीतिक हथकंडे अपना रहा है और पारदर्शिता, जवाबदेही और जन कल्याण से संबंधित चिंताओं को नजरअंदाज कर रहा है।

आउटसोर्सिंग नीति के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा करते हुए विपक्ष के नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर अपना अभियान तेज करेगी।

लेह समेत पांच स्थानों पर ईवी चार्जिंग सुविधा शुरू

- उपराज्यपाल सक्सेना ने शुरू किए पांच इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

भारतेंदु संवाददाता, लेह। सतत परिवहन को बढ़ावा देने और कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज केंद्र शासित प्रदेश में पांच इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया।

यह स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन और लद्दाख के नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। लद्दाख में पहले ये नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लेह के मुख्य बस स्टैंड, टिया रोंग, सोलर कॉलोनी, चुचोट शम्मा और खलत्सी में स्थापित किए गए हैं।

वहीं लेह में मैग्नेटिक हिल के पास स्थित छठा चार्जिंग स्टेशन निर्माण के अंतिम चरण में है। ये सभी चार्जिंग स्टेशन मिलकर लद्दाख में एक व्यापक ईवी चार्जिंग नेटवर्क की नींव रखेंगे जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी और स्थानीय निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए सुविधाजनक चार्जिंग अवसंरचना सुनिश्चित होगी।

नई ईवी चार्जिंग अवसंरचना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को लद्दाख में यात्रा करते समय या अपने वाहनों को चार्ज करते समय किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

जनसांख्यिकीय बदलाव रोकना जरूरी : एसपी वैद

- रोहिंग्या-बांग्लादेशी मुद्दे पर एसपी वैद ने रखी राय

भारतेंदु संवाददाता, रामबन। जम्मू-कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने कहा कि भारत की संस्कृति और जनसांख्यिकीय संतुलन की रक्षा के लिए अवैध घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर चिंताएं सामने आई हैं और इस विषय पर सटीक जानकारी तथा पारदर्शिता जरूरी है। वैद ने विदेशी फंडिंग की निगरानी को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार ने इसके लिए व्यवस्था और एक आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों और घुसपैठ पर प्रभावी कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

एलओसी पहुंचे सेना प्रमुख, जवानों को दिया मिशन पर फोकस का मंत्र

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर लगातार जारी गतिविधियों और घुसपैठ की आशंकाओं के बीच भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पुंछ और राजोरी के सीमावर्ती क्षेत्रों का महत्वपूर्ण दौरा किया। यह उनका सेना प्रमुख बनने के बाद इन संवेदनशील इलाकों का पहला दौरा था। इस दौरान उन्होंने नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों की युद्ध तत्परता, सुरक्षा व्यवस्था और ऑपरेशनल तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया।

एलओसी पर ऑपरेशनल तैयारियों का सेना प्रमुख ने लिया जायजा।

सेना प्रमुख ने अग्रिम चौकियों पर पहुंचकर सैनिकों से सीधे संवाद किया और उन्हें हर परिस्थिति में सतर्क रहते हुए अपने मिशन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने का संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहना आवश्यक है।

- सेना प्रमुख ने अधिकारियों संग की उच्चस्तरीय समीक्षा

दौरे के दौरान जनरल धीरज सेठ ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में नियंत्रण रेखा पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति, सैनिकों की तैनाती, निगरानी व्यवस्था, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और आतंकरोधी अभियानों की समीक्षा की गई।

यात्रा | 33 विदेशी श्रद्धालुओं समेत 8,796 यात्रियों का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना

जम्मू से अमरनाथ यात्रा का नौवां जत्था रवाना

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पवित्र अमरनाथ यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से 33 विदेशी श्रद्धालुओं सहित कुल 8,796 यात्रियों का नौवां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। पूरे आधार शिविर में सुबह से ही भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालु हर-हर महादेव, बम-बम भोले और जय बाबा बर्फानी के जयकारे लगाते हुए अपने पवित्र सफर पर निकले।

बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा जम्मू, अमरनाथ यात्रा जारी।

अधिकारियों के अनुसार इस जत्थे में 6,046 पुरुष, 2,042 महिलाएं, 228 साधु, 56 साध्वियां, 10 बच्चे, एक ट्रांसजेंडर श्रद्धालु तथा 33 विदेशी यात्री शामिल हैं। यात्रा को सुचारु और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कुल 354 वाहनों का काफिला तैयार किया गया। सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में श्रद्धालुओं को दो अलग-अलग मार्गों से घाटी की ओर रवाना किया गया।

जानकारी के अनुसार बालटाल मार्ग से जाने वाला पहला काफिला सुबह लगभग 3:35 बजे रवाना हुआ, जिसमें 3,450 श्रद्धालु शामिल थे। इसके बाद पहलगाम मार्ग से जाने वाले 5,346 श्रद्धालुओं का काफिला सुबह लगभग 4 बजे रवाना किया गया। दोनों मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों के जवान पूरी यात्रा के दौरान तैनात हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 2 जुलाई से प्रारंभ हुई थी और तब से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन के अनुसार अब तक जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 61,612 से अधिक श्रद्धालु कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं पवित्र अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक हिमलिंग के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1.73 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। यह संख्या यात्रा के प्रति देश और विदेश के श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को दर्शाती है।

यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पेयजल, विश्राम स्थल और आपातकालीन सहायता की विशेष व्यवस्था की गई है। चिकित्सा दल, एंबुलेंस और राहत टीमें भी पूरे मार्ग पर तैनात हैं। मौसम की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।

अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर वर्ष देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू-कश्मीर पहुंचते हैं।

इंजीनियर राजिंदर कुमार पर सरकार सख्त, विभागीय जांच शुरू

- 30 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता इंजीनियर राजिंदर कुमार के खिलाफ नियमित विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा दर्ज एक मामले के संबंध में की गई है। सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकारी आदेश के अनुसार इंजीनियर राजिंदर कुमार लोक निर्माण विभाग के निर्माण प्रभाग-चार तथा एसएसए और आरएमएसए परियोजनाओं के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के प्रभाग तीन और चार में कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत रहे थे। उनके कार्यकाल के दौरान हुए कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच अब विभागीय स्तर पर नियमित रूप से की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश में पीएमजीएसवाई सर्कल जम्मू के प्रभारी अधीक्षण अभियंता इंजीनियर अभिषेक गुप्ता को इस मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी के आर एंड बी प्रभाग बख्शी नगर के प्रभारी कार्यकारी अभियंता इंजीनियर संदीप गुप्ता को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच अधिकारी उपलब्ध अभिलेखों, दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर मामले की विस्तृत जांच करेंगे और विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

यह विभागीय जांच जम्मू के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो में दर्ज एफआईआर संख्या 05/2020 से जुड़े आरोपों के आधार पर शुरू की गई है। एफआईआर में लगाए गए आरोपों की सत्यता, संबंधित अधिकारियों की भूमिका तथा सरकारी नियमों के पालन की स्थिति की जांच की जाएगी।

न्यूज ब्रीफ

428 ग्राम अफीम सहित एक आरोपी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर की पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा, थाना इंदौरा की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 428 ग्राम अफीम बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) धर्म चंद वर्मा ने बताया कि पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा की टीम नियमित गश्त व मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए मलकाना चौक पर तैनात थी। इसी दौरान पुलिस को विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली कि सुमित ठाकुर, निवासी गांव मलकाना, अफीम की खरीद-फरोख्त कर रहा है और उसकी मोटरसाइकिल में अफीम छिपाकर रखी गई है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत गांव मंड घंडरां स्थित वाटर सप्लाई परिसर में दबिश दी। दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में मोटरसाइकिल की नियमानुसार तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के फ्यूल बॉक्स में छिपाकर रखी गई 428 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसे मौके पर कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। इस संबंध में थाना इंदौरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित ठाकुर (31 वर्ष), पुत्र नरेंद्र सिंह, निवासी गांव मलकाना, डाकघर पराल, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद अफीम का स्रोत क्या था और आरोपी किसी नशा तस्करी गिरोह से जुड़ा है या नहीं। मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

चंगर अनुभाग के अंतर्गत क्षेत्रों में बिजली रहेगी बंद

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सहायक अभियंता बिजली उपमंडल-II ई. रविंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जुलाई को चंगर अनुभाग में बिजली की लाइनों की आवश्यक मरम्मत व पेड़ों की कांट-छांट करने के चलते कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि चंगर अनुभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कोहल्वीं, कुनाला, पुलिस लाईन, लखनपुर, बलोह, लोक निर्माण विश्रामगृह धौलरा, लेकव्यू कैफे, बस स्टैंड, धौलरा रोड, पुलिस चौकी तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक बिजली आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।

शिक्षकों का काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राज्य स्तरीय आह्वान पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन केंद्रीय इकाई के निर्देशानुसार बिलासपुर कॉलेज के शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध के माध्यम से शिक्षकों ने सरकार का ध्यान अपनी वर्षों से लंबित समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। प्रमुख मांगों में करियर एडवांसमेंट स्कीम का समय पर क्रियान्वयन, महंगाई भत्ते की लंबित किश्तों का भुगतान, विभागीय पदोन्नतियां (तथा बकाया एरियर का शीघ्र निपटारा शामिल है। शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय से इन मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से प्रभावित न हो। इस दौरान एचजीसीटीए इकाई बिलासपुर के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत चंदेल, उपाध्यक्ष डॉ. दिनेश, सचिव डॉ. विजय, कोषाध्यक्ष डॉ. मोनिका सहित सभी सदस्यों ने कक्षाओं का संचालन जारी रखते हुए विरोध दर्ज कराया।

आईसीएमआर केंद्र का शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित

भारतेन्दु संवाददाता, लाहौल-स्पीति। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले के केलांग में 11 जुलाई को आयोजित होने वाले आईसीएमआर के उच्च हिमालयी चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण क्षेत्र में आवागमन प्रभावित होने तथा सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम की संशोधित तिथि की सूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। आयोजकों ने कार्यक्रम स्थगित होने से हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है।

क्लीन मंडी-ग्रीन मंडी में कन्या विद्यालय अव्वल

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। क्लीन मंडी-ग्रीन मंडी कार्यक्रम के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या व बाल मंडी ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानाचार्य अखिल कटोच ने बताया कि जिला भर में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने के आधार पर विद्यालय को यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने इस सफलता के लिए विद्यालय के समस्त स्टाफ, छात्र-छात्राओं को बधाई दी और कहा कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं हरित वातावरण बनाए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखा जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों और स्टाफ से भविष्य में भी इसी तरह सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

आरजीपीआरएस ने किया 'संविधान बचाओ सत्याग्रह'

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन (आरजीपीआरएस) द्वारा सेरी मंच पर 'संविधान बचाओ सत्याग्रह' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के विभिन्न अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर आरजीपीआरएस के राज्य अध्यक्ष सचिन मिरुपा, राज्य सह-अध्यक्ष अरुण प्रकाश आर्य और जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए जनजागरण अभियान को और तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्याग्रह को अब ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा, ताकि अधिक लोगों को अभियान से जोड़ा जा सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

जेएनवी कोठीपुरा में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा के प्राचार्य राकेश कुमार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छठी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। जिला बिलासपुर के स्थायी निवासी विद्यार्थी, जो वर्तमान में कक्षा पांचवीं में राजकीय, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, सर्व शिक्षा अभियान केंद्र या एनआईओएस में अध्ययनरत हैं, प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी का जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार होंगे। इच्छुक विद्यार्थी 31 जुलाई 2026 तक नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा 28 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। अधिक जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर 01978-280342 और 9418114501 पर संपर्क किया जा सकता है।

अवैध मत्स्य आखेट पर कार्रवाई, 220 मामले दर्ज और 2.28 लाख रुपए जुर्माना वसूला

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश के जलाशयों और सामान्य जल स्रोतों में मत्स्य संपदा संरक्षण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 16 जून से 9 जुलाई 2026 तक अवैध मत्स्य आखेट के 220 मामले दर्ज किए गए हैं। निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य विवेक चंदेल ने बताया कि इन मामलों में 2.28 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के पांच प्रमुख जलाशयों गोविंद सागर, पौंग डैम, चमेरा डैम, कोल डैम और रणजीत सागर में करीब 43,785 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 5,900 मछुआरे आजीविका से जुड़े हैं। इसके अलावा करीब 2,400 किलोमीटर लंबी नदियों और जलधाराओं में भी 6,000 से अधिक मछुआरे मत्स्य आखेट करते हैं। विवेक चंदेल ने बताया कि मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध अवधि में विभाग ने विशेष कैंप, उड़नदस्ते और नियमित गश्त की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर, पौंग, कोल डैम, चमेरा और रणजीत सागर सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई कर जुर्माने वसूले गए हैं। उन्होंने लोगों से प्रतिबंधित अवधि में अवैध मत्स्य आखेट न करने और मत्स्य संसाधनों के संरक्षण में सहयोग देने की अपील की।

'वंदे मातरम्' ने देशभक्ति को राष्ट्रीय कर्तव्य बनाया : उपराष्ट्रपति

सरदार पटेल ने देश के दिलों को भी जोड़ा, मजबूत भारत की नींव रखी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम ने मातृभूमि के प्रति प्रेम

को पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य में बदल दिया और इसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असंख्य सेनानियों को साहस, त्याग और आशा से प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने केवल रियासतों का ही नहीं, बल्कि देशवासियों के दिलों का भी एकीकरण किया और एक राष्ट्र, एक संविधान तथा साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।

उपराष्ट्रपति शुक्रवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी (आईआईएएस), शिमला द्वारा आयोजित 'वंदे मातरम् की यात्रा' पर स्थायी प्रदर्शनी के उद्घाटन तथा 'सरदार पटेल का विजन : एकीकरण, एकजुटता और संघवाद' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को आभासी माध्यम से संबोधित कर रहे थे। 'वंदे मातरम' केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्र चेतना का प्रतीक है। इसने देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। उन्होंने कहा कि आज भी यह गीत राष्ट्र के प्रति समर्पण, आत्मगौरव व राष्ट्रीय एकता का प्रेरक स्रोत बना हुआ है। वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने देशी रियासतों का सफलतापूर्वक विलय कर आधुनिक भारत के राजनीतिक व प्रशासनिक एकीकरण को साकार किया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक मजबूत व संगठित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईमानदारी, उत्कृष्ट कार्य संस्कृति, राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण के रूप में प्रतिदिन हमारे आचरण में दिखाई देनी चाहिए।

आईआईएएस शिमला में 'वंदे मातरम् की यात्रा' प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन

उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे वंदे मातरम् के शाश्वत संदेश और सरदार पटेल के राष्ट्रनिर्माण के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए एक एकजुट, आत्मविश्वासी और समावेशी भारत के निर्माण के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करें। इस अवसर पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा वंदे मातरम् की यात्रा विषयक स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया तथा सरदार पटेल की राष्ट्र एकता, एकीकरण और भारतीय संघीय व्यवस्था संबंधी दृष्टि पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ भी हुआ।

सरदार पटेल की एकता और संघवाद की सोच देश की शक्ति : राज्यपाल कविंद्र गुप्ता

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल केवल भारत के राजनीतिक एकीकरण के शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि भारतीय संघीय व्यवस्था के भी मजबूत समर्थक थे।

उन्होंने कहा कि भारत का संघीय ढांचा दुनिया में अनोखा है, जहां अलग-अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं संविधान के माध्यम से एक सूत्र में बंधी हुई हैं जो देश की एकता की मजबूत नींव है। राज्यपाल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 'सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, एकात्मता और संघवाद की परिकल्पना' तथा 'वंदे मातरम् की यात्रा- एक प्रदर्शनी' के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। भारत के उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वे नहीं आ सके। इस अवसर पर उप-राष्ट्रपति ने वीडियो के माध्यम से अपना संदेश दिया।

राज्यपाल ने कहा कि ये दोनों कार्यक्रम भारत की राष्ट्रीय चेतना के दो महत्वपूर्ण स्तंभों को समर्पित हैं। वंदे मातरम् की यात्रा- एक प्रदर्शनी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों में जागृत हुई राष्ट्रभक्ति की भावना को दर्शाती है, जबकि यह संगोष्ठी सरदार पटेल के उस दूरदर्शी नेतृत्व को याद करती है, जिसने देश को एकजुट कर मजबूत भारत की नींव रखी।

उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा रहा है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस अमर गीत ने स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रसेवा की भावना का संचार किया। यह प्रदर्शनी केवल पुराने दस्तावेजों और तस्वीरों का संग्रह नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय जागरण की जीवंत गाथा है, जो विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करेगी। राज्यपाल ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका योगदान केवल 560 से अधिक रियासतों के विलय तक सीमित नहीं था। बारडोली सत्याग्रह में उनके नेतृत्व, संगठन क्षमता, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए कहा कि इन्हीं गुणों के कारण उन्हें 'सरदार' की उपाधि मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात के केवड़िया में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के निर्माण की पहल की भी सराहना की।

प्रदेश में आपदा के दौरान मिलेगी किसी भी नेटवर्क से फोन करने की सुविधा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दौरान आम लोगों को फोन करने या अपने परिजनों की खैर खबर लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

वे फोन में नेटवर्क नहीं मिलने पर किसी भी दूरसंचार नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए दूरसंचार विभाग द्वारा उन्हें इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। आपदा के दौरान से जान-माल की भारी क्षति होने की आशंका रहती है। किसी आपदा के समय दूरसंचार सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता की आवश्यकता होती है, यह बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, दूरसंचार विभाग (हिमाचल प्रदेश एलएसए) ने जानकारी दी है कि आपदा के दौरान टेलीकॉम नेटवर्क में व्यवधान की स्थिति में इंट्रा सर्कल रोमिंग (आईसीआर) को सक्रिय किया जा सकता है। आपदा के दौरान, मोबाइल उपयोगकर्ता डिवाइस सेटिंग्स से मैन्युअल रूप से नेटवर्क का चयन कर सकते हैं और उपलब्ध नेटवर्क से किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के मोबाइल नेटवर्क का चयन कर सकते हैं। इस तरह से उपयोगकर्ता अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क से जुड़ेंगे जिसका कवरेज उपलब्ध है और मोबाइल कनेक्टिविटी प्राप्त करेंगे। इस सुविधा का एक फायदा यह है कि एक मोबाइल उपयोगकर्ता प्रभावित क्षेत्रों में अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क से कॉल कर सकते हैं । वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में हुई अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा के कारण दूरसंचार सेवाओं में उत्पन्न व्यवधान को देखते हुए, दूरसंचार विभाग द्वारा चंबा, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति जिलों तथा मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में इंट्रा-सर्किल रोमिंग (आईसीआर) सुविधा सक्रिय की गई थी, जब भी इंट्रा-सर्किल रोमिंग (आईसीआर) सुविधा सक्रिय की जाती है, दूरसंचार विभाग द्वारा इससे संबंधित सूचना जारी की जाती है, जिसमें नागरिकों को उन प्रभावित क्षेत्रों एवं आईसीआर व्यवस्था की प्रभावी अवधि की जानकारी दी जाती है, जहां यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

'एफआईआर सरकार' बन गई है कांग्रेस सरकार : राणा

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है।

हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है और प्रदेश की जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री सड़कों, पेयजल योजनाओं और आधुनिक निर्माण कार्यों के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज प्रदेश को 'एफआईआर वाले मुख्यमंत्री' मिल गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान सरकार और एफआईआर एक-दूसरे के पर्याय बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के हर फैसले में अब सिर्फ मामले दर्ज करने की राजनीति दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने संजौली में स्कूल संचालिका की हत्या, सरकाघाट में कॉलेज छात्रा की हत्या, ऊना में गोलीकांड, बिलासपुर में पुलिस मौजूदगी में हमला और कुल्लू में महिला से हुई दरिंदगी जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर में भी महिलाओं से जुड़े गंभीर मामले सामने आए हैं। उन्होंने विमल नेगी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि परिजनों को न्याय के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई।

उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों कर रही थी। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार का तीन साल का कार्यकाल अपराध, हिंसा और कानून व्यवस्था की विफलताओं से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 'व्यवस्था परिवर्तन' के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में व्यवस्था के बजाय अव्यवस्था बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी और स्टार्टअप हब बनाने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश में अपराध और एफआईआर की स्थिति बढ़ गई है। उन्होंने मांग की कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की जाए और गृह विभाग संभाल रहे मुख्यमंत्री सुक्खू नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। भाजपा जल्द ही प्रदेश की कानून व्यवस्था, झूठे मुकदमों और जनता की समस्याओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करवाएगी। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से निष्पक्ष होकर कार्य करने की अपील की और कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, इसलिए अधिकारियों को कानून के अनुसार काम करना चाहिए।

कांगड़ा में फोरलेन पर सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। कांगड़ा में दौलतपुर के समीप फोरलेन पर शुक्रवार सुबह हुए एक दर्दनाक सडक हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब बाइक के सामने अचानक एक पशु आ गया। पशु को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अभिषेक कुमार निवासी रजियाणा बांध के रूप में हुई है। युवक कांगड़ा स्थित आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत था। एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की है। युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा।

कॉलेजों से कोर्स हटाने के फैसले का एबीवीपी ने किया विरोध

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने लंबाथाच महाविद्यालय से बीएससी तथा डेहर और निहरी महाविद्यालयों से बीकॉम कोर्स हटाने के निर्णय का विरोध किया है। एबीवीपी के विभाग संयोजक मंजुल शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लगातार छात्र हितों के खिलाफ फैसले ले रही है। सरकार ने इन कोर्सों को हटाने के लिए नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार आधारभूत ढांचे और प्राध्यापकों की कमी का हवाला दिया है। एबीवीपी ने सवाल उठाया कि महाविद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना किसकी जिम्मेदारी है। मंजुल शर्मा ने कहा कि इन महाविद्यालयों में 70 से 80 प्रतिशत छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। कोर्स बंद होने से कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनके लिए अन्य संस्थानों में जाना संभव नहीं होगा। उन्होंने सरकार से कोर्स हटाने संबंधी अधिसूचना वापस लेने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय वापस नहीं लिया गया तो एबीवीपी प्रदेशभर में आंदोलन करेगी।

बिलासपुर पुलिस ने 28 घंटे के भीतर बंजार से पकड़े मुख्य आरोपी, अब तक 5 गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पंजाब के युवक सन्नी गिल पर हुए कातिलाना हमले के मामले में बिलासपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए वारदात के महज 28 घंटे के भीतर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र के जंगलों से तीन मुख्य आरोपियों को दबोचा, जबकि इस मामले में अब तक कुल पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने प्रेस वार्ता में बताया कि जांच के अनुसार सन्नी गिल पर मुख्य रूप से सौरभ परियाल उर्फ फांदी निवासी नसवाल (घुमारवीं) और कुलभूषण उर्फ लक्की निवासी लेहड़ (सदर बिलासपुर) ने हमला किया था। बंजार से पकड़े गए आरोपियों को बिलासपुर लाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ के बाद मामले के अन्य पहलुओं का खुलासा होने की संभावना है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए सुनियोजित तरीके से करीब आठ वाहन बदले। उन्होंने मुख्य मार्गों के बजाय ग्रामीण और संपर्क सड़कों का इस्तेमाल किया तथा मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर दिए, ताकि पुलिस उनकी लोकेशन ट्रैक न कर सके।

एसपी ने बताया कि आरोपी सूर्या चंदेल शूटरों के साथ बरठीं के जंगलों में छिपा था, जहां उसे भोजन और अन्य सहायता उपलब्ध कराने के आरोप में व्यापार मंडल बरठीं के प्रधान अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले धीरज धीमान को भी हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस की तकनीकी और खुफिया टीमों ने सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का पीछा किया और बंजार के जंगलों में घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया। उधर, घायल सन्नी गिल की मेडिकल रिपोर्ट में बाईं टांग पर घातक हथियार से गंभीर चोट की पुष्टि हुई है। पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी ताकि हमले के पीछे की साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाया जा सके।

बच्चे लक्ष्य निर्धारित कर करें कठिन परिश्रम : डीसी

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें तथा उसे हासिल करने के लिए पूरी लगन, अनुशासन और निरंतर कठिन परिश्रम करें। उन्होंने कहा कि आज का समर्पित प्रयास ही कल के उज्ज्वल भविष्य की नींव बनता है।

डीसी अपने कार्यालय में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंडी द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बगला की जमा एक एवं जमा दो की छात्राओं के एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के दौरान उनसे संवाद कर रहे थे। उन्होंने छात्राओं से कहा कि यदि वे अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं, तो आज से ही पूरी निष्ठा के साथ मेहनत शुरू करें। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतिदिन 10 से 12 घंटे नियमित एवं योजनाबद्ध अध्ययन करने, समय का सदुपयोग करने तथा लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प ही सफलता की वास्तविक कुंजी हैं। डीसी ने छात्राओं से उनकी पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं तथा कैरियर संबंधी आकांक्षाओं पर भी चर्चा की और उन्हें अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित कर पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर और अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर छात्राओं ने डीसी से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने सरल एवं प्रेरणादायक ढंग से उत्तर दिया। छात्राओं ने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस एक्सपोजर विजिट को अत्यंत उपयोगी बताते हुए इसके लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने भारतीय स्टेट बैंक की गांधी चौक शाखा का भ्रमण किया। इस अवसर पर बैंक अधिकारियों ने उन्हें वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल बैंकिंग, आर्थिक सशक्तिकरण, बचत के महत्व तथा डिजिटल लेन-देन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही डिजिटल धोखाधड़ी (साइबर फ्रॉड) से बचाव के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया। इसके उपरांत छात्राओं ने महिला पुलिस थाना, भ्यूली का भ्रमण किया। यहां पुलिस अधिकारियों ने उन्हें महिला सुरक्षा, महिलाओं के कानूनी अधिकार, साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा, हेल्पलाइन सेवाओं तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। छात्राओं को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न सरकारी प्रावधानों एवं कानूनों से भी अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) अजय बद्रेल तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी जितेंद्र कुमार सैनी सहित स्कूल के अध्यापक गण भी उपस्थित रहे।

लाभ धर्माणी ने कहा- 1.32 करोड़ से बदलेगी औहर स्कूल की तस्वीर, भवन नवीनीकरण का कार्य शुरू

अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई से संबद्ध होगा औहर स्कूल

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर को अगले शैक्षणिक सत्र से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध किया जाएगा।

इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। औहर स्कूल में आयोजित विद्यार्थियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्माणी ने कहा कि यह विद्यालय क्षेत्र का एक ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। उन्होंने बताया कि पहले इसी परिसर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) का प्रशिक्षण केंद्र संचालित होता था, जहां जेबीटी और बीएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्होंने बताया कि विद्यालय भवन काफी पुराना और जर्जर हो चुका है। इसके जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के लिए प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 32 लाख स्वीकृत किए हैं। इस राशि से भवन की छत, सीलिंग, फ्लोरिंग, खिड़कियां, दरवाजे, बिजली व्यवस्था, बरामदे और कक्षों का व्यापक नवीनीकरण किया जा रहा है। साथ ही छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आधुनिक शौचालय भी बनाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए स्कूल के खेल मैदान के चैनलाइजेशन, रखरखाव और बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों जैसी आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

बाल आश्रम घुमारवीं के निर्माण कार्यों के लिए सरकार ने जारी किए 2 करोड़

नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने घुमारवीं में बाल आश्रम के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के नाम तहसील घुमारवीं के मौजा पलसोटी में दो बीघा भूमि भी हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि संस्थान का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू की बजट घोषणा के अनुरूप यह परियोजना बच्चों की देखभाल, संरक्षण व पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि बाल आश्रम का निर्माण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में जरूरतमंद बच्चों को सुरक्षित आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, परामर्श, पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा बेहतर जीवन-यापन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 50 बच्चों की क्षमता वाले इस बाल आश्रम में दो डॉरमिटरी, दो कक्षाएं, प्राथमिक उपचार कक्ष, रसोईघर, भोजन कक्ष, भंडार कक्ष, मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय, पर्याप्त स्नानघर एवं शौचालय, कार्यालय, परामर्श एवं मार्गदर्शन कक्ष, कार्यशाला, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के लिए पृथक कक्ष तथा खेल मैदान जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। संबंधित विभागों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) जल्द तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, ताकि निर्माण कार्य बिना विलंब शुरू हो सके। उन्होंने इस परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाल आश्रम बनने से जिला बिलासपुर में बाल संरक्षण सेवाओं को मजबूती मिलेगी और जरूरतमंद बच्चों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध होगा।

आंगनबाड़ी वर्कर्स-हेल्पर्स यूनियन ने मनाया काला दिवस, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटू ने काला दिवस मनाते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री को जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) मंडी के माध्यम से मांग पत्र भेजा। यूनियन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पूर्व में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। यूनियन ने मांग की कि वर्ष 2018 से लंबित मानदेय वृद्धि लागू की जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए तथा फेस रिकग्निशन सिस्टम की अनिवार्यता समाप्त की जाए। साथ ही ऑनलाइन कार्यों के नाम पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने की मांग भी उठाई गई। यूनियन ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किया जाए व पोषण आहार की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों की अनदेखी की गई है। यूनियन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेड-3 और सहायिकाओं को ग्रेड-4 सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित करने की मांग की। नियमितीकरण तक न्यूनतम वेतन और पेंशन लागू करने, श्रम संहिताएं वापस लेने, एफआरएस और ई-केवाईसी की अनिवार्यता समाप्त करने तथा गैर-आईसीडीएस कार्यों से मुक्त रखने की मांग भी रखी गई। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस अवसर पर यूनियन जिला सचिव सुदर्शन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

लेरिशा मुंसाम का खूबसूरत अंदाज

नई दिल्ली। लेरिशा मुंसामी दक्षिण अफ्रीका की एक फिटनेस मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। वे केशव महाराज की पत्नी है। अपनी आकर्षक फिटनेस, फैशन और लाइफस्टाइल पोस्ट के कारण उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान बनाई है। वह स्वास्थ्यइ सकारात्मक जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए भी जानी जाती हैं।

फीफा विश्व कप | लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस

फ्रांस ने मोरक्को को 2–0 से हराया

एजेंसी, फॉक्सबोरो (अमेरिका)

गत उपविजेता फ्रांस ने फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में गुरुवार को मोरक्को को 2–0 से हराकर लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब फ्रांस का सामना अंतिम चार में स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होगा।

मैच की शुरुआत से ही फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया। चौथे मिनट में कप्तान किलियन एमबाप्पे गोल करने से मामूली अंतर से चूक गए। पहले हाफ में फ्रांस का दबदबा इतना रहा कि मोरक्को इंजरी टाइम तक गोल पर एक भी प्रभावी शॉट नहीं लगा सका। फ्रांस को 25वें मिनट में पेनाल्टी मिली, लेकिन लंबी वीडियो समीक्षा के बाद एमबाप्पे का कमजोर शॉट मोरक्को के गोलकीपर यासीन बोनू ने शानदार तरीके से बचा लिया। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ और स्कोर 0–0 रहा।

दूसरे हाफ में फ्रांस ने दबाव बढ़ाया और 60वें मिनट में एमबाप्पे ने शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। यह इस विश्व कप में उनका आठवां गोल और विश्व कप नॉकआउट मुकाबलों में 12वां गोल रहा। इसके साथ ही उन्होंने विश्व कप इतिहास में अपने कुल गोलों की संख्या 20 तक पहुंचा दी। फ्रांस ने बढ़त के छह मिनट बाद ही दूसरा गोल दाग दिया। एमबाप्पे के बेहतरीन पास पर उस्मान डेम्बेले ने मोरक्को की रक्षा पंक्ति को भेदते हुए गेंद को गोल में पहुंचाकर स्कोर 2–0 कर दिया। मैच के 77वें मिनट में एमबाप्पे हल्की चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए और बेंच पर उनके टखने पर बर्फ लगाई गई। मोरक्को ने अंतिम मिनटों में वापसी की कोशिश की और कई अवसर भी बनाए, लेकिन फ्रांस की मजबूत रक्षापंक्ति के सामने वह गोल करने में सफल नहीं हो सका। 2022 विश्व कप के सेमीफाइनल की तरह इस बार भी फ्रांस ने मोरक्को को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं, मोरक्को का शानदार सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। (अनंत ज्ञान)

गोल्डन बूट की दौड़ में एमबाप्पे सबसे आगे, मेसी दूसरे स्थान पर

एजेंसी, नई दिल्ली

फीफा विश्व कप अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश भी कर लिया है। इसी के साथ टूर्नामेंट के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाले गोल्डन बूट की दौड़ भी रोमांचक होती जा रही है।

फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी भी 8 गोल कर चुके हैं, लेकिन उनके नाम केवल एक असिस्ट होने के कारण वे दूसरे स्थान पर हैं। नॉर्वे के एरलिंग हालैंड 7 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

इंग्लैंड के हैरी केन 6 गोल और एक असिस्ट के साथ चौथे स्थान पर हैं, जबकि फ्रांस के उस्मान डेम्बेले 5 गोल और 2 असिस्ट के साथ पांचवें स्थान पर काबिज हैं। इसके अलावा सेनेगल के इस्माइला सार, स्पेन के मिकेल ओयारजाबाल, मेक्सिको के जूलियन क्विनोनेस, इंग्लैंड के जूड बेलिंघम और ब्राज़ील के विनीसियस जूनियर ने 4–4 गोल किए हैं। इन सभी खिलाड़ियों के नाम 1–1 असिस्ट भी दर्ज है, जिससे क्वार्टर फाइनल के बाद गोल्डन बूट की यह जंग और भी दिलचस्प हो गई है।

फीफा के नियमों के अनुसार यदि दो या उससे अधिक खिलाड़ी समान संख्या में गोल करते हैं, तो पहले असिस्ट की संख्या और उसके बाद मैदान पर खेले गए कम मिनट के आधार पर विजेता का फैसला किया जाएगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के साथ गोल्डन बूट की यह जंग और भी रोमांचक हो गई है।

स्पोर्ट्स विंडो

एशियाई अंडर–23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप

भारत ने पहले दिन जीते एक स्वर्ण एक रजत और तीन कांस्य पदक

एजेंसीख ओरडोस (चीन)। एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले ही दिन एक स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य सहित कुल पांच पदक अपने नाम किए। भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने जीता। आस्तिक प्रधान, सैंड्रा मोल साबू, सेतु मिश्रा और श्रावणी सचिन सांगले की भारतीय चौकड़ी ने 3:18.64 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह दिन का भारत के लिए आखिरी इवेंट था। भारत का पहला पदक भरतप्रीत सिंह ने दिलाया, जिन्होंने पुरुष डिस्कस थ्रो में 52.91 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। चीन के ली झिक्सिन ने 60.79 मीटर के साथ स्वर्ण और उनके ही देश के जियांग जेहाओ ने 59.60 मीटर के साथ रजत पदक जीता। पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में भारत ने दो पदक हासिल किए। शिवाजी परशुराम मदप्पागौड़ा ने 14:08.19 मिनट के समय के साथ रजत पदक जीता, जबकि विनोद सिंह ने 14:23.67 मिनट में दौड़ पूरी कर कांस्य पदक अपने नाम किया। जापान के रुई सुजुकी ने 14:01.24 मिनट के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। दिन का पांचवां पदक प्राची देवकर ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में जीता। उन्होंने 10:32.69 मिनट का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा में चीन की यांग यीतिंग ने 10:14.68 मिनट के साथ स्वर्ण और लियू युक्सिन ने 10:25.51 मिनट के साथ रजत पदक जीता।

एएम ग्रीन आईजीपीएल के स्टार गिल ने एशियन डेवलपमेंट टूर में शीर्ष -20 में बनाई जगह

एजेंसी, ताइपे। भारत के पुखराज सिंह गिल ने एशियन डेवलपमेंट टूर के 'एवर ग्लोरी एडीटी ओपन' में लगातार तीन राउंड में 3-अंडर 69 का स्कोर किया और संयुक्त रूप से 19वें स्थान पर रहे। लुधियाना के इस स्टार खिलाड़ी ने, जिन्होंने 2025 में भारत में 'एएम ग्रीन आईजीपीएल ऑर्डर ऑफ़ मेरिट' जीता था, एशियन डेवलपमेंट टूर के ज़रिए एशियन टूर में जगह बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। 69-69-69 के स्कोर के साथ उनका कुल स्कोर 9-अंडर 204 रहा और वे संयुक्त रूप से 19वें स्थान पर रहे। एएम ग्रीन आईजीपीएल में 'होनर होम्स गुरुग्राम' के लिए खेलने वाले गिल अब मेरिट लिस्ट में छठे स्थान पर हैं और उनके 2027 एशियन टूर में जगह बनाने की अच्छी संभावना है, क्योंकि टॉप-10 खिलाड़ी ही ऊंचे स्तर के टूर में आगे बढ़ते हैं। पिछले साल एएम ग्रीन आईजीपीएल में गिल के साथी करणदीप कोचर ने भी यही रास्ता अपनाया था।

23 जुलाई से दो अगस्त चलने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 का कार्यक्रम

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उतरेंगे 124 भारतीय एथलीट

एजेंसी, ग्लासगो। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से दो अगस्त तक होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल 124 भारतीय एथलीट आठ 'एबल-बॉडी' (सामान्य शारीरिक क्षमता वाले) और पांच पैरा-स्पोर्ट्स स्पर्धाओं में पदक के लिए मुकाबला करेंगे। ये मुकाबले स्कॉटलैंड के चार अलग-अलग जगहों पर आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के 'एबल-बॉडी' एथलीट एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, जूडो, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइक्लिंग, लॉन बॉल्स और तैराकी में हिस्सा लेंगे।

एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान, सलीमा टेटे को सौंपी कमान

एजेंसी, नई दिल्ली

हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को जापान में 19 सितंबर से 4 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले 20वें एशियन गेम्स आइची–नागोया 2026 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी। हाल ही में न्यूजीलैंड में एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीतने वाली टीम की कप्तान सलीमा टेटे एक बार फिर टीम की कमान संभालेंगी। टीम के मुख्य कोच सजॉर्ड मारिजन ने कहा कि हमारे पास ऐसी टीम है जिसमें जूनियर, अनुभवी और वरिष्ठ खिलाड़ियों का शानदार संतुलन है। सभी खिलाड़ी एक–दूसरे से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं।

हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सविता और बिचू देवी खारीबाम को टीम में गोलकीपर के रूप में शामिल किया गया है। रक्षा पंक्ति में सुशीला चानू, इशिका चौधरी, ज्योति, ललथांतलुआंगी और शिल्पी डाबस को जगह मिली है। ललथांतलुआंगी और शिल्पी डाबस ने एफआईएच नेशंस कप में अपना सीनियर डेब्यू किया था और शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें एशियन गेम्स टीम में भी शामिल किया गया है। मिडफील्ड में कप्तान सलीमा टेटे के साथ निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग खेलती नजर आएंगी। फॉरवर्ड लाइन में लालरेमसियामी, रुतुजा दादासो पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग को शामिल किया गया है। मुख्य कोच ने आगे कहा, 'इस टीम के खिलाड़ियों ने पिछले कुछ महीनों में शानदार फॉर्म और फिटनेस दिखाई है। हमें पूरा विश्वास है कि यह टीम एशियन गेम्स की चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है।'

वेस्टइंडीज ने चोटिल हेनरी की जगह ग्रिमंड को किया टीम में शामिल

एजेंसी, ब्रैंडी। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ होने वाले तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए चोटिल चिनेल हेनरी की जगह 21 साल की बल्लेबाज रियालियाना ग्रिमंड को टीम में जगह दी है। हाल ही में संपन्न हुए महिला टी–20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वेस्ट इंडीज की टीम में यह एकमात्र बदलाव है। उस टूर्नामेंट में उप–कप्तान रहीं हेनरी ने 131.42 के स्ट्राइक रेट से 92 रन बनाए, जो वेस्टइंडीज की सभी बल्लेबाजो में सबसे अच्छा था – और 8.87 की इकॉनमी रेट से तीन विकेट लिए। ग्रिमंड ने पांच एकदिवसीय मैच खेले हैं, जिनमें अप्रैल की शुरुआत में बासेटेरे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्टइंडीज का इस फॉर्मेट में सबसे हालिया मैच भी शामिल है।

टी–20 हार पर बीसीसीआई सख्त गंभीर और अय्यर की होगी समीक्षा

एजेंसी, मुंबई

मुंबई इंग्लैंड के खिलाफ टी–20 सीरीज हारने के बाद बीसीसीआई भारतीय टीम के परफॉर्मेंस का रीव्यू करने जा रहा है। हेड कोच गौतम गंभीर का रोल और टीम की रणनीति भी रिव्यू का हिस्सा होगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी भी समीक्षा के दायरे में आएगी। यह दावा एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से किया है।

रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार खराब प्रदर्शन के बाद बोर्ड यह समझना चाहता है कि रणनीति और टीम चयन के स्तर पर कहां कमी रही। फिलहाल गंभीर और अय्यर पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उनके कामकाज की समीक्षा तय मानी जा रही है। गंभीर का एग्रीमेंट 2027 तक है। अय्यर हाल ही में कप्तान बनाए गए हैं। भारतीय टीम को आयरलैंड दौरे में 0–2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। जबकि, टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी–20 सीरीज में 0–3 से पिछड़ रही है। एक मैच नो रिजल्ट रहा था। एक दिन पहले टीम सीरीज के चौथे मैच में 9 विकेट से हार गई थी। 2014 के बाद पहली बार

इंग्लैंड ने भारत को टी–20 सीरीज में हरा दिया। दोनों टीमों के बीच अब तक 10 सीरीज खेली गईं, जिनमें भारत ने 5 और इंग्लैंड ने 4 जीतीं। एक सीरीज ड्रॉ रही थी। बीसीसीआई ने हाल ही में टी–20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी थी। हालांकि, यह फैसला अब तक टीम के पक्ष में नहीं गया है।

भारत लगातार दूसरी टी–20 सीरीज हार चुका है। इंग्लैंड दौरे से पहले टीम को आयरलैंड के खिलाफ 2–0 से सीरीज गंवानी पड़ी थी, जो भारत की आयरलैंड के खिलाफ पहली टी–20 सीरीज हार थी।

धीमी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका का विरोध करने पर राज्यों को फटकारा

एजेंसी, नई दिल्ली। आपराधिक मामलों की सुनवाई में हो रही अत्यधिक देरी और इसके बावजूद आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और महाराष्ट्र सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य सरकारें समय पर मुकदमों का निपटारा सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं तो केवल जमानत का विरोध करना उचित नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्याय व्यवस्था में देरी से किसी आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं हो सकता।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के रवैये पर नाराजगी जताई। मामला वर्ष 2022 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार विदेशी नागरिक केल्विन चिन्दोजी ओकोरो से जुड़ा है। आरोपी पिछले चार वर्षों से अधिक समय से हिरासत में है, जबकि मामले में दाखिल आरोप पत्र में 45 गवाहों का उल्लेख किया गया था। अदालत को बताया गया कि अब तक केवल दो गवाहों से ही पूछताछ पूरी हो सकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मुकदमे की सुनवाई इतनी धीमी गति से चल रही है तो आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखना गंभीर चिंता का विषय है। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि अभियोजन प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हो रही है और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है।

सौर पैनल लगाने के कार्यक्रम को वित्तीय मदद देगा विश्व बैंक

एजेंसी, नई दिल्ली। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर कार्यक्रम को गति देने के लिए वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है। वित्त बैंक ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस पहल का उद्देश्य लाखों घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना है। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े विनिर्माण, स्थापना और सेवा क्षेत्र में लगभग 17 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। स कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण पैकेज में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निमाण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से 82 करोड़ डॉलर का ऋण, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से छह करोड़ डॉलर का रियायती ऋण और आईबीआरडी के लिवेबल प्लैनेट फंड से एक करोड़ डॉलर का अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक 4.2 अरब डॉलर का निजी निवेश भी जुटायेगा, जो वाणिज्यिक ऋणों के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा ताकि लोग अपने घरों की छतों पर सौर पैनल लगा सकें।

रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में धमतरी में कांग्रेस का प्रदर्शन

ईडी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला

एजेंसी, धमतरी

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को धमतरी में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांधी मैदान के समीप एकत्रित हुए और केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला दहन कर गिरफ्तारी की कार्रवाई का विरोध जताया।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के माध्यम से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र में सभी संस्थाओं की

निष्पक्षता जरूरी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी में आक्रोश है और इसी के विरोध में प्रदेशभर में आवाज उठाई जा रही है।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि जांच एजेंसियां बिना किसी दबाव के निष्पक्ष तरीके से कार्य करें। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन सरकारी संस्थाओं का उपयोग किसी भी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए।

विरोध | एथनॉल मिश्रण नीति वापस लेने की मांग को लेकर सड़क पर उतरी युवा कांग्रेस

युवा कांग्रेस ने एथनॉल नीति को बताया बड़ा घोटाला

एजेंसी, नई दिल्ली

एथनॉल मिश्रण वाली ई–20 नीति को लेकर युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने इस नीति को लेकर सवाल उठाते हुए इसे आम जनता के हितों के खिलाफ बताया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन का आयोजन दिल्ली के रायसीना रोड स्थित भारतीय युवा कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के बाहर किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए।

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरुण पांडे ने बताया कि दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लकड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एथनॉल मिश्रण नीति को लेकर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार ने ई–20 नीति को लागू करते समय उपभोक्ताओं

को कई फायदे मिलने का दावा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर आम लोगों को इसका लाभ नहीं दिखाई दे रहा है।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लकड़ा ने आरोप लगाया कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देते समय सरकार ने दावा किया था कि इससे ईंधन की लागत कम होगी और उपभोक्ताओं को सस्ता पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में एथनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमत लगभग उतनी ही है जितनी पहले सामान्य पेट्रोल की थी। ऐसे में आम उपभोक्ताओं को इस नीति का वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि एथनॉल मिश्रण से पेट्रोल की लागत कम हुई है तो उसका फायदा सीधे जनता तक पहुंचना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उपभोक्ताओं की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए इस नीति को लागू किया है। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ई–20 पेट्रोल के उपयोग को लेकर वाहन मालिकों में भी कई तरह की आशंकाएं हैं।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लकड़ा ने दावा किया कि एथनॉल मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल से कई वाहनों के इंजन के रखरखाव का खर्च बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि करोड़ों वाहन मालिकों को भविष्य में अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि नीति लागू करने से पहले इसके प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाए और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखा जाए।

प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि किसी भी योजना का उद्देश्य आम लोगों को राहत पहुंचाना होना चाहिए।

एंडी बर्नहैम का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय

एजेंसी, लंदन

लेबर पार्टी के सांसदों से मिले ऐतिहासिक समर्थन के बाद ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर और नवनिर्वाचित सांसद एंडी बर्नहैम का ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी नेतृत्व के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही कुल 403 सांसदों में से 322 ने श्री बर्नहैम को अपना समर्थन दे दिया है। संसदीय नियमों के अनुसार, श्री बर्नहैम को केवल एक और सांसद के समर्थन की आवश्यकता है, जिसके बाद वह 323 के जादुई आंकड़े पर पहुंच जाएंगे। इस आंकड़े को छूते ही किसी भी अन्य प्रतिद्वंद्वी के लिए मैदान में उतरना गणितीय रूप से असंभव हो

जाएगा, क्योंकि उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम 81 सांसदों का समर्थन जुटाना किसी के लिए संभव नहीं रहेगा।

श्री बर्नहैम के सभी प्रमुख संभावित प्रतिद्वंद्वी पहले ही इस दौड़ से पीछे हट चुके हैं। यह राजनीतिक घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब लेबर पार्टी को मई में हुए स्थानीय चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे निवर्तमान प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर पर पद छोड़ने का भारी दबाव बन गया था। इसी बीच 'किंग ऑफ द नॉर्थ' के नाम से मशहूर श्री बर्नहैम ने जून में मेकरफील्ड उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज कर संसद में वापसी की। उनके सांसद बनते ही राजनीतिक समीकरण बदल गए और श्री स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी।

यदि 15 जुलाई को नामांकन की समय–सीमा समाप्त होने तक कोई अन्य उम्मीदवार सामने नहीं आता है, तो 17 जुलाई को एक विशेष सम्मलेन में श्री बर्नहैम को आधिकारिक तौर पर लेबर पार्टी का नया नेता घोषित कर दिया जाएगा।